

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1971/बैशाख 11, 1893

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1971/VAISAKHA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जनवरी, 1971 तक प्रकाशित किये गये।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 22nd January, 1971.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1.	S. O. 98, dated 1st January, 1971	Ministry of Finance	Exempting the goods so mentioned from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).
	का० आ० 98, दिनांक 1 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	उल्लिखित सामानों को भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से छूट।
2.	S. O. 99, dated 1st January, 1971	Ditto.	Recession of the Notifications No. 179/F. No. 80/120/66-LCI, dt. the 1st Oct. 1966 and No. 112/80/67-LCI, dt. the 10th Nov. 1967 of the Min. of Finance (Deptt. of Rev. and Insurance).

Issue No. and Date No.	Issued by	Subject
एस० ओ० 99, दिनांक 1 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 179/फा० सं० 80/120/66-एल० सी० 1, तारीख 1 अक्टूबर 1966 और अधिसूचना सं० 112/80/67 एल० सी० 1 तारीख 10 नवम्बर, 1967 का विखंडन ।
S. O. 100, dated 1st January, 1971	Ditto.	Exemption to certain goods so specified from the Payment of Customs duty.
एस० ओ० 100, दिनांक 1 जनवरी 1971	तदैव	उल्लिखित कतिपय मामलों को उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क से छूट ।
3. S.O. 101, dated 1st January 1971	Election Commission of India	Designating officers as Returning Officers, for the election to the [Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi.
एस० ओ० 101, दिनांक 1 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन निरूपण के लिए आफिसरों को रिटर्निंग आफिसर अभिग्रहित करना ।
S.O. 102, dated 1st January, 1971	Ditto.	Appointment of Assistant Returning Officers to assist the Returning Officers for the election to the Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi.
एस० ओ० 102, दिनांक 1 जनवरी 1971	तदैव	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग आफिसरों की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति ।
S.O. 103, dated 1st January, 1971	Ditto.	Appointing Shri J.O.G. Russell, Election Officer, Delhi as Assistant Returning Officer for all the Parliamentary Constituencies in Delhi, in addition to the officers appointed by Notification No. 434/DL/70 (1), dt. 30-12-70.

Issue No. and Date No.	Issued by	Subject
एस० ओ० 103, दिनांक 1 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	श्री जे० ओ० जी० रसल निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को, दिल्ली राज्य के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना सं० 434/दिल्ली/70(1), ता० 30-12-70 द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्ति ।
4. S.O. 103-A, dated 2nd January, 1971	Ministry of Foreign Trade	Taking over the Hira Mills Limited, Ujjain by the Authorized Controller for a further period upto and inclusive of the 3rd March, 1972.
का० आ० 103-क, दिनांक 2 जनवरी, 1971	विदेश व्यापार मंत्रालय	हीरा मिल्स लि० उज्जैन को प्राधि-कृत नियंत्रक, द्वारा और आगे 3 मार्च 1972 तक की अवधि के लिए ग्रहण ।
S.O. 104, dated 2nd January, 1971	Ditto	Authorizing the Madhya Pradesh State Textile Corporation Ltd. to take over the management of the whole of the New Bhopal Textiles Ltd., Bhopal vice Shri B. L. Gupta until further orders.
का० आ० 104, दिनांक 2 जनवरी, 1971	तदैव	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स, लिमिटेड भोपाल का सम्पूर्ण प्रबन्ध श्री० बी० एल० गुप्त के स्थान पर लेने के लिए आगामी आदेश जारी होने तक प्राधिकृत ।
S.O. 105, dated 2nd January, 1971	Ditto	Authorizing the Madhya Pradesh State Textile Corporation Ltd. to take over the management of the whole of the Swadeshi Cotton & Flour Mills Ltd., Indore vice Shri G. K. Seth.
का० आ० 105, दिनांक 2 जनवरी 1971	तदैव	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर का सम्पूर्ण प्रबन्ध श्री जी० के० सेठ के स्थान पर लेने के लिए प्राधिकृत ।

Issue No. and Date	Issued by	Subject
S. O. 106, dated 2nd January, 1971	Ministry of Foreign Trade	Cancellation of the Order of the Govt. of India in the late Ministry of Commerce & Industry No. S. O. 581, dated the 4th March, 1963.
का० आ० 106, दिनांक 2 जनवरी 1971	विदेश व्यापार मंत्रालय	भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 581 दिनांक 4 मार्च, 1963 को रद्द करना ।
5. S.O. 107, dated 4th January, 1971	Ministry of Information & Broadcasting.	Approval of the films so specified in the Schedule in all their language versions.
एस० ओ० 107, दिनांक 4 जनवरी 1971	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में वर्णित फिल्मों की सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित स्वीकृति ।
S.O. 108, dated 4th January, 1971	Ditto.	Approval of a film so specified in the Schedule in all its language versions.
एस० ओ० 108, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	अनुसूची में वर्णित एक फिल्म की सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित स्वीकृति ।
6. S.O. 109, dated 4th January, 1971.	Ministry of Home Affairs	The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Rules, 1971.
7. S.O. 110, dated 4th January, 1971	Ditto	Duty by every person in Rajasthan referred to in the said clause (a) as active duty for a period of six months w.e.f. 7-1-1971.
सा० नि० 110, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति के ड्यूटी जो 7 जनवरी, 1971 से छह मास के लिये राजस्थान में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।
S.O. 111, dated 4th January, 1971	Ditto.	Duty by every person in Delhi referred to in the said clause (a) as active duty for a period of six months w.e.f. 23-1-71.
सा० नि० 111, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23 जनवरी 1971 से 22 जुलाई 1971 तक छह मास के लिए दिल्ली में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

Issue No. and Date	Issued by	Subject
S.O. 112, dated 4th January, 1971	Ministry of Home Affairs	Duty of every person in Bihar referred to in clause (a) as active duty for a period of six months w.e.f. 17-1-1971.
सा० नि० 112, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17 जनवरी 1971 से 16 जुलाई 1971 तक छह मास के लिए बिहार में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
S.O. 113, dated 4th January, 1971	Ditto.	Duty by every person in Kerala referred to in clause (a) as active duty for a period of six months w.e.f. 25-1-1971.
सा० नि० 113, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25 जनवरी 1971 से 24 जुलाई 1971 तक छह मास के लिए केरल में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
S.O. 114, dated 4th January, 1971	Ditto.	Duty by every person in West Bengal referred to in clause (a) as active duty for a period of six months w.e.f. 8-1-1971.
सा० नि० 114, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8 जनवरी 1971 से 7 जुलाई 1971 तक छह मास के लिए पश्चिम बंगाल में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
S.O. 115, dated 4th January, 1971	Ditto.	Duty by every person in Haryana referred to in clause (a) as active duty for a period of six months w.e.f. 8-1-1971.
सा० नि० 115, दिनांक 4 जनवरी 1971	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8 जनवरी 1971 से 7 जुलाई 1971 तक छह मास के लिए हरयाणा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।
8. S.O. 116, dated 5th January, 1971	Ministry of Foreign Trade	Further amendment to the notification of the Late Ministry of Commerce No. S. O. 771 dated the 6th March, 1965.
एस० ओ० 116, दिनांक 5 जनवरी 1971	विदेश व्यापार मंत्रालय	भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० ग्रा० 771 तारीख 6 मार्च 1965 में संशोधन।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
9.	S. O. 209, dated 5th January, 1971	Ministry of Railways	Appointment of Shri M. Jaganmohan Rao, as a whole-time claims Commissioner.
	एस० ओ० 209, दिनांक 5 जनवरी 1971	रेल मंत्रालय	श्री एम० जगनमोहन राव को दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त ।
10.	S.O. 210/15/ID-RA/70, dated 6th January, 1971	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade	Appointment of Shri R.C. Nigam as a member to make investigation into the affairs of M/s. Seksaria Cotton Mills Ltd. Bombay (Maharashtra) vice Shri S. C. Bafna.
	का० आ० 210/15/आई० डी० आर० ए०/70 दिनांक 6 जनवरी 1971	औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय	श्री आर० सी० निगम को सेक्सरिया काटन मिल्स लि० बम्बई (महाराष्ट्र) के मामलों की जांच करने हेतु नियुक्त ।
11.	S.O. 211, dated 7th January, 1971	Election Commission of India	Amendment in Notification No. 429/A & NI/69, dated the 13th November, 1969.
	एस० ओ० 211, दिनांक 7 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 429/आ० नि० डी०] 69, तारीख 13 नवम्बर, 1969 में संशोधन ।
12.	S.O. 212, dated 7th January, 1971	Ditto.	Amendment in Notification No. 434/PB/69, dated the 7th November, 1970.
	एस० ओ० 212, दिनांक 7 जनवरी 1971	तदैव	अधिसूचना सं० 434/पंजाब/69, तारीख 7 नवम्बर 1970 में संशोधन ।
13.	S.O. 213, dated 7th January, 1971	Ditto.	Appointment of Returning Officer and Assistant Returning Officers in respect of the Parliamentary Constituency of Andaman and Nicobar Islands.
	एस० ओ० 213, दिनांक 7 जनवरी 1971	तदैव	अण्डमान और निकोबार द्वीप के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति ।
14.	S.O. 214, dated 7th January, 1971	Ditto.	Further amendment in Notification No. 434/RJ/66, dated the 11th August, 1966.
	एस० ओ० 214 दिनांक 7 जनवरी 1971	तदैव	अधिसूचना सं० 434/राज०/66 तारीख 11 अगस्त 1966 में और आगे संशोधन ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
15	S. O. 215, dated January, 1971	7th Election Commission of India	Further amendment in Notification No. 434/NL/66, dated the 18th June 1966.
	का० आ० 215 दिनांक 7 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 434/नागा०/66 तारीख 18 जून 1966 में और आगे संशोधन ।
16	S. O. 216, dated January, 1971	7th Ditto.	Delimitation of Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
	एस० आ० 216 दिनांक 7 जनवरी 1971	तदैव	हिमाचल प्रदेश राज्य में ससदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिशोधन के लिए प्रस्थापनाएं ।
17	S.O. 217, dated January, 1971	8th Ministry of Irrigation & Power	The Supply of electrical energy to the Public in the State of Bihar declared as an essential Service.
	का० आ० 217 दिनांक 8 जनवरी 1971	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	बिहार राज्य में जनता को विद्युत शक्ति से सेवा को आवश्यक सेवा घोषित ।
	S. O. 218, dated January, 1971	8th Ditto.	Prohibition of Strikes in any Service in the State of Bihar connected with the supply of electrical energy to the Public.
	का० आ० 218 दिनांक 8 जनवरी 1971	तदैव	बिहार राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध जो जनता को विद्युत् शक्ति से सम्बन्धित ।
18	S. O. 219, dated January, 1971	8th Election Commission of India.	Further amendments in Notifications No. 434-OR/66 (I), dated the 8th June 1966.
	एस० आ० 219 दिनांक 8 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 434/उडी०/66(1) तारीख 8 जून 1966 में और आगे संशोधन ।
19	S.O. 220, dated, January 1971	8th. Ministry of Finance	Making of the Order to exempt a person from the operation of the time limit if he repays the loan.
	का० आ० 220 दिनांक 8 जनवरी 1971	वित्त मंत्रालय	उन व्यक्ति को समय परिसीमा के प्रवर्तन से छूट दे दी जाएगी जो किस्तों को प्रतिसंदत्त कर देता है उस पर आदेश ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
20	S. O. 221, dated January, 1971	8th Ministry of Information & Broadcasting.	Approval of the films so specified in the Schedule in all their language versions.
	एस० ओ० 221 दिनांक 8 जनवरी 1971	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में विनिर्दिष्ट फिल्मों को सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित स्वीकृति ।
	S. O. 222, dated January, 1971	8th Ditto.	Approval of a film so specified in the Schedule in all its language versions.
	एस० ओ० 222 दिनांक 8 जनवरी 1971	तदैव	अनुसूची में विनिर्दिष्ट फिल्मों को सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित स्वीकृति ।
	S. O. 223, dated January, 1971	8th Ditto.	Approval of a film so specified in the Schedule in all its language versions.
	एस० ओ० 223 दिनांक 8 जनवरी 1971	तदैव	अनुसूची में विनिर्दिष्ट फिल्मों को सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित स्वीकृति ।
21	S. O. 224, dated January, 1971	8th Election Commission of India.	Appointment of Returning and Assistant Returning Officers in respect of the Parliamentary Constituencies in the State of Madhya Pradesh.
	एस० ओ० 224 दिनांक 8 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति ।
22	S. O. 225, dated January, 1971	8th Ministry of Food, Agri., Com. Dev. & Co-operation.	Fixation of maximum prices at which vegetable oil products may be sold in various Zones w.e.f. 9-1-71.
	का० आ० 225 दिनांक 8 जनवरी 1971	खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को विभिन्न क्षेत्रों में 9 जनवरी 1971 से विक्रय किया जा सकेगा इसका नियतिकरण ।
23	S. O. 226, dated January, 1971	8th Election Commission of India.	Further amendments in Notification No. 508/AS /66, dated the 1st January, 1967.
	एस० ओ० 226 दिनांक 8 जनवरी 1971	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 508/असम/66 तारीख 1 जनवरी 1967 में और आगे संशोधन ।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
23-A	S.O. 226-A, dated 11th January, 1971	Ministry of Petro. Chem. and Metals.	& Further amendment in the Drugs (Prices Control) Order, 1970.
23-B	S.O. 225-B, dated 11th January, 1971	Cabinet Secretariat	Constituting an Advisory Committee to recommend the initial Strength and Composition of a State Cadre of (i) I.A.S., (ii) I.P.S. and (iii) I. Forest S. for the State of Himachal Pradesh.
का०	आ० 226-बी, दिनांक 11 जनवरी, 1971	मंत्रिमंडल सचिवालय	एक सलाहकार समिति की स्थापना जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए (i) भारतीय प्रशासन सेवा (ii) भारतीय पुलिस सेवा और (iii) भारतीय वन सेवा के राज्य संवर्ग की आरंभिक संख्या और संरचना की सिफारिश करेगा।
24	S. O. 227, dated 12th January, 1971	Ministry of Home Affairs	Declaring the All Jammu and Kashmir Plebiscite Front as an unlawful association.
	S. O. 228, dated 12th January, 1971	Ditto	Effect of the prior said notification from the date of its publication in the official Gazette.
	S. O. 229, dated 12th January, 1971	Ditto]	Direction to Jammu & Kashmir Govt. to exercise all the power used by Central Govt., under Sections 7 and 8 of the law so mentioned.
25	S. O. 230, dated 12th January, 1971	Election Commission of India.	of Amendment in Notification No. 434/MR / 69, dated the 22nd December, 1969.
एस०	ओ० 230, दिनांक 12 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 434/मनी० 69, तारीख 22 दिसम्बर, 1969 में संशोधन।
26	S. O. 231, dated 12th January, 1971	Ditto.]	Appointment of Retraining officers and Assistant Returning officers for each of the Parliamentary Constituencies in the State of Bihar so specified in the Table.
एस०	ओ० 231, दिनांक 12 जनवरी, 1971	तथैव	सारणी में विनिर्दिष्ट रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों को बिहार राज्य के प्रत्येक संसदीय चुनाव के लिए नियुक्ति।

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
27	S. O. 232, dated 12th January, 1971	Election Commission of India	Amendment in Notification No. 429 / A & NI / 69, dated the 1st January, 1971.
	एस० ओ० 232, दिनांक 12 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन अ.योग	अधिसूचना सं० 229/अ० नि० दबी/ 69, तारीख 1 जनवरी 1971 में संशोधन ।
28	S. O. 233, dated 12th January, 1971	Ditto.	Amendments in Notification No. 434/ TP / 69, dated the 6th March, 1970.
	एस० ओ० 233, दिनांक 12 जनवरी, 1971	तथैव	अधिसूचना सं० 434/त्रिपुरा/69, तारीख 6 मार्च 1970 में संशोधन ।
29	S. O. 234, dated 12th January, 1971	Ministry of Information & Broadcasting	Approval of a film so specified in the Schedule in all its Language versions.
	एस० ओ० 234, दिनांक 12 जनवरी, 1971	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में विनिर्दिष्ट फिल्मों का सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित स्वीकृति ।
	S. O. 235, dated 12th January, 1971	Ditto.	Approval of a film so specified in the Schedule in all its Language versions.
	एस० ओ० 235, दिनांक 12 जनवरी, 1971	तथैव	अनुसूची में विनिर्दिष्ट फिल्म का सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित स्वीकृति ।
30	S. O. 236, dated 12th January, 1971.	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade	Granting of recognition to the Hansi Punjab Commercial Exchange Ltd., Hansi for a further period of 2 years from the 13th January, 1971 to 12th January, 1973 (both days inclusive).
	का० आ० 236, दिनांक 12 जनवरी, 1971	औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय	13 जनवरी 1971 से लेकर 12 जनवरी 1973 तक दो वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए हांसी पंजाब कमर्शियल एक्सचेंज लि० हांसी की मान्यता प्रदान ।
31	S. O. 237, dated 12th January, 1971.	Election Commission of India.	Appointment of Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer for the Parliamentary Constituency of Chandigarh Union Territory.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	एस० ओ० 237, दिनांक 12 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों का चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्ति ।
32	S. O. 238, dated 12th January, 1971	Ditto.	Further Amendment in Notification No. 434/J. & K/H P /66, dated the 7th December, 1966.
	एस० ओ० 238, दिनांक 12 जनवरी 1971	तथैव	अधिसूचना सं० 434/जम्मू और काश्मीर/लो० सं०/66 तारीख 7 दिसम्बर 1966 में और आगे संशोधन ।
33	S. O. 239, dated 12th January, 1971	Ditto.	Amendment in Notification No. 429/J. & K. IIP/66, dated the 10th November 1966.
	एस० ओ० 239 दिनांक 12 जनवरी, 1971	तथैव	अधिसूचना सं० 429/जम्मू और काश्मीर/लो० सं०/66, तारीख 10 नवम्बर, 1966 में और आगे संशोधन ।
34	S. O. 240, dated 14th January, 1971.	Ditto.	Amendments in Notification No. 434/DL/70 (1) dated the 30th December, 1970.
	एस० ओ० 240, दिनांक 14 जनवरी, 1971	तथैव	अधिसूचना सं० 434/दिल्ली/70(1) तारीख 30, दिसम्बर, 1970 में और आगे संशोधन ।
35	S. O. 241, dated 14th January, 1971	Ditto.	Amendments in Notification No. 434/ HN / 67, dated the 23rd November 1967.
	एस० ओ० 241, दिनांक 14 जनवरी, 1971	तथैव	अधिसूचना सं० 434/हर 0/67, तारीख 23 नवम्बर, 1967 में और आगे संशोधन ।
36	S. O. 242, dated 14th January, 1971	Ministry of Railways.	Appointing Shri S. Swamikannu to deal with all claims arising out of the accident involving No. 19 Madras-Cochin Mail and No. 1 Madras-Mangalore Mail at Perambur Station.

Issue No. and Date	Issued by	Subject
एस० ओ० 242, दिनांक 14 जनवरी, 1971	रेल मंत्रालय	पैरम्बूर स्टेशन पर नं० 19 मद्रास-कोच्चिन मेल और नं० 1 मद्रास-मंगलूर के बीच हुई दुर्घटना से उत्पन्न दावों के निबटाने के लिए श्री एस० स्वामीकृष्ण की नियुक्ति।
37. S.O. 243, dated 14th January, 1971.	Election Commission of India.	Appointment of Returning Officers and Assistant Returning Officers, so specified in the Table, for the Parliamentary Constituencies in the State of Kerala.
एस० ओ० 243, दिनांक 14 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	सारणी में उल्लिखित रिटर्निंग आफिसरों तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों का केरल राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्ति।
38. S.O. 349, dated 14th January, 1971	Ministry of Finance	Exempting goods so specified in the Table from the duty of customs leviable thereon.
एस० ओ० 349, दिनांक 14 जनवरी, 1971	वित्त मंत्रालय	सारणी में विनिर्दिष्ट मालों को उद्-ग्रहणीय सीमा शुल्क से छुट।
39. S.O. 350/15/IDRA/70, dated 14th January 1971.	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade	Appointment of Shri A. K. Ghosh, as a member, to investigate into the affairs of Mohini Mills Ltd. No. 2 Belgharia, W. Bengal vice Shri T.N. Pandey.
का० आ० 350/15/आई० डी० आर० ए० 70, दिनांक 14 जनवरी, 1971	औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय	मोहिनी मिल्स नं० 2, बेलघारिया (पश्चिमी बंगाल) के कार्यों की जांच करने के लिए श्री ए० के० घोष को श्री टी० एन० पांडे के स्थान पर नियुक्ति।
40. S.O. 351, dated 14th January, 1971	Election Commission of India.	Further amendments in Notification No. 508/ AS/66, dated the 1st January 1967.
एस० ओ० 351, दिनांक 14 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 508/असम/66, ता० 1 जनवरी, 1967 में और अंग्रे संशोधन।
41. S.O. 352, dated 15th January, 1971	Ministry of Shipping & Transport.	Appointing the 1st day of Apr. 1971 as the date on which the provisions of Sections 33, 34, 76 and 82 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 1969 (56 of 1969) shall come into force.

Issue No. and Date	Issued by	Subject
एस० ओ० 352, दिनांक 15 जनवरी, 1971	पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय	1971 के अप्रैल के प्रथम दिन को उस तारोख के रूप में नियत करती है जिस तारोख को मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का 56) की धारा 33, 34, 76 और 82 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।
42. S.O. 353, dated 16th January 1971	Ministry of Law	Further amendment in the Con- duct of Elections Rules, 1961.
का० आ० 353, दिनांक 16 जनवरी, 1971	विधि मंत्रालय	निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में और आगे संशोधन।
43. S.O. 354, dated 16th January 1971	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade	Granting of recognition to the Pepper & Ginger Merchant's Association Ltd., Bombay for a period of 2 years ending the 18th January 1973 in respect of forward contracts in pepper.
एस० ओ० 354, दिनांक 16 जनवरी, 1971	औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय	जिजर मर्चेन्ट्स एसोशियेशन लिमिटेड बम्बई को काली मिर्च की अग्रिम संबिदाओं की बाबत 18 जनवरी, 1973 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान।
44. S.O. 355, dated 16th January 1971	Election Commission of India.	Appointment of Returning Officers and Assistant Re- turning Officers, so specified in the Table, for the election in the Parliamentary Constitu- encies in the State of Mysore.
एस० ओ० 355, दिनांक 16 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	सारणी में उल्लिखित रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों का मैसूर राज्य के हर एक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्ति।
45. S.O. 356, dated 18th January 1971	Ministry of Food, Agri., Com. Dev. & Co-opera- tion.	Appointing the National Seeds Corporation as seed certifica- tion agency for the State of Rajasthan upto 31-3-71.
एस० ओ० 356, दिनांक 18 जनवरी, 1971	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सह- कारिता मंत्रालय	राजस्थान राज्य के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को 31 मार्च, 1971 तक बीज प्रमाणिकरण एजेंसी के रूप में नियुक्त करना।

Issue No. and Date No.	Issued by	Subject
46. S.O.357, dated 18th January 1971	Election Commission of India.	Appointment of Returning Officers and Assistant Returning Officers, so specified in the Table, for the election in the Parliamentary Constituencies in the State of Tamil Nadu.
एस० ओ० 357, दिनांक 18 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	सारणी में त्रिनिटिडिस्ट रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों का तामिलनाडू राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्ति ।
47. S.O.358, dated 18th January 1971	Ditto	Further amendments in Notification No.429/J.&K./HP/66, dated the 10th November, 1966.
एस० ओ० 358, दिनांक 18 जनवरी, 1971	तद्वैव	अधिसूचना सं० 429/जम्मू और काश्मीर लो० सं० 66, तारीख 10 नवम्बर, 1966 में और आगे संशोधन ।
48. S.O.359, dated 18th January 1971	Ministry of Home Affairs	The unlawful Activities (Prevention)(Second Amendment) Rules, 1971.
एस० ओ० 359, दिनांक 18 जनवरी, 1971	गृह मंत्रालय	निधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (द्वितीय संशोधन), नियम 1971 ।
49. S.O.360, dated 18th January 1971	Election Commission of India.	Delimitation of Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
एस० ओ० 360, दिनांक 18 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	हिमाचल प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार ।
50. S.O.361/15/IDRA/70, dated 18th January 1971	Ministry of Industrial Dev. & Internal Trade.	Appointing a body of persons to investigate into the circumstances of the Shree Shanmugar Mills Ltd., Rajapalayam (Tamil Nadu).
का० आ० 361/15/आई० डी० आर० ए० 70, दिनांक 18 जनवरी, 1971	औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय	श्री शानुमुगार मिल्स लिमिटेड, राज-पलायम, (तामिल नाडु) नामक औद्योगिक उपक्रम का मामले की परिस्थितियों का जांच करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों के एक निकाय की नियुक्ति ।

Issue No. and Date No.	Issued by	Subject
51. S.O. 362, dated 19th January 1971	Ministry of Home Affairs	Establishing an Advisory Committee to recommend members for the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service and the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service.
का० आ० 362, दिनांक 19 जनवरी, 1972	गृह मंत्रालय	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा और दिल्ली हिमाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप पुलिस सेवा में अधिकारीओं का सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन।
52. S.O. 363, dated 20th January 1971	Election Commission of India	Appointment of Returning Officers and Assistant Returning officers, so specified in the Table, for the purpose of election in each of the Parliamentary Constituencies in the State of Uttar Pradesh.
एस० ओ० 363, दिनांक 20 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	सारणी के विनिर्दिष्ट रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों का उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्ति।
53. S.O. 364, dated 20th January 1971	Ministry of Industrial Dev. and Internal Trade	Notifying the directions, so declared, to continue as being necessary or expedient in the public interest.
एस० ओ० 364, दिनांक 20 जनवरी, 1971	औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय	अधिसूचना द्वारा जारी किये गये निदेश को, जो प्रकाशित हुआ था, जनहित में आवश्यक समझ कर अधिसूचित करती है।
54. S.O. 365, dated 20th January 1971	Ministry of Petroleum and Chem. & Mines and Metals.	Further amendment in the Order S.O. No. 1873 dated the 18th May 1970 of the said Ministry.
का० आ० 365, दिनांक 20 जनवरी, 1971	पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय	इस मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 1873, तारीख 18 मई 1970 में और आगे संशोधन।
55. S.O. 420, dated 20th January 1971	Ministry of Home Affairs	Amendment in the Official Trustee, Bombay (Reorganisation) Order, 1963.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
	का० आ० 420, दिनांक 20 जनवरी, 1971	गृह मंत्रालय	शासकीय न्यासी, मुम्बई (पुनर्गठन) आदेश, 1963 में संशोधन ।
	S.O.421, dated 20th January 1971.	Ministry of Home Affairs	Directing the whole of the properties so mentioned case to be vested in the official Trustee, Maharashtra State and the Vested in the Official Trustee, Gujarat State.
	का० आ० 421, दिनांक 20 जनवरी, 1971	तथैव	आदेश में उल्लिखित सम्पत्ति शासकीय न्यासी महाराष्ट्र राज्य में निहित नहीं रहेगी और शासकीय न्यासी राज्य में निहित होगी ।
56.	S.O. 422, dated 21st January 1971	Ministry of Railways	Extension of the period of operation of the Order No. S.O. 2636, dated the 27th July 1970 for a further period of six months w.e.f. the 27th January 1971.
	एस० ओ० 422, दिनांक 21 जनवरी, 1971	रेल मंत्रालय	27 जुलाई, 1970 के आदेश सं० एस० ओ० 2636 की अवधि 27 जनवरी, 1971 को और उस तारीख से छः महीने के लिए और बढ़वाना ।
57.	S.O.423, dated 21st January 1971	Election Commission of India.	Appointment of Returning Officers and Assistant Returning Officers for the purpose of election in each of the Parliamentary Constituencies in the State of Himachal Pradesh.
	एस० ओ० 423, दिनांक 21 जनवरी, 1971	भारत निर्वाचन आयोग	सारणी में विनिर्दिष्ट रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसरों को हिमाचल प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्ति ।
58.	S.O.424, dated 21st January 1971	Ministry of Home Affairs	Amendment in the Ministry of Home Affairs S.O. No. 3159, dated the 19th October 1966.
	एस० ओ० 424, दिनांक 21 जनवरी, 1971	गृह मंत्रालय	गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3159 तारीख 19 अक्टूबर, 1966 में संशोधन ।

Issue No. and Date No.	Issued by	Subject
S.O. 425, dated 21st January 1971	Ministry of Home Affairs	Extension of term of Office of all the existing Councillors of D.C.M. for 60 days.
क्र० आ० 425, दिनांक 21 जनवरी, 1971	गृह मंत्रालय	दिल्ली नगर निगम के सभी विद्यमान पार्षदों और पौर-मुख्यों की पदावधि साठ दिन की अवधि तक विस्तारित।
59. S.O. 426, dated 21st January, 1971	Ministry of Finance	Amendment in the Notification No.S.O. 4156, dated the 3rd October 1969 of the Ministry of Finance.
क्र० आ० 426, दिनांक 21 जनवरी, 1971	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आ० 4156, तारीख 3 अक्टूबर, 1969 में संशोधन।
60. S.O. 427, dated 22nd January, 1971	Ditto	Authorising the sums of expenditure not exceeding those specified in the Schedule be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.
एस० आ० 427, दिनांक 22 जनवरी, 1971	तथैव	हिमाचल राज्य की समेकित निधि से हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा की मंजूरी मिलने तक इतनी रकमें खर्च की जायें जो अनुसूची में उल्लिखित रकमों से अधिक न हों।
S.O. 428, dated 22nd January, 1971	Ditto	Authorising the sums of expenditure not exceeding those specified in the Schedule be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.
एस० आ० 428, दिनांक 22 जनवरी, 1971	तथैव	हिमाचल राज्य की समेकित निधि से हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा की मंजूरी मिलने तक इतनी रकमें खर्च की जायें जो अनुसूची में उल्लिखित रकमों से अधिक न हों।
61. S.O. 429, dated 22nd January, 1971	Ministry of Home Affairs	Directing every person to be on deputation to the Govt. of Himachal Pradesh on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before the appointed day.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
एस० ओ० 429,	दिनांक 22 जनवरी, 1971	गृह मंत्रालय	हिमाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक के अधीन प्रतिनियुक्त व्यक्ति को उन्हीं शर्तों पर जो कि उसे निर्धारित दिन से तत्काल पूर्व लागू भी प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएँ

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1760.—In pursuance of sub-section (3) of section 4 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with paragraph 44 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2104 dated 1st June, 1970, the Central Government hereby directs that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

- | | |
|---|----------------------------|
| (i) in Central Government securities. | Not less than 50 per cent. |
| (ii) in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax-free Small Savings securities and in the 1-year, 3-year and 5-year Time Deposits in Post Offices. | Balance. |

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in saving certificates

issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in the first paragraph.

3. The above pattern will be in force for the period from the 1st April, 1971, to the 30th April, 1971.

4. This notification shall come into force on the first day of April, 1971.

[No. 5-MT (7)/70.]

J. C. JETLI, Dy. Secy.

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1971

का० प्रा० 1760.—नाविक निर्वाह निधि योजना, 1966 के पैराग्राफ 44 के साथ पठित नाविक निर्वाह निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 4 की उपधारा (3) का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2104 दिनांक 1-6-1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि निर्वाह निधि अंशदान की जमापूँजी, व्यय तथा अन्य प्राप्तियों में से अनिवार्य बहुिर्गामी राशियाँ को कम, करने के बाद जो संचय रहेगा उसे निम्नलिखित ढंग से लगाया जाएगा, अर्थात् :

(1) केन्द्रीय सरकार की सैक्यूरिटीज में— 50 प्रतिशत से कम नहीं।

(2) राज्य सरकारों की सैक्यूरिटीज, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा गारंटी शदा सैक्यूरिटीज, कर-मुक्त अल्प बचत सैक्यूरिटीज में और डाक घरों के एक वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष के सावधिक जमा में शेष

2. निर्वाह निधि के संचय का सारा पुनर्निवेश (चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सजित और जारी की गई सैक्यूरिटीज अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये बचत प्रमाण पत्रों अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा सजित और जारी की गई सैक्यूरिटीज में लगाया गया हो) प्रथम पैराग्राफ में दिये गये ढंग के अनुसार ही किया जाएगा।

3. उपरोक्त प्रतिरूप 1 अप्रैल, 1971 से 30 अप्रैल, 1971 तक की अवधि में लागू रहेगा।

4. यह अधिसूचना अप्रैल, 1971 के प्रथम दिवस से लागू होगी।

[सं० 5-एम टी (7)/70]

जे० सी० जेतली, उप सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April 1971

S.O. 1761.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 157 of the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959, the Central Government hereby makes the

following corrections against the existing entries in this Ministry's notification of even number dated the 31st October, 1970:—

For

"Shri Sibendra Nath Mukherjee, C/o Messrs, S. N. Mukherjee & Co., 1, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, West Bengal (India)".

Read

"Shri Shibendra Nath Mukerjee, C/o Messrs, S. N. Mukerjee & Co., 1, Netaji Subhas Road, Calcutta-1, West Bengal (India)".

[No. 29(I)-I.T(TM)/70.]

P. SITARAMAN, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 26 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1761.—व्यापार तथा वाणिज्य चिन्ह नियम, 1959 के नियम, 157 के उप-नियम (2) के अनुसरण से, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस मंत्रालय की इसी संख्या वाली अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 1970 की विद्यमान प्रविष्टियों में निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है:—

के स्थान पर:

"श्री सिबेन्द्र नाथ मुखर्जी,
द्वारा मै० एस० एन० मुखर्जी एण्ड कं०,
1, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता—1, पश्चिम बंगाल (भारत)" ।

पढ़िए:

"श्री शिवेन्द्र नाथ मुखर्जी,
द्वारा मै० एस० एन० मुखर्जी एण्ड कं०,
1, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता—1, पश्चिम बंगाल (भारत) " ।

[सं० 29(1)-आई० टी० (टी एस०)/70]

पं० सीतारामन, उप सचिव ।

(Department of Industrial Development)

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 7th April 1971

S. O. 1762.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notified that the marking fee(s) per unit for various products, details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of effect
1	2	3	4	5	6
1.	Varnished cotton cloth and tapes for electrical purposes.	IS:3352-1965 Specification for varnished cotton cloth and tapes for electrical purposes.	1 square metre	3 Paise	16 February 1971

1	2	3	4	5	6
2	jute carpet backing fabric	IS: 4900-1969 Specification for jute carpet backing fabric (271, 305, 339 and 407 g/ m ²)	One tonne	Rs. 2.00	1st March 1971

[No. CMD/13:IC.]

(औद्योगिक विकास विभाग)]

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 7 अप्रैल 1971

एस० प्रो० 1762--भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह, विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से सूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की पट्टांकन फीस जिनके बारे में अनुसूची में दिए हैं, निर्धारित की गई हैं और ये फीस उनके आगे लिखी तिथियों से लागू हों जाएंगी :

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पर संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	बिजली के कार्यों के लिए वार्निश किया सूती कपड़ा और टेप	IS-: 3352-1965 बिजली के कार्यों के लिए वार्निश किए सूती कपड़े और टेप की विशिष्टि	एक वर्ग मीटर	3 रू० से	16 फरवरी 1971
2	जूट के गलीचे के पीछे लगाने का कपड़ा	IS-: 4900-1969 जूट के गलीचे के पीछे लगाने के कपड़े (271, 305, 339 और 407 ग्राम/मी ²) की विशिष्टि	एक मीटरी टन	रु० 2-00	1 मार्च 1971

[संख्या सी० एम० डी०/13:10]

New Delhi, the 19th April, 1971

S.O. 1763.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that one hundred and nineteen licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed:

THE SCHEDULE

Sl.No.	Licence No. and date.	Period of Validity		Name & Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licence and the Relevant IS : Designation.
		from	to		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CM/L-10 11-6-1956	16-6-1970	15-6-1971	Jeewanlal (1929) Ltd., Crown Aluminium Works, 26 Parel Tank Road, Bombay-12.	Wrought aluminium and aluminium alloy utensils— IS : 21—1959
2	CM/L-11 11-6-1956	16-6-1970	15-6-1971	Jeweanlal (1929) Ltd., Crown Aluminium Works, 95, Grand Trunk Road, P. O. Belurmath, Distt. Howrah.	(i) Wrought aluminium and aluminium alloy utensils IS : 21—1959 and (ii) Wrought aluminium and aluminium alloy utensils grade SIC, anodized— IS : 1868—1968.
3	CM/L 27 20-5-1957	1-6-1970	31-5-1971	Electrical Manufacturing Co. Ltd., EMC Gardens, 136, Jessore Road, Calcutta-55.	Hard-drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS : 398—1961.
4	CM/L-30 11-7-1957	16-7-1970	30-6-1973	The India Cement Ltd., Sankarnagar, Talaiyuthu, Distt. Tirunelveli.	Ordinary & rapid hardening portland cement— IS : 269—1967.
5	CM/L-88 22-5-1958	1-6-1970	30-4-1971	Hindustan Brown Boveri Ltd., Industrial Area, New Township, Faridabad (Haryana)	Aluminium conductors, steel re-inforced and all aluminium conductors— IS : 398—1961.
6	CM/L-132 24-6-1959	1-7-1970	30-6-1971	E. I. D. Parry Ltd., Dare House, Madras-1.	DDT dusting powders— IS : 564—1961.
7	CM/L-190 25-5-1960	1-6-1970	31-5-1971	The Indian Turpentine & Rosin Co. Ltd., P. O. Glutterbuckganj, Bareilly (UP)	Rosin (Gum rosin)— IS : 553—1955.
8	CM/L-195 30-5-1960	16-6-1970	15-12-1970	Western India Plywood Ltd., Baliapatam, Cannanore Distt., (Kerala)	Plywood for general purposes— IS : 303—1960.
9	CM/L 268 30-1-1961	1-6-1970	31-5-1971	All India Medical Corporation, M. J. Jetha Building, 185, Princess Street, Bombay 2.	BHC water dispersible powder— IS : 562—1962.
10	CM/L 285 8-3-1961	1-6-1970	31-5-1971	Do.	BHC dusting powders— IS : 561—1962.

11	CM/L-299 28-4-1961	16-5-1970	15-5-1971	J. B. Mengha Ram & Co. Pvt. Ltd., P. O. Residency, Gwalior.	Biscuits— IS : 1011—1968.
12	CM/L 300 28-4-1961	16-5-1970	15-5-1971	New Digvijaysinhji Tin Factory, Grain Mar- ket, Jamnagar	18 litre square tins— IS : 16—1966
13	CM/L 315 26-6-1961	1-7-1970	30-6-1971	Rohtas Industries Ltd., Dalmianagar (Bihar)	Unreinforced corrugated asbestos cement sheets (includ- ing semi corrugated)— IS : 459—1962.
14	CM/L 338 1-9-1961	16-6-1970	15-12-1970	Indo Asian Traders Pvt. Ltd., Nakodar Road Jullundur City.	Metal clad switches, 15 Amp 250 Volts with HC type fuse base & carrier— IS : 4064—1967
15	CM/L 341 20-9-1961	16-6-1970	15-6-1971	Mysore Insecticides Co. (Andhra), 18/257, Ghandhinagar, P' B. No. 425, Vijayawada- 3.	BHC dusting powder— IS : 561—1962
16	CM/L-342 20-9-1961	1-6-1970	31-5-1971	Ali India Medical Corporation, Mulji Jetha Building, 185, Princess Street, Bombay-2.	DDT water dispersible powder— IS : 565—1961
17	CM/L-375 12-1-1962	16-6-1970	15-6-1971	Balgopal Das Iron & Steel Co. Pvt. Ltd., 5, Gopal Doctor Road, Kidderpore, Cal- cutta-23.	18-litre square tins— IS : 916—1966
					Type Voltage Grade Conductor
18	CM/L-413 5-5-1962	16-5-1970	15-1-1971	Devidayal Cable Industries Pvt. Ltd., Pokhran Road, Mahiwada Village, Thana (Maharashtra)	(a) VIR Cables for fixed wiring (i) TRS (tough rub- ber sheathed) . 250/440 and (ii) Braided and compounded. 650/1 100 Volts. (iii) Weatherproof . 250/440 Volts (iv) Flame retarding 250/440 and 650/1 100 Volts (v) Weatherproof. 650/1 100 Volts (b) VIR flexible cables (vi) Welding cables — (c) VI flexible cords (vii) TRS (tough rub- bersheathed) 250/440 Volts. IS : 434 (Parts I & II)—1964
19	CM/L-535 30-4-1963	1-6-1970	30-6-1971	Power Cables Pvt. Ltd., Vithalwadi (Maha- tra.)	PVCCables only with aluminium Conductors, 250 and 650 volts grade— IS : 694 (Part II) 1964.
20	CM/L-539 13-5-1963	16-6-1970	30-9-1971	Tata Fision Industries Ltd., 20, Howrah Rd. Salkia, Calcutta.	COQ water dispersible powder concentrates— IS : 1507—1966

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	CM/L-546 5-6-1963	1-6-1970	30-11-1970	Vareti Timber Assam (P) Ltd., Makum Road, Tinsukia, Assam.	Tea chest plywood panels— IS : 10—1964.
22	CM/L-582 19-9-1963	16-10-1969	15-10-1970	Kamani Tubes Pvt. Ltd., Agra Road, Kurla, Bombay-70.	Free cutting brass rods and sections of the following sizes: Rounds : All sizes from 6.0 mm to 40 mm. Hexagonals : All sizes from 10.0 mm to 40 mm AF. Squares : All sizes from 12.0 mm to 25 mm Grade : 'CUZM 42 Pb.3d— IS : 319—1968
23	CM/L-611 31-12-1963	16-6-1970	15-6-1971	Prakash Pulversing Mills, Industrial Area, Alwar.	BHC dusting powders— IS : 561—1962
24	CM/L-656 29-4-1964	1-6-1970	31-5-1971	Tensile Steel Ltd., Hirabaug, Vishwamitri Road, Baroda.	Plain hard-drawn steel wire for prestressed concrete— IS : 1785 (Part I)—1966
25	CM/L-663 1-5-1964	1-6-1970	31-5-1971	Industrial Cables (India) Ltd., Industrial Area, Rajpura (Punjab).	Paper-insulated lead-sheathed cables with aluminium conductor for electricity supply upto and including 33 KV— IS : 692—1965
26	CM/L-666 7-5-1964	15-6-1970	15-6-1971	Mukand Iron & Steel Works, Ltd., Kurla, Bombay-70.	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1969
27	CM/L-681 17-6-1964	1-7-1970	30-6-1971	The Indian Steel Rolling Mills Ltd., 'Mill Building', P. B. No. 1, Nagapattinam, Tanjore Distt.	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1969
28	CM/L-682 17-6-1964	1-7-1970	30-6-1971	Do.	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1969
29	CM/L-780 10-9-1964	1-7-1970	30-6-1970	S. R. Sharma & Sons, 140, Rai Bahadur R. N. Guha Road, Dum Dum, Calcutta-28.	Brass ball valves (horizontal plunger type) 15 mm size— IS : 1703—1968.
30	CM/L-801 20-10-1964	1-6-1970	31-5-1971	Satellite Engineering Ltd., P. O. Maize Products, Kathwada, Ahmedabad-2.	Starters for fluorescent lamps, 26/40/80 watts rating— IS : 2215—1968
31	CM/L-829 2-11-1964	16-6-1970	15-12-1970	National Industrial Corporation, 99/100, Agra Road, Bhandup, Bombay-78, N. B.	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1969
32	CM/L-830 2-11-1964	16-6-1970	15-12-1970	Do.	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1969
33	CM/L-861 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	The Kinnison Jute Mills Co. Ltd., Titaghur, 24 Parganas.	(i) Jute hessian— IS : 2818—1964 and (ii) Hessian bags— IS : 3790—1966
34	CM/L-862 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS : 1943—1964 IS : 2566—1965 IS : 2874—1964 IS : 2875—1964 IS : 3667—1966

IS : 3668—1966
IS : 3750—1966
IS : 3751—1966
IS : 3794—1966

35	CM/L-877 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Samnuggur Jute Factory Co. Ltd., Bhadreswar, Hooghly. (Off: 3, Clive Row, Calcutta-1).	(i) Jute hessian— IS : 2818—1964 and (ii) Hessian bags— IS : 3790—1966	
36	CM/L-878 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS : 1943—1964 IS : 2566—1965 IS : 2874—1964 IS : 2875—1964 IS : 3667—1966	IS : 3668—1966 IS : 3750—1966 IS : 3751—1966 IS : 3794—1966
37	CM/L-881 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Victoria Jute Co. Ltd., P. O. Telinipara, Distt. Hooghly.	(i) Jute hessian— IS : 2818—1964 and (ii) Hessian bags— IS : 3790—1966	
38	CM/L-882 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS : 1943—1964 IS : 2566—1965 IS : 2874—1964 IS : 2875—1964 IS : 3667—1966	IS : 3668—1966 IS : 3750—1966 IS : 3751—1966 IS : 3794—1966
39	CM/L-913 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Bally Jute Co. Ltd., 25, Scott Kerr Road, Bally, Howrah.	(i) Jute hessian— IS : 2818—1964 and (ii) Hessian bags— IS : 3790—1966	
40	CM/L-914 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS : 1943—1964 IS : 2566—1965 IS : 2874—1964 IS : 2875—1964 IS : 3667—1966	IS : 3668—1966 IS : 3750—1966 IS : 3751—1966 IS : 3794—1966
41	CM/L-935 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Kelvin Jute Co. Ltd., Titaghur, 24 Parganas.	(i) Jute hessian— IS : 2818—1964 and (ii) Hessian bags— IS : 3790—1966	
42	CM/L-936 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS : 1943—1964 IS : 2566—1965 IS : 2874—1964 IS : 2875—1964 IS : 3667—1966	IS : 3668—1966 IS : 3750—1966 IS : 3751—1966 IS : 3794—1966

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	CM/L-949 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Shree Hanuman Jute Mill, 76, Jogendra Nath Mukherjee Road, Ghosuri, Howrah.	(i) Jute Hessian— IS: 2818-1964 and (ii) Hessian bags— IS: 3790-1966
44	CM/L-950 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS: 1943-1964 IS: 2566-1965 IS: 2874-1964 IS: 2875-1964 IS: 3667-1966 IS: 3668-1966 IS: 3750-1966 IS: 3751-1966 IS: 3794-1966
45	CM/L-957 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Prabartak Jute Mills Ltd., Kamarhatty, B.T. Road, 24 Parganas	(i) Jute Hessian— IS: 2818-1964 and (ii) Hessian bags— IS: 3790-1966
46	CM/L-958 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Jute sackings— IS: 1943-1964 IS: 2566-1965 IS: 2874-1964 IS: 2875-1964 IS: 3667-1966 IS: 3668-1966 IS: 3750-1966 IS: 3751-1966 IS: 3794-1966
47	CM/L-1036 19-3-1965	1-7-1970	30-6-1971	Anand Insecticides 4/5, Elaiya Street, Korukupet, Madras-21.	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310-1958
48	CM/L 1068 18-5-1965	16-5-1970	15-10-1970	Bhagsons Paint Industries (India) 16-A, D.L.F. Industrial Area, Najafgarh Road, New Delhi-15.	(i) Varnish goldsize— IS: 198-1952 (ii) Varnish, finishing, interior— IS: 337-1952 (iii) Varnish, mixing— IS: 340-1952 and (iv) French polish— IS: 348-1952
49	CM/L-1090 3-6-1965	16-6-1970	15-6-1971	West India Steel Co. Ltd., Cheruvannur, Feroke (Kerala).	Structural steel (standard quality)— IS: 226-1969
50	CM/L-1091 3-6-1965	16-6-1970	15-6-1971	Do.	Structural steel (ordinary quality)— IS: 1977-1969
51	CM/L-1114 28-7-1965	16-6-1970	15-6-1971	Industrial Research Corporation, B-44, Industrial Estate, Rajajinagar, Yashwan- pur.	Dye-based fountain pen ink (blue and red) IS: 221-1957

52	CM/L-1132 27-8-1965	1-6-1970	31-5-1970	All India Medical Corporation, Simpoli Road, Borivli West, Bombay-66.	Organo mercurial seed dressing formulations— IS:3284—1965.
53	CM/L-1223 9-3-1966	16-6-1970	15-12-1970	Calcutta Plywood Mfg. Co., P.O. Ledo, Distt. Lakhimpur (Assam)	Tea-chest plywood panels— IS: 10—1964
54	CM/L-1262 20-5-1966	16-6-1970	15-12-1970	Pesticides, India Udaisagar Road, Udaipur	Aldrin dusting powder— IS:1308—1958
55	CM/L-1264 23-5-1966	1-6-1970	31-5-1971	Hooseini Metal Rolling Mill Pvt Ltd. Tambawala Properties, Reay Road, Bombay-10.	Lead sheet for use in chemical industry— IS 405—1961
56	CM/L-1269 30-5-1966	1-6-1970	31-5-1971	Naveen Industries, C-82 Rawari Line, Industrial Area, (Mayapur) Phase, II New Delhi-27.	Plastic water-closet seat and covers phenolic, type 'A'— IS:2548—1967
57	CM/L-1272 31-5-1966	16-6-1970	15-12-1970	Kisan Chemicals, 127, Industrial Area, Chandigarh.	Dieldrin emulsifiable concentrates— IS: 1054—1962
58	CM/L-1275 31-5-1966	16-6-1970	15-6-1971	Mysore Insecticides Co. (Andhra) Tadepalli, Guntur Distt.	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310—1958
59	CM/L-1279 10-6-1966	16-6-1970	15-6-1971	Prakash Pulverising Mills, Industrial Area, Alwar.	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310—1958
60	CM/L-1280 10-6-1966	16-6-1970	15-6-1971	Do.	DDT dusting powders— IS: 564—1961
61	CM/L-1283 23-6-1966	1-7-1970	15-7-1971	The Omega Insulated Cable Co., India Ltd., Plot 16 and 17 Industrial Estate, Ambattur, Madras-58.	Hard drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS:398—1961
62	CM/L-1287 28-6-1966	1-7-1970	30-6-1971	S. R. Sharm & Sons., 140, Rai Bahadur R.N. Guha Road, Dum Dum, Calcutta-28.	Sand cast brass crew down bib taps— IS:781—1967
63	CM/L-1290 30-6-1966	1-7-1970	30-6-1971	E. I. D. Parry Ltd. Ranipet North Arcot Distt. (Tamil Nadu).	Malathion, emulsifiable concentrates— IS:2567—1963
64	CM/L-1292 30-6-1966	16-6-1970	15-6-1971	Industrial Research Corporation, B-44 Industrial Estate, Rajajinagar, Yashwantpur.	Ferro-galo tannate fountain pen ink— (0.1 percent iron content)— IS:220—1959
65	CM/L-132 30-9-1966	1-6-1970	13-12-1970	Swan (India) Pvt. Ltd., 2/1, Mile, Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad.	Dye-based fountain pen ink (green, black, blue and red)— IS: 1221—1957
66	CM/L-1369 16-12-1966	16-6-1970	15-6-1971	The Western India Plywoods Ltd., P. O. Bapatnam, Cannanore Distt. (Kerala State).	(i) Medium strength aircraft plywood— IS: 709—1957 (ii) Marine plywood— IS: 710—1957
67	CM/L-1434 26-4-1967	1-5-1970	30-4-1971	Hindustan Brown Boveri Ltd., Kot Village, Ghaziabad (U.P.)	Hard drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS: 398—1961

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	CM/L 1442 16-5-1967	16-5-1970	15-12-1970	Pesticides India, Udaisagar Road, Udaipur	Dieldrin emulsifiable concentrates— IS: 1054—1962
69	CM/L-1443 16-5-1967	16-5-1970	15-12-1970	Do.	Aldrin emulsifiable concentrates IS: 1307—1958
70	CM/L 1451 8-6-1967	16-6-1970	15-6-1971	Excel Industries Ltd, Excel Estate, S. V. Road, Goregaon, Bombay—62.	Stabilised methoxy ethyl mercury chloride concentrate IS: 2127—1962
71	CM/L-1452 8-6-1967	16-6-1970	15-6-1971	Do.	Formulations based on stabilised methoxy ethyl mercury chloride concentrates— IS: 2358—1963
72	CM/L-1453 8-6-1967	16-6-1970	15-6-1971	Do.	Organo mercurial seed dressings— IS: 3284—1965
73	CM/L-1455 12-6-1967	16-6-1970	15-6-1971	Bengal United Co Pvt Ltd., Brojonath Lahiri Lane, P.O. Santragachi, Howrah.	(i) Sluice valves for waterworks purposes (with non-ferrous spindles & rings), class I, upto 300 mm sizes— IS: 780—1967 (ii) Sluice valves for waterworks purposes, class I, double flange, 500 mm size— IS: 2906—1964 and (iii) Sluice valves for waterworks purposes, class II double flange, 400 to 500 mm 600 mm and 750 mm sizes— IS: 2906—1964
74	CM/L-1459 15-6-1967	1-7-1970	31-6-1971	Andhra Industrial Works, C-2 Industrial Estate, Cuddaph (AP)	Hard-drawn stranded aluminium and steel-cord aluminium conductors for overhead power transmission purposes. IS: 398—1961
75	CM/L 1461 16-6-1967	16-6-1970	15-2-1971	Tata Fison Industries Ltd, Plot No. 49 Industrial Estate, Ambattur, Madras—58	BHC dusting powders— IS: 561—1962
76	CM/L-1462 16-6-1967	16-6-1970	31-3-1971	Mohatta & Hecker Ltd, Khopali Sheelphara Distt. Kolaba, Maharashtra	(i) Steel wire ropes for winding purposes in mines— IS: 1855—1961 (ii) Steel wire ropes for haulage purposes in mines— IS: 1856—1961
77	CM/L-1463 16-6-1967	16-5-1970	15-11-1970	Grandlay Electricals (India) Military Prade Road, Nirankari Colony, Delhi	Weatherproof polythene insulated, taped, braided and compounded cables with aluminium conductors of following types; (i) Single core, 650/1100 volts Grade and (ii) Twin core, flat, 250/440 volts Grade] IS: 3035 (Part II) 1965

78	CM/L-1464 20-6-1967	1-7-1970	30-6-1971	Mohan Aluminium Private Ltd. Near 9th Milestone, Old Madras, Road, Post Bag No. 13 Bangalore-16	Hard-drawn stranded aluminium and steel-cord aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS: 398—1961
79	CM/L-1467 26-6-1967	1-7-1970	30-6-1971	The India Cements Ltd, Sankarnagar P.O. Trunelveli Distt. (Tamil Nadu)	Port land-pozzolana cement— IS: 1489—1967
80	CM/L-1551 24-10-1967	1-7-1970	31-12-1970	Mahabir Steel Rolling Mills, Qabool Nagar, G.T. Road, Shahdara, Delhi-32	Rolled steel sections, F. 4B, F 7B, F 5, F 8 and F 6 for doors, windows, and ventilators— IS: 1038—1968
81	CM/L-1567 24-11-1967	16-6-1970	15-12-1970	Keen Pesticides (Pvt.) Ltd, Vazhakulam, (Via Alwaye)	DDT water dispersible powders— IS: 565—1961
82	CM/L-1568 24-11-1967	1-6-1970	31-5-1971	Prakash Insecticides Pvt Ltd P. O. Naini Distt. Allahabad (U.P.)	BHC dusting powders— IS: 561—1962
83	CM/L-1583 13-12-1967	16-6-1970	15-6-1971	Rattanchand Harjasrai (Mouldings) Pvt Ltd, 54, Industrial Area, Faridabad.	Water-closet seats and covers made out of phenolic plastics or urea-formaldehyde, Type 'A' IS: 2548—1967.
84	CM/L-1649 8-3-1968	16-3-1970	15-3-1971	Agarwal Hardware Works (Pvt. Ltd.), 29, Ishwar Chatterjee Road, Sodepur, 24 Parganas.	Cold twisted steel bars for concrete reinforcement IS: 1786—1966
85	CM/L-1661 27-3-1968	1-4-1970	31-3-1971	Chaliha Rolling Mills Pvt. Ltd, 13 Chanditola Lane, Tollygunge, Calcutta-40	Structural steel (ordinary quality)— IS: 1977—1969
86	CM/L-1693 30-5-1968	16-5-1970	15-5-1971	Prakash Pulverising Mills, Industrial Area, Alwar (Rajasthan)	Aldrin emulsifiable concentrates— IS: 1307—1958
87	CM/L-1695 14-5-1968	1-6-1970	15-2-1971	Ankar Industries, Jessore Road, P. O. Mahyagram, 24 Parganas.	BH water dispersible powder concentrates— IS: 562—1962
88	CM/L-1696 16-5-1968	16-5-1970	15-5-1971	G. & H Shaw (Pvt Ltd, Icnnapur Road, Dasnagar, Howrah	Structural steel (standard quality)— IS: 226—1969
89	CM/L-1697 16-5-1968	16-5-1970	15-5-1971	Do.	Structural steel (ordinary quality)— IS: 1977—1969
90	CM/L-1702 22-5-1968	1-6-1970	31-12-1970	Mahendra Electricals Ltd, Kamal Mission Road, Nadiad, W. Rly.	Hard-drawn stranded aluminium and steel-cord Aluminium conductors for overhead powder transmission purposes— IS: 398—1961
91	CM/L-1705 31-5-1968	1-6-1970	30-11-1970	Esso Standard Eastern Inc., Survey No. 24/3 A & B Chikkabiderakallu village, Neelamangala Taluka, Bangalore—Tumkur Road, Bangalore Distt.	Malathion emulsifiable concentrates— IS: 2567—1963
92	CM/L-1707 31-5-1968	1-6-1970	15-11-1970	The Aluminium Industries Ltd, Ramachandrapuram, Hyderabad—32	Hard-drawn stranded aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS: 398—1961
93	CM/L-1713 6-6-1968	16-6-1970	15-6-1971	Bharat Steel Tubes Ltd, Ganaur Distt. Rohtak (Haryana)	Mild steel tubes— IS: 1239 (Part I) 1966

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	CM/L-1714 11-6-1968	16-6-1970	15-6-1971	Timber & Plywood Co (Pvt) Ltd, No. 1, Nimak Mahal Road, Kidderpore, Calcutta	Tea-chest metal fittings— IS:10—1964
95	CM/L-1721 13-6-1968	16-6-1970	15-12-1971	Standard Mineral Product Pvt Ltd, Subhas Nagar, Jogeshwari (East), Bombay-60	BHC water dispersible powder— IS:562—1962
96	CM/L-1727 24-6-1968	16-6-1970	15-6-1971	P. K. Venu & Co. Pvt Ltd, Agra Road, Naupada, Thana	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310—1958
97	CM/L-1728 25-6-1968	1-7-1970	31-3-1971	The Indian Steel Rolling Mills Ltd, Main Road, Tiruninsavur, (Chingleput Distt)	Hot rolled mild steel medium tensile and high yield strength steel deformed bars for concrete reinforcement— IS: 1139—1966
98	CM/L-1753 23-7-1968	1-5-1970	30-4-1971	Ram Chander Heera Lal, 62 College Ghat Road, Shalimar Howrah	Structural steel (standard quality) IS: 226—1969
99	CM/L-1754 23-7-1968	1-5-1970	30-4-1971	Do.	Structural steel (ordinary quality) IS: 1977—1969
100	CM/L-1755 23-7-1968	1-5-1970	30-4-1971	Do.	Rivet bars for structural purposes— IS: 1148—1964
101	CM/L-1757 29-7-1968	1-7-1970	30-6-1971	E. I. D. Parry Ltd, Ranipet, North Arcot Distt.	DDT emulsifiable concentrates— IS: 633—1956
102	CM/L-1848 29-11-1968	16-6-1970	15-6-1971	Haryana Conductors (Pvt) Ltd, 16/4 Mile stone, Mathura Road, Faridabad, (Haryana)	Hard-drawn stranded aluminium and steel cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes— IS: 398 —1961
103	CM/L-1850 5-12-1968	1-6-1970	30-11-1971	Vishweshwar Chemical Industries Private Limited, Post Pen, Distt. Kolaba, (Maharashtra)	Malathion emulsifiable concentrates— IS:2567—1963
104	CM/L-1851 5-12-1968	1-6-1970	30-11-1970	Do.	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310—1958
105	CM/L-1962 30-4-1969	1-5-1970	30-4-1971	Engineering Cottage Industries, M. P. Oil Mills, Compounds, Gutaiya, Kanpur	(i) Steel toe-caps for miner's safety leather boots and shoes— IS: 1989—1967 and (ii) Steel toe-caps for safety rubber canvas boots for miners. IS: 3976—1967
106	CM/L-1966 7-5-1969	16-5-1970	15-5-1971	Met Industries, 166 Jessore Road, Calcutta—55	Wrought aluminium and aluminium alloy wires Grades—GIC, HG 9, NG 1 and NG 2 IS: 739—1966

107	CM/L-1970 16-5-1969	16-5-1970	15-10-1970	Bhagsons Paint Industries (I) 16-A, D. L. F. Industrial Area, Najafgarh Road New Delhi-15	(i) Distemper dry— IS: 427—1965 and (ii) Distemper oil emulsion— IS: 428—1963
108	CM/L-1972 21-5-1969	16-5-1970	15-5-1971	Woodcrafts Assam (Prop. Jayshere Tea & Industries Ltd, mariani (Assam)	Wooden flush door shutters (solid core type) with plywood face panels— IS: 2202 (Part I) 1966
109	CM/L-1974 22-5-1969	1-6-1970	31-5-1971	The Gwalior Forest Products, Ltd, Shib-puri (MP)	Cutch— IS: 3967—1967
110	CM/L-1976 22-5-1969	1-6-1970	30-11-1970	Zamindar Chemicals Industries 17 Industrial Estate, Rajpura	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310—1958
111	CM/L-1979 26-6-1969	1-6-1970	30-11-1970	Mayur Industries, Pimpalgaon Road, Yeotmal	Malathion emulsifiable concentrates— IS: 2567—1963
112	CM/L-1981 29-5-1969	1-6-1970	31-5-1971	Hindustan Gum & Chemicals Ltd. Birla Colony, Bhiwani (Haryana)	Guar gum, Grade 2 (Powder)— IS: 3988—1967
113	CM/L-1984 30-5-1969	1-6-1970	31-5-1971	Srinivasa Pulverising Mills, F-6, Assisted Pvt. Industrial Estate, Chittor (AP)	BHC water dispersible powder— IS: 562—1962
114	CM/L-1987 11-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	Industrial Minerals & Chemicals Co Pvt Ltd, Kurla Marol Road, Chakala, Andheri, Bombay-58	Aldrin dusting powders— IS: 1308—1958
115	CM/L-1988 12-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	Universal Copper & Steel Rolling Mills, Near Kotharia v Station, Rajkot	Structural steel (standard quality)— IS: 226—1969
116	CM/L-1989 12-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	Do.	Structural steel (ordinary quality)— IS: 1977—1969
117	CM/L-1990 13-6-1968	16-6-1970	15-12-1970	Esso Standard Easter Inc., Survey No 24/3 A & B, Chikkabiderakullu Village, Neelamangala Taluka, Bangalore—Tumkur—road, Bangalore Distt.	Endrin emulsifiable concentrates— IS: 1310—1958 -
118	CM/L-1991 16-6-1969	16-6-1970	15-6-1971	J. B. Norton & Sons, Ltd, 89, 'O' Road, Belgachia, Howrah	Cast iron flushing cistern, high level, bell type 12.5 litre capacity— IS: 774—1964
119	CM/L-1999 30-6-1969	1-7-1970	30-6-1971	N. I. Industries (P) Ltd, 21 H/7, Cana West Road, Calcutta—6	Tea-chest metal fittings— IS: 10—1964

[No. CMD/13:112]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1763.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन मुहर) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि जिन एक सौ उन्नीस लाइसेंसों के व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे नए फिर किए गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	दिनांक	वैधता की अवधि से	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया तत्सम्बन्धी भारतीय मानक पदनाम	ओर IS:
1	2	3	4	5	6	

1. सी एस / एल-10 16-6-1970 15-6-1971 जीवनलाल (1929) लि०, फ़ाउन पिटवां एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रघातु के बर्तन —
11-6-1956 एल्युमिनियम वर्क्स, 26, परेल
टैंक रोड, बम्बई-12 IS: 21-1959

2. सी एस / एल-11 16-6-1970 15-6-1971 जीवनलाल (1929) लि०, फ़ाउन (1) पिटवां एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र घातु के बर्तन —
11-6-1956 एल्युमिनियम वर्क्स, 95, ग्रैंड ट्रंक रोड, डाकघर बेलूरमठ, जिला हावड़ा IS: 21-1959

(2) पिटवां एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र घातु के बर्तन, ग्रैंड एस आई सी एनोडीकृत—

IS: 1868-1968

3. सी एम / एल-27
20-5-1957 1-6-1970 31-5-1970 इलेक्ट्रिकल मैन्फैक्चरिंग कं. लि०, शिरोपरि पावल प्रेषण कार्यों के लिए सस्त
ई एम सी गार्डेन, 136, जेसोर खिचे लड़दार एल्युमिनियम और
रोड, कलकत्ता-55 इस्पात की और कोर बोले एल्युमिनियम
चालक --
IS: 398-1961
4. सी एम / एल-30
1-17-1957 16-7-1970 30-6-1973 दि इण्डिया सीमेन्ट लि०, शंकरनगर, साधारण और शीघ्र कठोरकारी पोर्टलैंड
तालैयूतु, जिला तिश्तेल्वली । सीमेन्ट--
IS: 269-1967
5. सी एम / एल-88
22-5-1958 1-6-1970 30-4-1971 हिन्दुस्तान ब्राउन बावरी लि०, इस्पात प्रबलित एल्युमिनियम चालक और
इंडस्ट्रियल एरिया, न्यु टाउन - सम्पूर्ण एल्युमिनियम चालक --
शिप फरीदाबाद (हरयाणा) । IS: 398-1961
6. सी एम / एल-132
24-6-1959 1-7-1970 30-6-1971 ई आई डी परी लि०, डेयरहाउस, डी डी डी घूल पाउडर --
मन्नास-1 । IS: 564-1961
7. सी एम / एल-190
25-5-1960 1-6-1970 31-5-1971 दि इंडिया टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन बरोजा (गोंद बरोजा) --
कं. लि०, डाक घर कलटखकगंज, IS: 553-1955
बरेली (उ० प्र०) ।
8. सी एम / एल-195
30-5-1960 16-6-1970 15-12-1970 वेस्टर्न इंडिया प्लाइवुड लि० बलि- सामान्य कार्यों के लिए प्लाईवुड --
यापाधम, कन्नूर जिला (केरल) IS: 303-1960
9. सी एम / एल-268
30-1-1961 1-6-1970 31-5-1971 आल इंडिया मेडिकल कार्पोरेशन, बी एच सी जल विसर्जनीय चूर्ण --
मूलजी जेटा विल्डिंग, 185, IS: 562-1962
प्रिसेस स्ट्रीट, बम्बई-2
10. सी एम / एल-285
28-3-1961 1-6-1970 31-5-1971 बी एच सी घूलन पाउडर --
IS: 561-1962

1	2	3	4	5	6
11.	सी एम / एल-299 28-4-1961	16-5-1970	15-5-1971	जे बी मंथाराम एण्ड कं० प्रा० लि०, बिस्कुट — पो० ब० रेबीडेन्सी, ग्वालियर IS: 10-11-1968	18—लीटर चौकोर डिब्बे — IS : 916—1966
12.	सी एम / एल-300 28-4-1961	16-5-1970	15-5-1971	न्यु दिग्विजय सिंह जी टिन फैक्ट्री, ग्रेन मार्केट, जामनगर ।	अप्रबलित लहसुदार एक्वेस्टांस सीमेण्ट क्री चद्वरे (अर्थलहरदार सहित) — IS: 459—1962
13.	सी एम / एल-315 26-6-1961	1-7-1970	30-6-1971	रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर, (बिहार) ।	एच सी टाइप फ्यूज बेस और कॅरियर सहित घातु के ढक्कन वाले स्विच, 15 प्रम्पी 250 वो— IS: 4064—1967
14.	सी एम / एल -338 1-9-1961	16-6-1970	15-12-1970	इंडो-एशिया ट्रेडर्स, प्रा० लि०, नको- दर रोड, जलंधर सिटी ।	एच सी घुलन पाउडर— 18/257, गांधी नगर, पो० ब० IS: 561—1962 425, विजयवाड़ा-3
15.	सी एम / एल-341 20-9-1961	16-6-1970	15-6-1971	मैसूर इंसेक्टीसाइस कं० (आंध्र), बी एच सी घुलन पाउडर— 18/257, गांधी नगर, पो० ब० IS: 561—1962 425, विजयवाड़ा-3	आल इंडिया मैडिकल कार्पोरेशन, डी डी टी जलविसर्जनीय तेज चुर्ण— मुलबी जठा विहिड्य, 185, प्रिंसिपल स्ट्रीट, बम्बई-2
16.	सी एम / एल-342 20-9-1961	1-6-1970	31-5-1971	आल इंडिया मैडिकल कार्पोरेशन, डी डी टी जलविसर्जनीय तेज चुर्ण— मुलबी जठा विहिड्य, 185, प्रिंसिपल स्ट्रीट, बम्बई-2	आल इंडिया मैडिकल कार्पोरेशन, डी डी टी जलविसर्जनीय तेज चुर्ण— मुलबी जठा विहिड्य, 185, प्रिंसिपल स्ट्रीट, बम्बई-2
17.	सी एम / एल-375 12-1-1962	16-6-1970	15-6-1971	बालगोपालदास आयरन एण्ड स्टील कं० प्रा० लि०, 5, गोपाल डाक्टर रोड, बिदिरपुर, कलकत्ता-23	18—लीटर चौकोर डिब्बे — IS: 916—1966

18 सी एम / एल—413 5-5-1962	16-5-1970	15-1-1971	देवीदयाल केवल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, टाइट पोखरन रोड, माहीवाड़ा यांव, बाला (महाराष्ट्र)	बो० ग्रह	बालक
			(क) अचलवायरिंग के लिए की आई और केवल		
			(1) सख्त रबड़ खोल वाले		
			(टी और एस) 250/440		
			(2) बड़े और सहमिलित	650/1100 बो०	तांबा या एल्यू- मिनियम
			(3) ऋतुसह	250/440 बो०	
			(4) लो मंदक	250/440 और 650/1100 बो०	
			(5) ऋतुसह	650/1100	(केवल बो०) एल्यूमि- नियम

1	2	3	4	5	6
					(ब) वी आई आर नम्य केवल ।
					(6) वॉलिंग केवल — तांबा केवल
					(ग) वी आई आर नम्य डोरियां
					(7) सक्ता रबड़बोल वाली 250/440 केवल तांबा (टी आर एस)
19	सी एम / एल—535 30-4-1963	1-6-1970	30-6-1971	पावर केवल प्रा० लि० विट्ठल- वाड़ी (महाराष्ट्र)	434 (भाग 1 और 2) —1964. केवल एल्यूमिनियम चालकों वाले पी वी सी केवल, 250 और 650 बो ग्रै— 694 (भाग 2)—1964
20	सी एम / एल—539 13-5-1963	16-6-1970	30-9-1971	टाटा फायरान इंडस्ट्रीज लि० 20 सी ओ सी जल विसर्जनीय तेज बूर्ण— हावड़ा रोड, सत्किया कलकत्ता IS: 1507—1966	
21	सी एम / एल—546 5-6-1963	1-6-1970	30-11-1970	वरेट टिम्बर ग्रुपस (प्रा०) माकस बाय फ्री फेटियों के लिए प्लाइवूड के तख्ते— रोड, तिनसुकिया, असम IS: 10—1964	
22	सी एम / एल—582 19-9-1963	16-10-1969	15-10-1970	कमानी ट्युब प्रा० लि० आगरा रोड, निम्नलिखित नाप की फ्री कटिंग, पीतल की छड़ें और सेवजल : कुरला बम्बई-70 गोल : 6.0 मिमी से 40 मिमी तक सभी नाप	
					षष्ठभुज : 10.0 मिमी से 40 मिमी ए एफ तक के सभी नाप

वर्गीकरण : 12.0 मिमी से 25 मिमी तक के सभी नाप		ग्रह : सी यु जड एम 42 पी बी 3 डी IS: 319—1968	
23	सी एम / एल—611 31-12-1963	16-6-1970	15-6-1971
		प्रकाश पृथ्वराईजिंग मिल्स इंडस्ट्रियल एरिया अलवर	
24	सी एम / एल—656 29-4-1964	1-6-1970	31-5-1971
		टेसाइल स्टील लि० हीराबाग, विश्वमित्र रोड, बड़ौदा	
25	सी एम / एल—663 1-5-1964	1-6-1970	31-5-1971
		इंडस्ट्रियल केबल (इंडिया) लि० इंडस्ट्रियल एरिया राजपुरा पंजाब	
26	सी एम / एल—666 7-5-1964	16-6-1970	15-6-1971
		मकुन्द प्रायरल स्टील वर्क्स कुरला, बम्बई-70	
27	सी एम / एल—681 17-6-1964	1-7-1970	30-6-1961
		दि इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स लि० 'मिल विल्डिंग' पो० बा० 1 नागापत्तिनम, तंजौर जिला।	
28	सी एम / एल—682 17-6-1964	1-7-1970	30-6-1971
		..	
29	सी एम / एल—780 10-9-1964	1-7-1970	30-6-1971
		एस आर शर्मा एण्ड संस 140, राय बहादुर आर एनगुहा रोड, डम-डम, कलकत्ता-28	

पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट के लिए सादे सल्ट बिबे
इस्पात के तार —
IS: 1785 (भाग 1) — 1966
33 कि बो और उससे कम तक विजली की
सप्लाय के लिए एल्युमिनियम चालकों
वाले कागज रोधित सीसा के खोल
चढ़े केबल —
IS: 692—1965
संरचना इस्पात (साधारण किस्म) —
IS: 1977—1969
संरचना इस्पात (मानक किस्म) —
IS: 226—1969
संरचना इस्पात (साधारण किस्म) —
IS: 1977—1969
प्रेस बाल वाल, (क्षैतिजप्लंबर मुमा) 15
मिमी नाप—
IS: 1703—1968

1	2	3	4	5	6
30	सी एम / एल—801 20-10-1964	1-6-1970	31-5-1971	सैटेलाइट इंजीनियरिंग लि० हाक- घर मेज प्रोडक्ट्स काठवाड़ा, अहमदाबाद	प्रतिदीप्ति बत्तियों के स्टार्टर, 20/40/80 वाटरेटिंग — IS: 2215—1968
31	सी एम / एल—829 2-11-1964	16-6-1970	15-12-1970	नेशनल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन— 99/100 आगरा रोड, भांडूप बम्बई -78	संरचना इस्पात (मानक किस्म) — IS: 226—1969
32	सी एम / एल—830 2-11-1964	16-6-1970	15-12-1970	" "	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) — IS: 1977—1969
33	सी एम / एल—861 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	दि किन्नीसन जूट मि० क० लि० दीटा गढ़, 24 परगना	(1) पटसन हेसियन — IS: 2818—1964 और (2) हेसियन बोरे— IS: 3790—1966
34	सी एम / एल—862 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	दि किन्नीसन जूट मि० क० लि० दीटा गढ़, 24 परगना ।	पटसन सैक्किंग IS: 1943—1964 IS: 3668-1966 IS: 2566-1965 IS: 3750-1966 IS: 2874-1964 IS: 3751-1966 IS: 2875-1964 IS: 3794-1966 IS: 3667-1966
35	सी एम / एल—877 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	सामनगर जूट फैक्ट्री क० लि० भद्रेश्वर, दुमकी (कायलिय) 3, कलाइव रोड, कलकत्ता-1	(1) जूट हेसियन — IS: 2818—1964 और (2) हेसियन बोरे — IS: 3790—1966

36	सी एम / एल—879 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	पटसन हेसियन — IS : 1943-1964 IS : 3668-1966 IS : 2566-1965 IS : 3750-1966 IS : 2874-1964 IS : 3751-1966 IS : 3667-1966 IS : 3794-1966 IS : 2875-1964
37	सी एम / एल—881 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	विक्टोरिया जूट कं. लि. डाकघर तेलिनपाड़ा, हुगली जिला (1) पटसन हेसियन — IS : 2818-1964, और (2) हेसियन बोरे — IS : 3790-1966
38	सी एम / एल—882 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	विक्टोरिया जूट कं. लि. डाक- घर तेलिनपाड़ा, हुगली जिला पटसन सैकिंग — IS : 1943-1964 IS : 3668-1966 IS : 2566-1965 IS : 3750-1966 IS : 2874-1964 IS : 3751-1966 IS : 2875-1964 IS : 3794-1966 IS : 3667-1966
39	सी एम / एल—913 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	बाली जूट कं. लि. 2, स्कट- कर रोड, बाली, हावड़ा (1) पटसन हेसियन — IS : 2818-1964 और (2) हेसियन बोरे — IS : 3790-1966
40	सी एम / एल—914 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	बाली जूट कं. लि. 25, स्कट- का रोड, बाली, हावड़ा पटसन सैकिंग — IS : 1943-1964 IS : 3668-1966 IS : 266-1965 IS : 3750-1966 IS : 2874-1964 IS : 3751-1966

1	2	3	4	5	6
41	सी एम / एल-933 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	केल्विन जूट कं. लि०, टीटागढ़, 24 परगना	IS : 2875-1964 IS: 3794-1966 IS : 3667-1966 (1) पटसन हेसियन — IS: 2818-1964 और (2) हेसियन बोरे — IS: 3790-1966
42	सी एम / एल-936 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1970	केल्विन जूट कं. लि०, टीटागढ़, 24 परगना	पटसन सैकिंग— IS: 1943-1964 IS: 3668-1966 IS: 2566-1965 IS: 3750-1966 IS: 2874-1964 IS: 3751-1966 IS: 2875-1964 IS: 3794-1966 IS: 3667-1966
43	सी एम / एल —949 28-11-1964	1-6-1970	30-11-1979	श्री हनुमान जूट मिल, 76, जोगन्धनाथ मुकजी रोड, धुसुरी हावड़ा	(1) पटसन हेसियन — IS: 2818-1964, और (2) हेसियन बोरे — IS: 3790-1966
44	सी एम० / एल-950 23-11-1964	1-6-1960	30-11-1970	"	पटसन हेसियन — IS: 1943-1964 IS: 3668-1966 IS: 2566-1965 IS: 3750-1966 IS: 2874-1964 IS: 3751-1966 IS: 2875-1964 IS: 3794-1966 IS 3667-1966

- 45 सी एम / एल-957 1-6-1970 30-11-1970 प्रवर्तक जट मिल्स लि०, कमर हट्टी, (1) पटसन हेसियन
28-11-1964 बी टी रोड, 24-परगना IS: 2818-1964, और
(2) हेसियन बोरे —
IS: 3790-1966
- 46 सी एम / एल-958 1-6-1970 30-11-1970 प्रवर्तक जट मिल्स लि०, कमर हट्टी, पटसन सैकिंग —
28-11-1964 बी टी रोड, 24-परगना IS: 1943-1964 IS: 3668-1966
IS: 2566-1965 IS: 3750-1966
IS: 2874-1964 IS: 3751-1966
IS: 2875-1964 IS: 3794-1966
IS: 3667-1966
- 47 सी एम / एल-1036 1-7-1970 30-6-1971 आनन्द इंस्टीट्यूट्स 4/5 इलैया, एलिडन पायसनीय तेज चूण —
19-3-1965 मुदाली स्ट्रीट कोस्कोपेट, IS : 1310-1958
मद्रास -21
- 48 सी एम / एल-1068 16-5-1970 15-10-1970 भागसत्स पेंट इंडस्ट्रीज (इंडिया) (1) वार्निश, गोल्ड साइज —
18-5-1965 16-ए, डी एल एफ इंडस्ट्रि- IS: 198-1952
यल एरिया, नजफगढ़ रोड, (2) भीतर फिनिश देने की वार्निश—
नई दिल्ली-15 IS: 337-1952
(3) मिल्स की वार्निश—
IS: 240-1952, और
(4) फ्लैट पॉलिश—
IS: 348-1952—
- 49 सी एम / एल-1090 16-6-1970 15-6-1971 वस्त इंडिया स्टील कं० लि०, संरचना इस्पात (मानक किस्म) —
3-6-1958 चेरुवन्नूर फेरोक (केरल) IS: 226-1969

1	2	3	4	5	6
50	सी एम/एल-1031 3-6-1965	16-6-1970	15-6-1971	वेस्ट इंडिया स्टील कं० लि०, चेन्नन्नूर फेरीक (केरल) IS: 1977-1969	संरचना इत्यात (साधारण किस्म)
51	सी एम/एल-1114 28-7-1965	16-6-1970	15-6-1971	इंडस्ट्रियल रिसर्च कारपोरेशन, बी-44, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजाजीनगर, यशवन्तपुर IS : 1221-1957	रंजकों बनी फाउन्टेन पेन की स्याही, (नीली, ग्रीन लाल) —
52	सी एम/एल-1132 27-8-1965	1-6-1970	31-5-1971	आल इंडिया मेडिकल कारपोरेशन, सिमपोली रोड, बोहली पारा पश्चिम, पश्चिम बम्बई-66 IS: 3284-1965	बीजों में सूखा लगाए जाने वाला कार्बन यौगिक —
53	सी एम/एल-1223 9-3-1966	15-6-1970	15-12-1970	कलकत्ता प्लाईवुड मैयूफैक्चरिंग कं०, डाकघर लीडो, जिला लखीमपुर (असम) पेस्टीसाइड्स इंडिया, उदयसागर रोड, उदयपुर IS: 1308-1958	चाय के बस्तों के लिए प्लाईवुड के तख्ते —
54	सी एम/एल-1262 20-5-1965	1-6-1970	15-12-1970	पेस्टीसाइड्स इंडिया, उदयसागर रोड, उदयपुर	ऐलिड्रिन धूलन पाउडर —
55	सी एम/एल-1264 23-5-1966	1-6-1970	31-5-1971	हुसेनी मेटल रोलिंग मि० प्रा० लि०, तांबावाला, प्रोपर्टीज, रिए रोड, बम्बई-10	रसायनिक उद्योग के लिए सीसे के छर्रे —
56	सी एम/एल-1269 30-5-1966	1-6-1970	31-5-1971	नवीन इंडस्ट्रीज, सी-82, रेवाड़ी लाइन, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़	प्लास्टिक के डब्बू सी के फीनोली डक्कन, टाइप ए —
57	सी एम/एल-1227 31-5-1966	16-6-1970	15-12-1970	किसान केमिकल्स, 127, इंड- स्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़	डाइएलिड्रन पायसनीय तेज प्रव —

58	सी एम/एल-1275 31-5-1966	16-6-1970	15-6-1971	मैसूर इंसेटीसाइड कं० (आन्ध्र) टाडेपल्ली, गुंटूर जिला	एन्ड्रिन का पायसनीय तेज द्रव— IS: 1310-1958
59	सी एम/एल-1279 10-6-1966	16-6-1970	15-6-1971	प्रकाश पल्ल राइजिंग मिल्स, इंड- स्ट्रियल एरिया, अलवर	एन्ड्रिन का पायसनीय तेज द्रव— IS: 1310-1958
60	सी एम/एल-1280 10-6-1966	16-6-1970	15-6-1971	"	डी डी टी घूलन पाउडर— IS: 564-1961
61	सी एम/एल-1283 23-6-1966	1-7-1970	15-7-1971	दि ओमेगा इंसुलेटड (कं०) इंडिया लि०, प्लाट 16 और 17, इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बटूर, मद्रास-58	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिए सख्त खिंचे लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चातक— IS: 398-1961
62	सी एल/एल-1287 28-6-1966	1-7-1970	30-6-1971	एस आर शर्मा एण्ड सन्स, 140, रायबहादुर आर एन गुहा रोड, डमडम, कलकत्ता-28	रेत ढली पीतल की घुमाकर खोली जाने वाली पानी की टोंटी— IS: 781-1967
63	सी एम/एल-1290 30-6-1966	1-7-1970	30-6-1971	ई आई डी पैरी लि०, रानीपेट, उत्तर अर्काट जिला (तमिल- नाडु)	मालाधियोन पायसनीय तेज द्रव— IS: 2567-1963
64	सी एम/एल-1292 30-6-1966	16-6-1970	15-6-1971	इंडस्ट्रियल रिसर्च कारपोरेशन, बी-44, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजाजीनगर, यशवन्तपुर	फेरोमैलो डैनेट फाउंटेन पेन की स्पाइयो (0.1 प्रतिशत लोहा युक्त)— IS: 220-1959
65	सी एम/एल-1342 30-9-1966	1-6-1970	31-12-1970	स्वान (इंडिया) प्रा० लि०, 12/1 मील, मथुरा रोड, डाकघर अमरनगर, फरीदाबाद	रंजकों से बनी फाउंटेन पेन की स्पाइ (नीली, हरी, लाल और काली)— IS: 1221-1957

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66	सी एम/एल-1369 11-12-1966	16-6-1970	15-6-1971	दि वैस्टर्न इंडिया प्लाइवुड लि०, बालियापाटम, कन्नूर जिला (केरल राज्य)	1) मध्यम सामर्थ्य वाली वायुयानों की प्लाईवुड IS: 709-1957 2) समुद्री प्लाईवुड IS: 710-1957
67	सी एम/एल-1434 26-4- 1967	1-5-1970	30-4-1971	हिन्दुस्तान ब्राउन बोवरी लि० कोटा गांव, गाजियाबाद (उ० प्र०)	मिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिए सल्ट बिचे लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक IS: 398-1961
68	सी एम/एल-1442 16-5 1967	16-5-1970	15-12-1970	पेस्टीसाइड्स इंडिया, उदयसागर रोड, उदयपुर	एल्ट्रिम का पायसनीय तेज द्रव- IS: 1307-1958
69	सी एम/एल-1443 16-5 1967	16-5-1970	15-12-1970	" "	एल्ट्रिम का पायसनीय तेज द्रव IS 1307-1958
70	सी एम/एल 1451 8-6 1967	16-6-1970	15-6-1971	एक्सेल इंडस्ट्रीज लि० एक्सेल स्टेट एस वी रोड गोरगांव, बम्बई- 62	स्थिरीकृत मेथाक्सी इथाइल पारा क्लो, राइड का तेज द्रव IS: 2127-1962
71	सी एम/एल 1452 8-6- 1967	16-6-1970	15-6-1971	"	मिथाइक्सी इथाइल पारा क्लोराइड के तेज द्रव से बने योगिक IS: 2358-1963
72	सी एम/एल-1453 8-6 1967	16-6-1970	15-6-1971	"	बोनों में लगाने के कार्बनिक के पदार्थ पारे के पदार्थ IS: 3284-1965

73	सी एम/एल-1455 12-6-1967	16-6-1970	15-6-1971	बंगाल यूनाइटेड कं० प्र० लि० ब्रजनाथ लहिड़ी लेन डाकघर संतरागची हावड़ा	1) जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व (अलौहिक स्पिडल और छल्ले वाले) क्षेत्र 1,300 मिमी नाप तक के IS: 780-1967 2) जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व (अलौहिक स्पिडल और छल्ले वाले) क्षेत्री 1,300 मिमी नाप तक के IS: 2906-1964, और 3) जलकल कार्यों के लिए स्लूस वाल्व क्षेत्री 2, डुहरे कोर वाले, 400 से 500 मिमी 600 मिमी और 750 मिमी नाप वाले IS : 2906-1964
74	सी एम/एल 1459 15-6-1967	1-7-1970	30-6-1971	आनंद इंडस्ट्रियल वर्क्स, सी-2 इंडस्ट्रियल इस्टेट कूड्डपा (आनंद)	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सहा बिंबे लडवार, एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम बालक- IS: 398-1961
75	सी एम/एल-1461 16-6-1967	16-6-1970	15-2-1971	टाटा फायसन इंडस्ट्रियल लि० ज्वाट नं० 94 इंडस्ट्रियल इस्टेट अम्बटूर, मद्रास-58	बी एच सी धूलन पाउडर IS: 561-1962

1	2	3	4	5	6
76	सी एम/एल 1462 16-6 1967	16-6-1970	31-3-1971	मोहंटा एण्ड हेकेल लि० खोपली, सीलफाटा, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र	1) खानों में वाइडिंग कार्यों के लिए तार के रस्से IS : 1855-1961 2) खानों में वाइडिंग कार्यों के लिए तार के रस्से IS : 1856-1961
77	सी एम/एल-1463 16-6 1967	16-5-1970	15-11-1970	ग्रेडले इलेक्ट्रिकल लि० (इंडिया) मिलिटरी परेड रोड, निरकारी कालोनी, दिल्ली	एल्युमिनियम चालकों वाले ऋतुसह्य पोलिब थीन रोडित टेप लगे ब्रेडेड और सह्य मिलित केवल, निम्न प्रकार के 1) एकहरे कोर, 650/1100 ो ग्रेड 2) दोहरे कोर वाले, चपटे, 250/440 वो ग्रेड IS : 3035 (भाग 2) 1965
78	सी एम/एल-1464 20-6 1967	1-7-1970	30-6-1971	मोहन एल्युमिनियम प्रा० लि० निकट नर्वामील ओल्ड मद्रास रोड पो० ब०-13 वंगलौर-16	शिरोपरि पावर प्रेषण का रों के लिए सख्त खिचे लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक IS : 398-1961
79	सी एम/एल-1467 26-6 1967	1-7-1970	30-6-1971	दि इंडिया सीमेण्ट लि० संकरनगर डाकघर तिरुनेल्वली जिला (तमिलनाडु)	पोर्टलैंड पोत्सोलाना सीमेण्ट IS : 1489-1967

80	सी एम/एल-1551 24-10-1967	1-7-1970	31-12-1970	महावीर स्टील रोलिंग मिल्स काबूल, नमर, जीटी रोड शहादरा रोड, दिल्ली-32	दवाओं खिड़कियों और रोखतदानों के लिए गेल्ड इस्पात के सेक्शन, एक 4 बी, एक 7 बी, एक 5, एक 8 और एक 6
					IS: 1038-1968
81	सी एम/एल-1567 24-11-1967	16-6-1970	15-12-1970	कीन पेस्ट्रीसाइड्स (प्रा०) लि० बलाकुलम अल्वाय	डी डी टी जल विसर्जनीय पाउडर
					IS: 565-1961
82	सी एम/एल-1568	1-6-1970	31-5-1971	प्रकाश इलेक्ट्रीसाइड्स प्रा० लि० डाकघर तैनी जिला इलाहाबाद (उ० प्र०)	बी एच सी धूलन पाउडर
					IS: 561-1962
83	सी एम/एल-1583 13-12-1967	16-6-1970	15-6-1971	रतनचन्द हरजस राय (मॉलिङ-गज) प्रा० लि० 54, इंडास्ट्रियल एरिया फरीदाबाद	फेनीली प्लास्टिक या यूरिया फार्मिडिहाइड टाइप ए, के बने डब्लू सी सीट और डक्कन,
					IS: 2548-1967
84	सी एम/एल-1649 8-3-1968	16-3-1970	15-3-1971	अप्रवाल हाईवेयर वर्क्स (प्रा०) लि० 29, ईश्वर चटर्जी रोड सोदपुर, 24-परगना	कंक्रिट प्रबलन के लिए ठंडी मुड़ी इस्पात की सरिया
					IS: 1786-1966
85	सी एम/एल-1661 27-3-1968	1-4-1970	31-3-1971	बालिहा रोलिंग मिल्स प्रा० लि० 13, चंडीटोला लेन, टोलीनंज कलकत्ता-40	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)
					IS: 1997-1969
86	सी एम/एल-1693 30-5-1968	16-5-1970	15-5-1971	प्रकाश पल्वराइजिंग मिल्स, इंडास्ट्रियल एरिया, अलवर, राजस्थान 1	एल्टिन पायसनीय तेज द्रव
					IS: 1307-1958
87	सी एम/एल-1695 14-5-1968	1-6-1970	15-2-1971	अंकार इंडस्ट्रीज, जेसोर रोड, डाक घर मध्यम ग्राम, 24-परगना	बी एच सी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण
					IS: 562-1962

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88	सी एम/एल-1696 16-5-1968	16-5-1970	15-5-1971	जी एच एच शा (प्रा०) लि० इच्छापुर रोड, दासनगर हाबड़ा	संरचना इस्पात (मानक क्रिस्म) IS: 226-1969
89	सी एम/एल-1997 16-5-1968	16-5-1970	15-5-1971	"	संरचना इस्पात (साधारण क्रिस्म) IS: 1977-1969
90	सी एम/एल-1702 22-5-1968	1-6-1970	31-12-1970	महेन्द्र इलेक्ट्रिकल लि० कामला, मिशन रोड, नाडियाड, प० रेलवे	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिए सख्त विचित्र लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक IS: 398-1961
91	सी एम/एल-1705 31-5-1968	1-6-1970	30-11-1970	एसो स्टेड ईस्टर्न इका सर्वे न० 24/3 ए और बी चिक्काविदर-कल्लु गांव नीलमंगल तालुका बंगलौर-दुम्कुर रोड, बंगलौर जिला	मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव IS: 2567-1963
92	सी एम/एल-1707 31-5-1968	1-6-1970	15-11-1970	दि एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज लि० रामचन्द्रपुरम, हैदराबाद-32	शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिए सख्त विचित्र लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात की कोर वाले एल्युमिनियम चालक IS: 398-1961
93	सी एम/एल-1713 6-6-1968	16-6-1970	15-6-1971	भारत स्टील ट्यूब लि०, गन्नीर जिला रोहतक (हरयाणा)	साधारण इस्पात की नलियां IS: 1239 (भाग 1)—1966
94	सी एम/एल-1714 11-6-1968	16-6-1970	15-6-1971	टिम्बर एण्ड प्लाइवुड क० (प्रा०) लि० न०-1 निमक महल रोड खिदपुर, कलकत्ता	चाय की भेटियों के घातु के फिटिंग IS: 10-1964

95	सी एम/एल-1721 13-6-1969	16-6-1970	15-12-1971	स्टैंडर्ड मिनरल प्रोटेक्ट प्रा० लि० मुम्बई, जोगेश्वरी (पूर्व) बम्बई - 60	बी एच सी विसर्जनीय पाउडर IS : 562-1962
96	सी एम/एल-1727 21-6-1968	16-6-1970	15-6-1971	पी के डेल्यू एन्ड कं० प्रा० लि०, आगरा रोड, नौदा थाना	एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव IS : 1310-1958
97	सी एम/एल-1728 23-7-1968	1-7-1970	31-3-1971	विडिगन स्टोल रॉयल पि० लि०, मेन रोड लिक्विस्तावर (चिंगलपेट जिला)	इस्पात की स्लैब तनाव वाली और उच्च पराभव सामर्थ्य वाली इस्पात की वित्त सरिया IS : 1139-1966
98	सी एम/एल-1753 23-7-1968	1-5-1970	30-4-1971	रामचन्द्र होरालाल 62 कालेज गेट रोड, शालीमार, हावड़ा	संरचना इस्पात (मानक क्रिस्म) IS : 228-1969
99	सी एम/एल-1755 23-7-1968	1-5-1970	30-4-1971	"	संरचना इस्पात (साधारण क्रिस्म) IS : 1977-1969
100	सी एम/एल-1755 23-7-1968	1-5-1970	30-4-1971	"	संरचना कार्यों के लिए रिबेडों की सरिया IS : 1148-1964
101	सी एम/एल-1757 29-7-1966	1-7-1970	30-6-1971	ई आइ डी री लि० रानोपेट, उत्तर आकांठ जिला	डी डी डी पायसनीय तेज द्रव IS : 633-1956
102	सी एम/एल-1848 29-11-1968	16-6-1970	15-6-1971	हरयाणा कंड टॉ (प्रा०) लि० 16/4 मील, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरयाणा)	क्रिओलिन पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त ब्रिच लड़दार एल्युमिनियम और इस्पात के कोर वाले एल्युमिनियम चालक IS : 398-1961

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
103	सी एम/एच-18 50 5-12-1968	1-6-1970	30-11-1970	विशेषकर कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि० ड. कवर पेन, जिला कोलबा (महाराष्ट्र)	मालाश्रित पायसनीय तेज द्रव IS : 2567-1963
104	सी एम/एल-18 51 5-12-1968	1-6-1970	30-11-1970	"	एलिइन पायसनीय तेज द्रव IS : 1310-1958
105	सी एम/एच-1962 30-6-1969	1-5-1970	30-4-1971	इजिनियरिंग काटेज इंडस्ट्रीज एम० पी तेन मिलस अहता, गुड ट्यूना, कानपुर	(1) छानिकों के चमड़े के बचाव बूट और जूते IS : 1989-1967 और (2) छानिकों के रबड़ के कैंवस के बूटों के इस्पात के टो-फैप IS : 3976-1967
106	सी एम/एल-1966 7-5-1969	16-5-1970	15-5-1971	मेट इंडस्ट्रीज, 166, जेओर रोड, कलकत्ता-55	पिटवा एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्रधातु के तार ब्रेड, जो आई सी, एच जी 9, एन जी 1 और एन जी 2 IS : 739-1966
107	सी एम/एल-1970 16-5-1969	16-5-1970	15-10-1970	भागसंस गेट इंडस्ट्रीज (आई) 16-ए, डी एल एफ इंडस्ट्रियल नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15	1) सूखा डिस्टम्पर IS : 427-1955, और 2) तेल पायसनीय डिस्टेंपर IS : 428-1963
108	सी एच/एच-1972 21-5-1969	16-5-1970	15-5-1971	बुडकापट असम (मालिक जयश्री टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि०) मरियानी (असम)	कार प्लाईवुड लगे हुए लकड़ी के दरवाजों के समतल कपाट (ओस मध्य भाग वाले) IS : 2202 (भाग 1)-1966

109	सी एम/एल-1974 22-5-1969	1-6-1970	31-5-1971	दि ग्वालियर फोरेस्ट प्राडक्ट्स लि० गिबपुरी (म० प्र)	कच्चा IS : 3967-1967
110	सी एम/एल-1976 22-5-1969	1-6-1970	30-11-1970	जमींदार केमिकल्स इंडस्ट्रीज 17 इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजपुरा	गन्निष्ठ पायसनीय तेज द्रव IS : 1310-1958
111	सी एम/एल-1979 26-6-1969	1-6-1970	30-11-1970	मयूर इंडस्ट्रीज पिपल गांव रोड येवतमाल	मालाधियोत पायसनीय तेज द्रव IS : 2567-1963
112	सी एम/एल-1981 29-5-1969	1-6-1970	31-5-1971	हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल लि० बिड़ला कालोती भिवानी (हर-याण I)	गुवार गोंद, ग्रेड 2 (बूरा) IS : 3988-1967
113	सी एम/एल-1984 30-5-1969	1-6-1970	31-5-1971	श्रीनिवासन पल्लवराईजिंग मिल्स एफ०-6, ग्रिसिस्टेड, प्रा० इंडस्ट्रियल इस्टेट चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)	बी एच सी जल विसर्जनीय तेज चूर्ण IS : 562-1962
114	सी एम/एल-1987 11-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	इंडस्ट्रियल मिनरल एण्ड केमिकल्स क० प्रा० लि० कुरला मरोल रोड, चकला, अंधेरी बम्बई 58	एल्ट्रिन धूलन पाउडर IS : 1308-1958
115	सी एम/एल-1988 12-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	यूनिवर्सल कापर एण्ड स्टील रो-लिंग मि० निकट कोठरिया रेलवे स्टेशन, राजकोट	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226-1969
116	सी एम/एल-1989 12-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	यूनिवर्सल कापर एण्ड स्टील रो-लिंग मिल निकट कोठरिया रेलवे स्टेशन, राजकोट	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1969

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117.	सी एम/एल-1900 13-6-1969	16-6-1970	15-12-1970	एसो स्टैंडर्ड्स सर्वे नं० 24/3 मालाथियोन पायसतीय तेज द्रव एम्रीरबी, चिक्कबिदरकल्लु गांव नीलमगलम तालुका बंगलौर-हुम्कुर रोड बंगलौर जिला	IS : 2567-1963
118.	सी एम/एल-1991 16-6-1969	16-6-1970	15-6-1971	जे बी नोर्टन एंड प्रंस लि० 89, 'ओ' रोड बेलगछिया हावड़ा	डलवा लोहे की ऊंचे पर लगने वाली घंटा-नुमा 12.5 लीटर समाई वाली प्लेन की टंकियां IS : 774-1964
119.	सी एम/एल-1999 30-6-1969	1-7-1970	30-6-1971	एन आई इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि० 21/एच/7, कैनेल ब्रैस्ट रोड कलकत्ता-6	चाग की पेटियों के धातु के फिटिंग IS : 10-1964

[सं० सी० एम० डी०/13:12.]

New Delhi, the 22nd April, 1971

S. O. 1754.—In pursuance of sub-regulation(3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for Carbon tetrachloride, details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1 April 1971:

THE SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Products	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1	2	3	4	
1.	Carbon tetrachloride, pure grade	IS: 718-1970 Specification for carbon tetrachloride	One tonne	Rs. 3.00

[No. CMD/13 : 1C]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

एन० प्रो० 1734--भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था को ओर से अधिपूचित किया जाता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रमाणन कोट जिसका नमूना नीचे अनुसूची में दिया है, निर्धारित की गई है और यह कोस 1 अप्रैल 1971 से लागू हो जाएगी।

अनुसूची


क्रमांक उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पसंख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	
1	2	3	4	5
1	कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुद्ध ग्रेड	IS: 783-1970 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मीटर की ब्रिगिटि	एक मीटर	रु० 3-00

एन० प्रो० एन० डी० 13/10]

S. O. 1765.—In pursuance of sub-rule () of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark design of which together with the usual descriptive and design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder shall come into force with effect from 1 April 1971.

THE SCHEDULE


Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
I.		Carbon tetrachloride, pure grade.	IS:718-1970 Specification for carbon tetrachloride	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side and the words 'PURE' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13:9

एस० आ० 1765—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955, के नियम 4 के उप नियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिष्ठाित किया जाता है कि मानक चिन्ह जिसकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दिया है, या संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है।

4 भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बनने नियमों के निमित्त यह मानक चिन्ह 1 अप्रैल, 1971 से लागू हो जाएगी।


अनुसूची

क्रमांक	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1		कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुद्ध ग्रेड	IS: 718-1970 कार्बन टेट्राक्लोराइड की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें IS शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गीली और अनुपात में तैयार किया गया है, और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के उपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है और शब्द 'Pure' मोनोग्राम के नीचे की ओर दिया हुआ है।

S. O. 1766.—In partial modification of the then Ministry of Commerce and Industry (Indian Standards Institution) Notification No. 207, dated 18 February, 1958 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 15 March, 1958, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark for Copper sulphate, has been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the Schedule hereto annexed.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1956, shall come into force with effect from the date of publication of this notification.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1.		Copper sulphate IS:261-1966 Specification for copper sulphate	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number designation of the Indian Standard being superscribed on the top side and the words 'TECH' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.
----	---	---	---

[No. C/ D/ 3 : 9]


A. K. GUP. A.,

Deputy Director General.

एस० प्रो० 1766—भारतीय गजट के भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में 15 मार्च, 1958 को प्रकाशित तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग (भारतीय मानक-संस्था) अधिसूचना सं० 207, दिनांक 18 फरवरी, 1958 के आंशिक संशोधन के रूप में भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि ता प्रसुल्फेट के मानक-चिन्ह में परिवर्तन किया गया है। मानक चिन्ह की परिवर्तित डिजाइन अपने आंशिक विवरण और तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के निमित्त यह मानक चिन्ह 1 मई 1971 से लागू हो जाएगा :

प्रामाण्य

क्र०	मानक-चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक को पदपंक्ति और शीर्षक	मानक, चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1	2	3	4	5
1.		ताम्र सल्फेट	IS:261-1966 ताम्र सल्फेट को विशिष्ट	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें IS1 शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुगत में तैयार किया गया है, और जैसा दिखाया है उस मोनोग्राम के उपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी हुई है और मोनोग्राम के नीचे की ओर 'टेक' शब्द दिया हुआ है।

[संख्या सी० एम० डी० 13:9]

ए० के० गुप्ता,
उपमहानिदेशक ।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 22nd December 1970

S.O. 1767.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of its earlier order No. 82 (F. No. 261/18/70-ITJ), dated the 19th May, 1970, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that in the Schedule annexed thereto in Serial I under Patna Range, Special Circle, Ward-C, Patna shall be added to item (vii) in column 3 thereof.

This Notification shall take effect from 14th December, 1970.

Explanatory Note

The modification has become necessary on account of the creation of new Ward namely Ward-C, Special Circle, Patna.

(The above note does not form a part of the modification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 197 (F. No. 261/18/70-ITJ.)]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1970

एस.ओ. 1767.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उद्देश्य निमित्त समाप्त बचाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 19 मई, 1970 के अपने पूर्ण आदेश सं. 82 (फा. सं. 261/18/70—अ ई. टी. जे.) को आंशिक रूप से उद्घाटित करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त आदेश से उद्घाटित अनुसूची में कम सं. 1 में पटना रेंज में, उसके स्तम्भ 3 के मद (7) में विशेष सर्किल, बार्ड-ग, पटना जोड़ा जाएगा।

यह उद्घाटन 14 दिसम्बर, 1970 से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण टिप्पण

यह उद्घाटन, बार्ड-ग, विशेष सर्किल, पटना नामक नए बार्ड के बन जाने के कारण आवश्यक हो गया है।

(उपरोक्त टिप्पण उद्घाटन का भाग नहीं है, बल्कि सांख्यिकीकरण मात्र के लिए आशयित है)

[सं. 197 (फा. सं. 261/18/70—अ ई. टी. जे.)]

S.O. 1768.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in succession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts, specified in the corresponding entry in column 3 thereof :—

Sl. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2	3
1. Range-I, Lucknow		1. Circle-I, Lucknow excluding :— (i) C-Ward, Circle-I, Lucknow. (ii) F-Ward, Circle-I, Lucknow. 2. Salary Circle, Lucknow. 3. Special Circle, Lucknow. 4. Lucknow. 5. Special Survey Circle, Lucknow. 6. Project Circle, Lucknow. 7. Hardoi.
2. Range-II, Lucknow		1. Circle-II, Lucknow (which existed upto 31-5-68 and from 1-8-68 to 1-6-69 and thereafter). 2. C-Ward, Circle-I, Lucknow. 3. F-Ward, Circle-I, Lucknow. 4. Company Circle, Lucknow. 5. Estate-duty and I.T. Circle, Lucknow. 6. Sitapur. 7. Lakhimpur-Kheri.

1	2	3
3.	Range-I, Varanasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. C-Ward, Varanasi. 2. E-Ward, Varanasi. 3. F-Ward, Varanasi. 4. Special Circle, Varanasi. 5. Jaunpur. 6. Azamgarh.
4.	Range-II, Varanasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varanasi Circle excluding :— <ol style="list-style-type: none"> (i) C-Ward, Varanasi. (ii) E-Ward, Varanasi. (iii) F-Ward, Varanasi. 2. Special Survey Circle, Varanasi. 3. Project Circle, Varanasi. 4. Ballia.
5.	Range-I, Allahabad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allahabad Circle excluding :— <ol style="list-style-type: none"> (i) B-Ward, Allahabad. (ii) F-Ward, Allahabad. (iii) I.T.O. (Collection). 2. Salary Circle, Allahabad. 3. Estate-Duty-Cum-I.T. Circle, Allahabad. 4. Faizabad. 5. Gonda.
6.	Range-II, Allahabad	<ol style="list-style-type: none"> 1. B-Ward, Allahabad. 2. F-Ward, Allahabad. 3. I.T.O. (Collection), Allahabad. 4. I.T.O. (Administration) & (Collection), Allahabad. 5. Mirzapur.
7.	Gorakhpur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gorakhpur. 2. Basti.
8.	Range-I, Bareilly	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bareilly Circle excluding :— <ol style="list-style-type: none"> (i) B-Ward, Bareilly. (ii) D-Ward, Bareilly. (iii) F-Ward, Bareilly. 2. Nainital. 3. Almora. 4. Haldwani.
9.	Range-II, Bareilly	<ol style="list-style-type: none"> 1. B-Ward, Bareilly. 2. D-Ward, Bareilly. 3. F-Ward, Bareilly. 4. Pilibhit. 5. Badaun. 6. Shahjahanpur.
10.	Range-I, Moradabad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moradabad Circle excluding :— <ol style="list-style-type: none"> (i) B-Ward, Moradabad. (ii) D-Ward, Moradabad. 2. Najibabad. 3. Kashipur.
11.	Range-II, Moradabad]	<ol style="list-style-type: none"> 1. B-Ward, Moradabad. 2. D-Ward, Moradabad. 3. Bulandshahr. 4. Rampur.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District thereof is transferred.

This notification shall take effect from 24 December/1970.

Explanatory Note

The amendments have become necessary for providing even work load to the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax at Allahabad and Gorakhpur and also to cover the creation of new wards and Circles.

[No. 198 (F. No. 281/7/70-ITJ).]

एस० न० 1768.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी हुई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अरील) उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्राविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सर्किलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आय कर सर्किल, वार्ड और जिले
1	2	3
1	रेंज-1, लखनऊ	1. सर्किल-1, लखनऊ, निम्नलिखित को अप-वर्जित करके— (i) ग-वार्ड, सर्किल-1, लखनऊ (ii) ग-वार्ड, सर्किल-1, लखनऊ 2. वतन सर्किल, लखनऊ 3. विशेष सर्किल, लखनऊ 4. लखनऊ 5. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, लखनऊ 6. परिषोजना सर्किल, लखनऊ 7. हरदोई
2	रेंज-2, लखनऊ	1. सर्किल-2, लखनऊ (जो 31-5-68 तक और 1-8-68 से 1-6-69 तक और तत्पश्चात् अस्तित्व में रहा) । 2. ग-वार्ड, सर्किल-1, लखनऊ 3. च-वार्ड, सर्किल-1, लखनऊ 4. कम्पनी सर्किल, लखनऊ 5. सम्पदा शुल्क-सह-आयकर सर्किल, लखनऊ 6. सीतापुर 7. लखीमगढ़ खेरी
3	रेंज-1, वाराणसी	1. ग-वार्ड, वाराणसी 2. ड-वार्ड, वाराणसी 3. ख-वार्ड, वाराणसी 4. विशेष सर्किल, वाराणसी 5. जौनपुर 6. आजमगढ़

1	2	3
4 रेंज-2, वाराणसी		1. वाराणसी सिकिल-निम्नलिखित को अप- वर्जित करके :— (i) ग-वाड़, वाराणसी (ii) ड-वाड़, वाराणसी (iii) च-वाड़, वाराणसी 2. विशेष सर्वेक्षण सिकिल, वाराणसी 3. परियोजना सिकिल, वाराणसी 4. बलिया
5 रेंज-1, इलाहाबाद		1. इलाहाबाद सिकिल, निम्नलिखित को अप- वर्जित करके :— (i) ख-वाड़, इलाहाबाद (ii) च-वाड़, इलाहाबाद (iii) आयकर अधिकारी (वसूली) 2. वेतन सिकिल, इलाहाबाद 3. सम्पदा-शुल्क-सह-आयकर सिकिल, इलाहा- बाद 4. फैजाबाद 5. गोंडा
6 रेंज-2 इलाहाबाद		1. ख-वाड़, इलाहाबाद 2. च-वाड़, इलाहाबाद 3. आयकर अधिकारी (वसूली), इलाहाबाद 4. आयकर अधिकारी (प्रशासन) और (वसूली), इलाहाबाद 5. मिर्जापुर
7 गोरखपुर		1. गोरखपुर 2. बस्ती
8 रेंज-1, बरेली		1. बरेली सिकिल, निम्नलिखित को अपवर्जित करके :— (i) ख-वाड़, बरेली (ii) घ-वाड़, बरेली (iii) च-वाड़ बरेली 2. नैनीताल 3. अलमोड़ा 4. इन्दौर
9 रेंज- बरेली		1. ख-वाड़, बरेली 2. घ-वाड़, बरेली

1	2	3
		3. च-वार्ड, बरेली 4. पीलीभीत 5. बदय 6. शाहजहंपुर
10	रेंज-1, मुरादाबाद . . .	1. मुरादाबाद सिकिल, निम्नलिखित को अप- वर्जित करके :— (i) ख-वार्ड, मुरादाबाद (ii) घ-वार्ड, मुरादाबाद 2. नजीबाबाद 3. काशीपुर
11	रेंज-2, मुरादाबाद . . .	1. ख-वार्ड, मुरादाबाद 2. घ-वार्ड, मुरादाबाद 3. बुलन्दशहर 4. रामपुर

जहाँ इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सिकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया हो वहाँ उस आयकर सिकिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई श्रृंखलाओं जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज, के जिससे वह आयकर सिकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सिकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जायगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 24-12-1970 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण

सहायक आयकर आयुक्त (अपील) इलाहाबाद और गोरखपुर को समान-कार्य भार देने और नये वार्डों तथा सिकिलों के बन जाने के कारण ये संशोधन आवश्यक हो गए हैं।

[सं० 198(फा० सं० 261/7/70-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 24th December 1970

S. O. 1769.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in super-session of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in Column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and

Income assessed to Income-tax or super-tax in the Income-tax, Wards, Circles and Districts specified in the corresponding entry in Column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range with Headquarters	Income-tax Circles, Wards and Districts
(1)	(2)
1. Gauhati Range-I	A-Ward, Addl. A-Ward, D-Ward, E-Ward and Special Wards of Gauhati Circle.
2. Gauhati Range-II	1. All Wards of Gauhati Circle 'excluding those allotted to Gauhati Range-I. 2. Nalbari Circle. 3. Agartala Circle.
3. Shillong Range	1. Shillong Circle. 2. Salary Circle, Shillong. 3. Special Circle, Shillong. 4. Nowgong Circle. 5. Silchar Circle. 6. Karimganj Circle. 7. Manipur Circle, Imphal.
4. Jorhat Range	1. Jorhat Circle. 2. Silsagar Circle. 3. Golaghat Circle.
5. Tezpur Range	1. Tezpur Circle. 2. Dhubri Circle.
6. Dibrugarh Range-I	1. A & B Wards of Dibrugarh Circle. 2. Dibsai Circle.
7. Dibrugarh Range-II	1. All Wards of Dibrugarh Circle excluding those in the jurisdiction of Dibrugarh-I Range-I. 2. I.T. cum Estate Duty Circle, Dibrugarh. 3. Salary Circle, Dibrugarh. 4. Tinsukia Circle.

Where an Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st January, 1971.

Explanatory Note

The amendments have become necessary on account of reallocation of Appellate Assistant Commissioners jurisdiction, abolition of Silchar Range and creation of Range II at Gauhati.

(The above note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 199 (F. No. 261/9/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1970

एत० ओ० 1769.—आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इन निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संघ में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों

के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिष्ट आय-कर वाडों, सकिलों और जिलों में आय-कर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय की बाबत में अपने कृत्यों का पालन करगे :—

अनुसूची

रेंज जिनका मुख्यालय निम्नलिखित है आय कर सकिल, वाड और जिले

- | | |
|---------------------|--|
| 1. गौहाटी रेंज-1 | क-वाड, अतिरिक्त क-वाड,
घ-वाड, डा०-वाड और गौहाटी सकिल के
विशेष वाड |
| 2. गौहाटी रेंज-2 | 1. गौहाटी रेंज-1 को आबंटित वाडों को अप-
वर्जित करके गौहाटी सकिल के सब वाड
2. नलबाड़ी सकिल
3. भगरतला सकिल |
| 3. शिलांग रेंज | 1. शिलांग सकिल
2. वेतन सकिल, शिलांग
3. विशेष सकिल, शिलांग
4. नवगांव सकिल
5. सिलचर सकिल
6. करीमगंज सकिल
7. मणिपुर सकिल, इम्फाल |
| 4. जोरहट रेंज | 1. जोरहट सकिल
2. शिवसागर सकिल
3. गोलाघाट सकिल |
| 5. तेजपुर सकिल | 1. तेजपुर सकिल
2. दुधरी सकिल |
| 6. डिब्रूगढ़ रेंज-1 | 1. डिब्रूगढ़ सकिल के क और ख वाड
2. डिब्रूगढ़ सकिल |
| 7. डिब्रूगढ़ रेंज-2 | 1. डिब्रूगढ़-1 रेंज-1 को अधिकारिता में जितने
वाड हैं उन्हें अपवर्जित करके डिब्रूगढ़ सकिल
के सब वाड
2. आयकर-सह-सम्पदा-शुल्क सकिल, डिब्रूगढ़
3. वेतन सकिल, डिब्रूगढ़.
4. तिनसुकिया सकिल |

जहां इस प्रविष्टि द्वारा कोई आय-कर सकिल, वाड या जिला या उनका कोई भाग, एक रेंज दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहां उस आय कर सकिल, वाड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अनुसूचना की तारीख

से ठीक पहले उस रेंज के, जिसने वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग, अन्तर्गत कर दिया गया है सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड, या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी जो के संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण :—

सहायक आयुक्त (अपील) की अधिकारिता के पुनराबंटन सिलचर रेंज के उत्साहन और गौहाटी में रेंज-2 के बन जाने से ये संशोधन आवश्यक हो गए हैं।

(उपरोक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि स्पष्टीकरण मात्र के लिए आशयित है)

[सं० 199/फा० सं० 261/9/70—आई टी जे]

New Delhi, the 30th December, 1970.

S. O. 1770—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column of the Schedule below shall perform their functions in respect of persons and incomes assessed to income-tax or super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Ward and Districts.
(1)	(2)
A—Range, New Delhi	1. Companies Circles III, VII, X, XII, XIV, XV, XVI, XIX & XX, New Delhi. 2. Special Circles-V, IX & X, New Delhi. 3. D-I, District, New Delhi.
B—Range, New Delhi	1. District-III (19), (20), (21), (22) & (23), New Delhi. 2. Distt. VII (1), (2), (3) & (4), New Delhi. 3. Distt-III, Wards, A, A(Addl.), A(Addl. I), O & O (Addl.), New Delhi. 4. Distt-VII Wards A, A(1) & B, New Delhi. 5. Distts. B-I, B-I(I), New Delhi. 6. Distts. C-I, C-I (I), C-II and C-III, New Delhi. 7. Distt-I, Wards A & A (I), New Delhi. 8. Distt-IX, Ward-A, New Delhi. 9. Refund Circle, New Delhi.
D—Range, New Delhi	1. Distt-III(10), (11), (12), (12)(Addl.), (13), (14), (14) (Addl.), (15), (16), (17) & (18), New Delhi. 2. Distt. VI (11), (12), (13), (14) & (15), New Delhi. 3. Distt-III, Wards, H, I, J, K & L, New Delhi. 4. Distts, B-VI, B-VII, Addl. B. VII, B-IX, & Addl. B-IX, New Delhi. 5. Income-tax-cum-wealth tax Circles-II IV & XI New Delhi. 6. Distt- I Wards A (1), (II), C (1) & C(I) (Addl.), New Delhi. 7. Distt.-X (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (10) (Addl. & 11), New Delhi.

(1)	(2)
E-Range, New Delhi]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distt. VIII (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and (19) (Addl.), New Delhi. 2. Distt. VIII, Ward A (Addl.) B, B (Addl.) B (Addl.-I) B (Addl. II), C, D, D (I), E, & F, New Delhi. 3. A-I, A. II, A. III, A-IV (I) & I(I) Districts, New Delhi. 4. Income-tax-cum-wealth-tax Circle-VIII, New Delhi
F-Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Companies Circles-I, V, IX, XXII & XIII, New Delhi. 2. Special Circles-I, I (Addl.) II, VI, VII & VIII, New Delhi.
H-Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distt. VI (1), (2), (3), (4), (5) (6), (7), (8), (9), (10) (Addl.), New Delhi. 2. Distt.-VI, Ward-A, A (Addl.), B. (Addl.), C, Cl. (Addl. D. & E New Delhi.
J-Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distt.-II (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) (Addl.) & 12, New Delhi. 2. Distt. II Wards-A, B, C, D E, F, A(I), C(I), C(I) (Addl.) & C (II), New Delhi. 3. Distt. V (1), (2), & (3), New Delhi. 4. Distt. V, Wards, A. A(Addl.) B, B (Addl.), C, D, E, F & G, New Delhi. 5. Distt. I (1) & (2), New Delhi 6. Distt. IX (1), New Delhi.
K-Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distt.-V (4), (5), (6) (7), (8), (9), (10), (11), (11) (Addl. (12), (12) (Addl) (13), & (13) (Addl.) New Delhi.
M-Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distt. III (1), (2) (3), (4) (5) (6), (6) (Addl.) (7), (7) (Addl), (8) & (9) New Delhi 2. Distt.-III, Wards B, C, D, E, F, F (Addl.) G, M, M(I) & N, New Delhi
Q-Range, New Delhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Companies Circles-II, IV, VI, VIII, XI, XIII, XVII, XVIII, New Delhi. 2. Special Circles-III & IV, New Delhi. 3. D-II, District, New Delhi.

Where an Income-tax Circles, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circles, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range, to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st January, 1971.

Explanatory Note :

This amendment has become necessary on account of reallocation of work amongst the Appellate Assistant Commissioners of Income tax in the Commissioner's charge.

(This note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory

[No. 2 (F, No. 261/4/70-INJ)]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 1770—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्वतम अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निवेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर

आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिविष्ट आयकर सकिलों, वार्डों और जिलों में उन व्यक्तियों की बाबत जिन पर आयकर या अधिकर निर्धारित किया गया है अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

रेंज	आयकर सकिल, वार्ड और जिले
1	2
क रेंज नई दिल्ली .	<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पनी सकिल III, VII, X, XII, XIV XV, XVI, XIX और XX, नई दिल्ली 2. विशेष सकिल—V, IX और X, नई दिल्ली 3. डी-1, जिला, नई दिल्ली
रेंज नई दिल्ली	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला III (19), (20), (21), (22), और (23), नई दिल्ली 2. जिला VII, (1), (2), (3), और (4), नई दिल्ली 3. जिला III, वार्ड क, क(अतिरिक्त), क(अतिरिक्त-1), ग और ग(अतिरिक्त), नई दिल्ली 4. जिला VII, वार्ड क, क(1) और ख, नई दिल्ली 5. जिले ख-1, ख-1 (1), नई दिल्ली 6. जिले ग-1, ग-1(1), ग-II और ग-III; नई दिल्ली 7. जिला-1, वार्ड क और क(1), नई दिल्ली 8. जिला X, वार्ड क, नई दिल्ली 9. प्रतिदाय सकिल, नई दिल्ली
घ रेंज, नई दिल्ली .	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला, (III), (10), (11), (12), (12) (अतिरिक्त); (13), (14), (14) (अतिरिक्त), (15), (16), (17), और (18), नई दिल्ली 2. जिला VI (11), (12), (13); (14), और (15), नई दिल्ली 3. जिला-III, वार्ड ज, झ, त-, ट और ठ, नई दिल्ली 4. जिले ख-VI, ख-VII, अतिरिक्त ख-VII, ख-IX और अतिरिक्त ख-IX, नई दिल्ली 5. आयकर एवं धनकर सकिल-II, IV और XI, नई दिल्ली 6. जिला 6, वार्ड क(I), क(II), ग(1) और ग(1) (अतिरिक्त), नई दिल्ली 7. जिला X-(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); (8), (9), (10), (10), (अतिरिक्त) और (11), नई दिल्ली

1

2

- ॐ रेंज, नई दिल्ली . . . 1. जिला VIII, (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14); (15), (16), (17), (18), (19) और (19) (अतिरिक्त) नई दिल्ली
2. जिला VIII, वार्ड क, क (अतिरिक्त), ख, ख (अतिरिक्त), ख (अतिरिक्त-1), ख (अतिरिक्त-2), ग, घ, घ(1), छ और च, नई दिल्ली
3. क-I, क-II, क-III, कIV, क-IV(1) और 1(1) जिले
4. आयकर एवं धनकर सर्किल VIII, नई दिल्ली
- च रेंज, नई दिल्ली . . . 1. कम्पनी सर्किल—I, V, IX, XXI और XXII, नई दिल्ली
2. विशेष सर्किल-1, 1(अतिरिक्त), II, IV, VII, और VIII, नई दिल्ली
- ख रेंज, नई दिल्ली . . . 1. जिला VI(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) और (10) (अतिरिक्त), नई दिल्ली
2. जिला-VI, वार्ड क, क(अतिरिक्त), ख(अतिरिक्त), ग ग(अतिरिक्त), घ और छ, नई दिल्ली ।
- न रेंज, नई दिल्ली . . . 1. जिला II (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); (8), (9), (10), (11), (11) (अतिरिक्त) और 12, नई दिल्ली ।
2. जिला II वार्ड-क, ख, ग, घ, छ, च, क(1), ग(1), ग(1) (अतिरिक्त) और ग(II), नई दिल्ली
3. जिला V (1), (2) और (3), नई दिल्ली
4. जिला V वार्ड क, क(अतिरिक्त), ख, ख(अतिरिक्त), ग, घ, छ, च और छ, नई दिल्ली
5. जिला I(1) और (2) नई दिल्ली
6. जिला IX(1), नई दिल्ली
- ट रेंज, नई दिल्ली . . . 1. जिला V (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); (11), (11) (अतिरिक्त), (12), (12) (अतिरिक्त), (13) और (13) (अतिरिक्त), नई दिल्ली ।
- ड रेंज, नई दिल्ली . . . 1. जिला-III (1), (2), (3), (4), (5), (6), (6) (अतिरिक्त), (7), (7) (अतिरिक्त), (8) और (9), नई दिल्ली ।
2. जिला-III, वार्ड ख, ग, घ, छ, च, छ(अतिरिक्त)ज, छ, छ(1) और छ नई दिल्ली ।

- य रेंज नई दिल्ली 1. कम्पनी सफिल, II, IV, VI, VIII, XI, XIII, XVII और XVIII नई दिल्ली
2. विशेष सफिल—III और IV, नई दिल्ली
3. घ-II, जिला, नई दिल्ली

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज में अन्तरित हो गया हो वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसके किसी भाग में निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के अपीली सहायक आयुक्त के समक्ष लम्बित थीं। जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, अपीली सहायक आयुक्त को अन्तरित कर दी जायगी और उनके संबंध में कार्यवाही उस अपीली सहायक आयुक्त द्वारा की जायगी।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण

यह संशोधन आयुक्त के भारसाधन में सहायक आयकर आयुक्तों (अपील) में कार्य के पुनः आवंटन के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु इसका आशय स्पष्टीकरण करना मात् है)।

[सं० 201 (फा० 261/4/70-आई० टी जे०)]

New Delhi, the 31st December, 1970.

S. O. 1771—In exercise of the powers conferred by sub-section(I), of Section 122 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Notification No. 101 (F. No. 261/1/70,-ITJ) dated 15-6-1970. For the existing entries in column 2 of the Schedule appended to the above mentioned Notification against Appellate Assistant Commissioner Jammu, Patiala and Appellate Assistant Commissioner Ludhiana the under mentioned entries shall be substituted :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2
Jammu	1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at:— (i) Jammu. (ii) Srinagar. (iii) The Income-tax Officer, Chamba and Kangra District at Pathank t.

(1)	(2)
Patiala	<p>1. All the Income-tax circles, Wards or Districts having headquarters at :—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Chandigarh (ii) Patiala (iii) Sangrur (iv) Malerkotla (v) Barnala (vi) Bhatinda (vii) Khanna (viii) Districts I (9) I(10), I(11) and I(12) Ludhiana. (ix) Pathankot <p>2. Special Survey Circle, Patiala (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of the Income-tax Officers, Chandigarh, Patiala Sangrur, Malerkotla, Barnala and Bhatinda).</p> <p>3. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Khanna Districts I (9), I (10), I(11), I(12), Ludhiana and Pathankot.</p> <p>4. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers Chandigarh, Patiala, Sangrur, Malerkotla, Barnala, Bhatinda, Khanna and Districts, I(9), I (10), I (11), I (12), Ludhiana and Pathankot.</p>
Ludhiana	<p>1. All Income-tax Circles, Wards or Districts having headquarters at:—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Ludhiana (Except Districts I (9), I (10), I (11), I (12) and Central Circles, Ludhiana.) (ii) Gurdaspur (iii) Batala (iv) Moga (v) Ferozepur (vi) Abohar <p>2. Special Survey Circle, Amritsar (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Ludhiana (except Districts I(9), I(10), I(11) & I(12), Ludhiana, Gurdaspur, Batala, Moga, Ferozepur and Abohar.)</p> <p>3. Salary Circle, Jullundur (in respect of persons who have their principal place of business in or reside in the jurisdiction of Income-tax Officers, Ludhiana (Except Districts I (9), I (10), I(11) and I (12), Ludhiana, Gurdaspur, Batala, Moga, Ferozepur and Abohar)</p>

This amendment shall take effect from 1-1-1971.

Explanatory Note:—

The amendment has become necessary for assigning even work-load to the Appellate Assistant Commissioners in the Commissioner's charge.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1970

एस० ओ० 1771—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वर्तन अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं 101 (फा० सं० 201/1/70—आई टी जे), तारीख 15-6-1970 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है। उपरिर्णित अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर सहायक आयुक्त (अपील), जम्मू, पटियाला और सहायक आयुक्त (अपील) लुधियाना के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

अनुसूची

रज

आयकर सर्किल, वार्ड और जिले

1

2

- | | |
|-------------------|--|
| जम्मू | 1. सभी आयकर सर्किल, वार्ड या जिले जिनका मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों पर है —
(i) जम्मू
(ii) श्रीनगर
(iii) आयकर अधिकारी, चम्बा और कांगड़ा जिले, पठानकोट । |
| पटियाला | 1. सभी आयकर सर्किल, वार्ड या जिले जिनका मुख्यालय निम्नलिखित स्थानों पर है :—
(i) चण्डीगढ़
(ii) पटियाला
(iii) संगरूर
(iv) मालेरकोटला
(v) बरनाला
(vi) भटिंडा
(vii) खन्ना
(viii) जिले 1 (9), 1 (10), 1 (11), और 1 (12) लुधियाना
(ix) पठानकोट

2. विशेष सबक्षेत्र सर्किल, पटियाला (उन व्यक्तियों की यादत जिनका चण्डीगढ़, पटियाला, संगरूर, मालेरकोटला, बरनाला और भटिंडा के आयकर अधिकारियों की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है अथवा जो इन की अधिकारिता में निवास करते हैं) । |

1

2

3. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका खन्ना, जिले 1 (9), 1 (10), 1 (11), 1 (12), लुधियाना और पठानकोट के आयकर अधिकारियों की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है अथवा जो इन की अधिकारिता में निवास करते हैं) ।

4. बंटन सर्किल, जालन्धर, (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका चण्डीगढ़, पटियाला, संगरूर, मालेरकोटला, बरनाला, भटिंडा खन्ना और जिले 1 (9), 1 (10), 1 (11), 1 (12), लुधियाना और पठानकोट के आयकर अधिकारियों की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है अथवा जो इन की अधिकारिता में निवास करते हैं) ।

लुधियाना

1. सभी आयकर सर्किल, थार्ड या जिले जिनका मुख्यालय निम्न-लिखित स्थानों पर है :—

1. लुधियाना (जिला 1 (9), 1 (10), 1 (11), 1 (12), और केन्द्रीय सर्किल लुधियाना को छोड़ कर

(ii) गुरदासपुर

(iii) बटाला

(iv) मोगा

(v) फिरोजपुर

(vi) अबोहर

2. विशेष सर्वेक्षण सर्किल अमृतसर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका लुधियाना (जिला 1 (9), 1 (10), 1 (11), और 1 (12) लुधियाना को छोड़कर) गुरदासपुर, बटाला, मोगा, फिरोजपुर और अबोहर के आयकर अधिकारियों की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है अथवा जो इन की अधिकारिता में निवास करते हैं) ।

3. बंटन सर्किल, जालन्धर (उन व्यक्तियों की बाबत जिनका लुधियाना (जिला 1 (9), 1 (10), 1 (11), और 1 (12) लुधियाना को छोड़कर) गुरदासपुर, बटाला, मोगा, फिरोजपुर और अबोहर के आयकर अधिकारियों की अधिकारिता में कारबार का मुख्य स्थान है अथवा जो इनकी अधिकारिता में निवास करते हैं) ।

स्पष्टीकरण टिप्पण

यह संशोधन आयुक्त के भारसाधन में सहायक आयुक्तों (अपील) को समान कार्यभार समनुद्दिष्ट करने के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु इसका आशय स्पष्टीकरण करना मात्र है)

[सं० 202 (फ० सं० 261/1/70—आई टी जे)]

S.O. 1772.—In exercise of the powers conferred by Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments in the Schedule appended to its Notification No. 12 (F. No. 50/7/69-ITJ) dated 14th January, 1966 as amended from time to time, namely:—

In the Schedule against:—

'S' Range, Calcutta, following shall be substituted:—

1. Howrah.

This notification shall take effect from 1st January, 1971.

Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of abolition of 'AF' Range, Calcutta, and consequent re-allocation of the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax jurisdiction in West Bengal charge.

(This does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 203 (F. No. 261/5/70-ITJ)]

एस० ओ० 1772.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा इसकी समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 12 (फ० सं० 50/7/60 आई टी जे) तारीख 14-1-1966 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करता है, अर्थात् —

अनुसूची में,

“घ” रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

1. हावड़ा

यह अधिसूचना 1-1-1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण टिप्पण

यह संशोधन “कच” रेंज, कलकत्ता, के उत्पादन और पश्चिम बंगाल भारसाधन में सहाय आयकर आयुक्तों (अपील) के परिणामिक पुनः आबंटन के कारण आवश्यक हो गया है।

(यह अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु इसका आशय स्पष्टीकरण करना मात्र है)।

[सं० 203 (फ० सं० 261/5/70—आई टी जे)]

New Delhi, the 6th January, 1971.

S.O. 1773.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all the previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax, of the Range specified in column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards, and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Circles, Wards and Districts
(1)	(2)
Poona Range-I, Poona . . .	<ol style="list-style-type: none"> 1. B-Ward, Poona 2. D-Ward, Poona. 3. Addl. D-Ward, Poona. 4. G-Ward, Poona. 5. Addl. C-Ward, Poona. 6. C-Ward, Poona. 7. Addl. C-Ward, Poona. 8. Wealth-tax Circle, Poona. 9. Special Investigation Circle, Poona. 10. K-Ward, Poona. 11. Collection-I, Poona. 12. Collection-II, Poona. 13. L-Ward, Poona. 14. M-Ward, Poona.
Poona Range-II, Poona . . .	<ol style="list-style-type: none"> 1. A-Ward, Poona. 2. Addl. A-Ward, Poona. 3. Central Circle, Poona. 4. Companies Circle, Poona. 5. Addl. Companies Circle, Poona. 6. E-Ward, Poona. 7. Addl. E-Ward, Poona. 8. F-Ward, Poona. 9. Addl. F-Ward, Poona. 10. H-Ward, Poona. 11. J-Ward, Poona. 12. Addl. J-Ward, Poona.
Kolhapur Range, Kolhapur . . .	<ol style="list-style-type: none"> 1. A-Ward, Kolhapur. 2. B-Ward, Kolhapur. 3. C-Ward, Kolhapur. 4. D-Ward, Kolhapur. 5. E-Ward, Kolhapur. 6. F-Ward, Kolhapur. 7. G-Ward, Kolhapur. 8. H-Ward, Kolhapur. 9. Collection Circle, Kolhapur. 10. Ratnagiri. 11. A-Ward, Satara. 12. B-Ward, Satara. 13. C-Ward, Satara. 14. A-Ward, Sangli. 15. B-Ward, Sangli. 16. C-Ward, Sangli. 17. D-Ward, Sangli. 18. Special Survey Circle, Poona. 19. Addl. Special Survey Circle, Poona. 20. Salaries and Refunds Circle, Poona. 21. G.H.Q., Income-tax Circle, Poona.

(1)

(2)

Nasik Range, Nasik

1. A-Ward, Nasik.
2. B-Ward, Nasik.
3. C-Ward, Nasik.
4. D-Ward, Nasik.
5. E-Ward, Nasik.
6. F-Ward, Nasik.
7. Collection Circle, Nasik.
8. A-Ward, Malegaon.
9. B-Ward, Malegaon.
10. A-Ward, Dhulia.
11. B-Ward, Dhulia.
12. C-Ward, Dhulia.
13. A-Ward, Jalgaon.
14. B-Ward, Jalgaon.
15. C-Ward, Jalgaon.
16. D-Ward, Jalgaon.
17. A-Ward, Ahmednagar.
18. B-Ward, Ahmednagar.
19. C-Ward, Ahmednagar.

Thana, Range, Thana

1. A-Ward, Thana.
2. Addl. A-Ward, Thana.
3. B-Ward, Thana.
4. C-Ward, Thana.
5. D-Ward, Thana.
6. E-Ward, Thana.
7. F-Ward, Thana.
8. G-Ward, Thana.
9. H-Ward, Thana.
10. J-Ward, Thana.
11. K-Ward, Thana.
12. Collection Circle-I, Thana.
13. Collection Circle-II, Thana.
14. Special Survey Circle, Thana.
15. Addl. Special Survey Circle, Thana.
16. Recovery Circle-III, Thana.
17. Palghar.
18. A-Ward, Panvel.
19. B-Ward, Panvel.
20. C-Ward, Panvel.
21. A-Ward, Sholapur.
22. B-Ward, Sholapur.
23. C-Ward, Sholapur.
24. D-Ward, Sholapur.
25. E-Ward, Sholapur.
26. Income-tax Circle, Barsi.

When an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

The notification shall take effect from 1-2-1971.

Explanatory Note :

The amendments have become necessary on account of reallocation of work amongst the Appellate Assistant Commissioners in the Commissioner's Charge due to abolition of Sholapur Range.

(This note does not form a part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1971

एस० ओ० 1773-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे

अनुसूची

रेंज	आय कर सफिल, वार्ड और जिले
1	2
पूना रेंज-1, पूना	1. ख-वार्ड, पूना 2. घ-वार्ड, पूना 3. अतिरिक्त घ-वार्ड, पूना 4. छ-वार्ड, पूना 5. अतिरिक्त छ-वार्ड पूना 6. ग-वार्ड, पूना 7. अतिरिक्त ग-वार्ड, पूना 8. धन कर सफिल, पूना 9. विशेष अन्वेषण सफिल, पूना 10. ट-वार्ड, पूना 11. संग्रहण-1, पूना 12. संग्रहण-2, पूना 13. ठ-वार्ड, पूना 14. ड-वार्ड, पूना
पूना रेंज-2, पूना	1. क-वार्ड, पूना 2. अतिरिक्त क-वार्ड, पूना 3. केन्द्रीय सफिल, पूना 4. कम्पनी सफिल, पूना 5. अतिरिक्त कम्पनी सफिल, पूना 6. इ-वार्ड, पूना 7. अतिरिक्त इ-वार्ड, पूना 8. फ-वार्ड, पूना 9. अतिरिक्त फ-वार्ड, पूना 10. ज-वार्ड, पूना 11. झ-वार्ड, पूना 12. अतिरिक्त झ-वार्ड, पूना

1

2

कोल्हापुर रेंज,
कोल्हापुर

1. क—वार्ड, कोल्हापुर
2. ख—वार्ड, कोल्हापुर
3. ग—वार्ड, कोल्हापुर
4. घ—वार्ड, कोल्हापुर
5. ङ—वार्ड, कोल्हापुर
6. च—वार्ड, कोल्हापुर
7. छ—वार्ड, कोल्हापुर
8. ज—वार्ड, कोल्हापुर
9. संग्रहण सर्किल, कोल्हापुर
10. रत्नागिरि
11. क—वार्ड, सतारा
12. ख—वार्ड, सतारा
13. ग—वार्ड, सतारा
14. क—वार्ड, सांगली
15. ख—वार्ड, सांगली
16. ग—वार्ड, सांगली
17. घ—वार्ड, सांगली
18. विशेष सर्वेक्षण सर्किल, पूना
19. अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण सर्किल, पूना
20. सम्बलम और प्रतिदाय सर्किल, पूना
21. साधारण मुख्यालय आय-कर सर्किल, पूना

नासिक रेंज,
नासिक

1. क—वार्ड, नासिक
2. ख—वार्ड, नासिक
3. ग—वार्ड, नासिक
4. घ—वार्ड, नासिक
5. ङ—वार्ड, नासिक
6. च—वार्ड, नासिक
7. संग्रहण सर्किल, नासिक
8. क—वार्ड, मालेगांव
9. ख—वार्ड, मालेगांव
10. क—वार्ड, धुलिया
11. ख—वार्ड, धुलिया
12. ग—वार्ड, धुलिया
13. क—वार्ड, जलगांव
14. ख—वार्ड, जलगांव
15. ग—वार्ड, जलगांव
16. घ—वार्ड, जलगांव
17. क—वार्ड, अहमदनगर

1

2

थाना रेंज,
थाना .

18. ख—वार्ड, अहमदनगर
19. ग—वार्ड, अहमदनगर
1. क—वार्ड, थाना
2. अतिरिक्त क—वार्ड, थाना
3. ख—वार्ड, थाना
4. ग—वार्ड, थाना
5. घ—वार्ड, थाना
6. ङ—वार्ड, थाना
7. च—वार्ड, थाना
8. छ—वार्ड, थाना
9. ज—वार्ड, थाना
10. अ—वार्ड, थाना
11. ट—वार्ड, थाना
12. संग्रहण सफिल—1, थाना
13. संग्रहण सफिल—2, थाना
14. विशेष सर्वेक्षण सफिल, थाना
15. अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण सफिल, थाना
16. वसूली सफिल—3, थाना
17. पालघर
18. क—वार्ड, पनवेल
19. ख—वार्ड, पनवेल
20. ग—वार्ड, पनवेल
21. क—वार्ड, शोलापुर
22. ख—वार्ड, शोलापुर
23. ग—वार्ड, शोलापुर
24. घ—वार्ड, शोलापुर
25. ङ—वार्ड, शोलापुर
26. आय-कर सफिल, बर्से

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सफिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-सफिल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से अधिक ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आयकर सफिल, वार्ड, या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सफिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जायगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना 1-2-1971 से प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकारक टिप्पणी

यह संशोधन, शोलापुर रेंज के उत्पादन के कारण आयुक्त के भारसाधन में सहायक आयुक्तों (अपील) के मध्य कार्य के पुनर्आवंटन के कारण आवश्यक हो गए हैं।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है धरन इसका आशय केवल स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं० 3 (फा० सं० 261/8/70-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 8th January 1971

S.O. 1774.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby make the following amendment in the Schedule appended to its notification No. 183 (261/8/70-ITJ) dated 20th November, 1970, namely:—

Again Thana Range, Thana under column 2 of the following shall be added:—

24. K.Ward, Thana.

This notification shall take effect from 8th January, 1971.

Explanatory Note

The amendmnet has become necessary on account of creation of a new Ward known as 'K' Ward, Thana in the Commissioner's charge.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory.)

[No. 6 (F. No. 261/8/70-ITJ).]

नई दिल्ली, 8 जनवरी 1971

एस० ओ० 1774.—प्रायः कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इन निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं० 183 (261/8/70—आई टी जे) ता० 20-11-1970 से उल्लिखित अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :

स्तम्भ 2 के अन्तर्गत थाना रेंज, थाना के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

24. ट—वार्ड, थाना

यह अधिसूचना 8-1-1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

आयुक्त के भारसाधन में "ट" वार्ड थाना नामक एक नए वार्ड के बन जाने के कारण यह संशोधन आवश्यक हो गया है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं० 6 (फा० सं० 261/8/70-आई टी जे)]

New Delhi, the 27th January 1971

S.O. 1775.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, New Delhi, hereby makes the following further amendments in the Schedule appended to its Notification No. 94 (F. No. 261/20/70-ITJ) dated, 8-6-70 viz.,

- (i) In the said Schedule against A-Range, Jabalpur the following entries shall be substituted viz.,

Bhopal Range, Bhopal	1.	I.T.O., A-Ward, Bhopal.
	2.	I.T.O., B-Ward, Bhopal.
	3.	I.T.O., C-Ward, Bhopal.
	4.	I.T.O., D-Ward, Bhopal.
	5.	I.T.O., E-Ward, Bhopal.
	6.	I.T.O., F-Ward, Bhopal.
	7.	I.T.O., Betul.
	8.	I.T.O., A-Ward, Itarsi.
	9.	I.T.O., B-Ward, Itarsi.
A-Range, Jabalpur	1.	I.T.O., Central Circle, Jabalpur.
	2.	I.T.O., A-Ward, Jabalpur.
	3.	I.T.O., Special Estate Duty cum-Income-tax Circle, Jabalpur.
	4.	I.T.O., A-Ward, Satna.
	5.	I.T.O., B-Ward, Satna.
	6.	I.T.O., C-Ward, Satna.
	7.	I.T.O., D-Ward, Satna.

- (ii) In the said Schedule under Column 1 between B-Range, Jabalpur and Raipur Range, Raipur, C-Range, Jabalpur will be inserted and against C-Range, Jabalpur under Column 2, the following entries shall be inserted viz.,

C-Range, Jabalpur	1.	I.T.O., B-Ward, Jabalpur.
	2.	I.T.O., G-Ward, Jabalpur.
	3.	I.T.O., A-Ward, Sagar.
	4.	I.T.O., B-Ward, Sagar.
	5.	I.T.O., C-Ward, Sagar.

This notification shall take effect from 1-2-1971.

Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of creation of an Appellate Range at Jabalpur known as C-Range, Jabalpur.

(The above note does not form part of the notification, but is intended to be merely clarificatory).

[No. 11(F. No. 261/1/71-ITJ).]

नई दिल्ली, 27 जनवरी 1971

एस० ओ० 1775 : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 94 (का०

सं० 261/20/70-आई०टी०जे०), ता० 8-6-70 से उवाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् —

(I) उक्त अनुसूची में क-रेंज, बलजपुर के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :

भोपाल रेंज, भोपाल

1. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, भोपाल
2. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, भोपाल
3. आयकर अधिकारी, ग-वार्ड, भोपाल
4. आयकर अधिकारी, घ-वार्ड, भोपाल
5. आयकर अधिकारी, ड-वार्ड, भोपाल
6. आयकर अधिकारी, च-वार्ड, भोपाल
7. आयकर अधिकारी, बतुल
8. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, इटारसी
9. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, इटारसी

क-रेंज जबलपुर

1. आयकर अधिकारी, जबलपुर
2. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, जबलपुर
3. आयकर अधिकारी, विशेष सम्पदा शल्क-एवम् आयकर सकिल, जबलपुर
4. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, सतना
5. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, सतना
6. आयकर अधिकारी, ग-वार्ड, सतना
7. आयकर अधिकारी, घ-वार्ड, सतना

(ii) उक्त अनुसूची में स्तम्भ 1 के अन्तर्गत ख-रेंज, जबलपुर और रायपुर रेंज, रायपुर के बीच, ग-रेंज जबलपुर अन्तःस्थापित किया जाएगा और स्तम्भ 2 के अन्तर्गत ग-रेंज, जबलपुर के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :

ग-रेंज, जबलपुर

1. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, जबलपुर
2. आयकर अधिकारी, छ-वार्ड, जबलपुर
3. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, सागर
4. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, सागर
5. आयकर अधिकारी, ग-वार्ड, सागर

स्पष्टीकारक टिप्पण :

जबलपुर में ग—रेंज, जबलपुर नामक अपीलो रेंज के बन जाने के कारण यह संशोधन, आवश्यक हो गया है।

(उपर्युक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं० 11 (फा० सं० 261/1/71)-आई० टी० जे०]

New Delhi, the 28th January 1971

S.O. 1776.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all the other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its notification No. 199 (F. No. 261/9/70-ITJ) dated 24th December, 1970, namely:—

In the said Schedule against Jorhat Range, the following shall be added under Column 2—

“4. Dimapur Circle,”

This notification shall take effect from 1st February, 1971.

Explanatory Note

The amendment has become necessary on account of the creation of a new Income-tax Circle at Dimapur.

(The above note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 12(261/3/71-ITJ.)]

नई दिल्ली, 28 जनवरी 1971

एस० ओ० 1776.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा अपनी अधिसूचना सं० 199 फा० सं० 261/9/70—आई० टी० जे०), ता० 24-12-1970 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

उक्त अनुसूची में जोरहट रेंज के सामने, स्तम्भ 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा
“ 4 दिमापुर सर्किल ”

यह अधिसूचना 1-2-1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

दिमापुर में एक नए आयकर सर्किल के बन जाने के कारण यह संशोधन, आवश्यक हो गया है।

(उपर्युक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं० 12 (फा० सं० 261/3/71-आई० टी० जे०)]

S. O. 1777.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the

Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 2 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-Tax or Super-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts, specified in the corresponding entry in column 3 thereof:—

S. No.	Ranges	Income-tax Circles, Wards & Districts
(1)	(2)	(3)
1	Range-I, Lucknow	1. Circle-I, Lucknow excluding :— (i) C-Ward, Circle-I, Lucknow. (ii) F-Ward, Circle-I, Lucknow. 2. Salary Circle, Lucknow. 3. Special Circle, Lucknow. 4. Lucknow. 5. Special Survey Circle, Lucknow. 6. Project Circle, Lucknow. 7. Hardol.
2	Range-II, Lucknow.	1. Circle-II, Lucknow (which existed upto 31-5-68 and from 1-8-68 to 1-6-69 and thereafter). 2. C-Ward, Circle-I, Lucknow. 3. F-Ward, Circle-I, Lucknow. 4. Company Circle, Lucknow. 5. Estate-duty-cum-I.T. Circle, Lucknow.
3	Range-I, Varanasi	1. C-Ward, Varanasi. 2. E-Ward, Varanasi. 3. F-Ward, Varanasi. 4. Special Circle, Varanasi. 5. Jaunpur. 6. Azamgarh.
4	Range-II, Varanasi	1. Varanasi Circle excluding :— (i) C-Ward, Varanasi. (ii) E-Ward, Varanasi. (iii) F-Ward, Varanasi. 2. Special Survey Circle, Varanasi. 3. Project Circle, Varanasi. 4. Ballia.
5	Range-I, Allahabad	1. Allahabad Circle, excluding :— (i) B-Ward, Allahabad. (ii) F-Ward, Allahabad. (iii) I.T.O. (Collection). 2. Salary Circle, Allahabad. 3. Estate-duty-cum-I.T. Circle, Allahabad. 4. Faizabad. 5. Gonda.
6	Range-II, Allahabad	1. B-Ward, Allahabad. 2. F-Ward, Allahabad. 3. I.T.O. (Collection), Allahabad. 4. I.T.O. (Administration) & (Collection), Allahabad. 5. Mirzapur.
7	Gorakhpur	1. Gorakhpur. 2. Basti.
8	Range-I, Bareilly	1. Bareilly Circle, excluding :— (i) B-Ward, Bareilly. (ii) D-Ward, Bareilly. (iii) F-Ward, Bareilly. 2. Nainital. 3. Haldwani.
9	Range-II, Bareilly	1. B-Ward, Bareilly. 2. Pilibhit. 3. Shahjahanpur.

(1)	(2)	(3)
10. Range-III, Bareilly		1. D-Ward, Bareilly. 2. F-Ward, Bareilly. 3. Lakhmipur-Kheri. 4. Sitapur 5. Almora. 6. Badaun.
11. Range-I, Moradabad.		1. Moradabad Circle, excluding (i) B-Ward, Moradabad. (ii) D-Ward, Moradabad. (iii) E-Ward, Moradabad. 2. Najibabad.
12. Range-II, Moradabad.		1. B-Ward, Moradabad. 2. D-Ward, Moradabad. 3. E-Ward, Moradabad. 4. Bulandshahr. 5. Rampur. 6. Kashipur.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof, is transferred shall, from the date this notification takes effect be transferred to and effect dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-2-1971.

Explanatory Note

The amendments have become necessary to provide jurisdiction to the new Appellate Assistant Commissioner posted as Appellate Assistant Commissioner Range-III, Bareilly and to make consequential adjustments in the jurisdiction of other Appellate Assistant Commissioners to make better distribution of workload amongst them.

[No. 13(F. No. 261/2/71-ITJ).]

एस० ओ० 1777—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) उसके स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आय-कर सिकिलों, वार्डों और जिलों में आयकर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे :—

अनुसूची

क्रम संख्या	रेंज	आय-कर सिकिल, वार्ड और जिले
1	2	3
1. रेंज-1 लखनऊ		1. सिकिल-1, लखनऊ, निम्नलिखित को अपवर्जित करके । (i) ग-वार्ड, सिकिल-1, लखनऊ (ii) च-वार्ड, सिकिल-1, लखनऊ

1	2	3
		2. सबजम सिकिल, लखनऊ 3. लखनऊ 4. लखनऊ 5. विशेष सर्वेक्षण सिकिल, लखनऊ 6. परियोजना सिकिल, लखनऊ 7. हरदोई
2. रेंज-2, लखनऊ		1. सिकिल-2, लखनऊ (जो कि 31-5-68 तक था और 1-8-68 से 1-6-69 तक और तत्पश्चात् ।) 2. ग-वार्ड, सिकिल-1, लखनऊ 3. च-वार्ड, सिकिल-1, लखनऊ 4. कम्पनी सिकिल, लखनऊ 5. सम्पदा शुल्क-सह-आयकर सिकिल, लखनऊ
3. रेंज-1, वाराणसी		1. ग-वार्ड, वाराणसी 2. ड-वार्ड, वाराणसी 3. च-वार्ड, वाराणसी 4. विशेष सिकिल, वाराणसी 5. जोनपुर 6. आञ्जमगढ़
4. रेंज-2, वाराणसी		1. वाराणसी सिकिल, निम्नलिखित को अपवर्जित करके — (i) ग-वार्ड, वाराणसी (ii) ड-वार्ड, वाराणसी (iii) च-वार्ड, वाराणसी 2. विशेष सर्वेक्षण सिकिल, वाराणसी 3. परियोजना सिकिल, वाराणसी 4. बलिया
5. रेंज-1, इलाहाबाद		1. इलाहाबाद सिकिल, निम्नलिखित को अपवर्जित करके— (i) ख-वार्ड, इलाहाबाद (ii) च-वार्ड, इलाहाबाद (iii) आयकर अधिकारी, (संग्रहण) 2. सम्बलम सिकिल, इलाहाबाद 3. सम्पदा शुल्क-सह-आयकर सिकिल, इलाहाबाद 4. फैजाबाद 5. गोंडा
6. रेंज-2, इलाहाबाद		1. ख-वार्ड, इलाहाबाद 2. च-वार्ड, इलाहाबाद 3. आयकर-अधिकारी (संग्रहण), इलाहाबाद ।

1	2	3
		4. आयकर अधिकारी (प्रशासन) और (संग्रहण), इलाहाबाद ।
		5. मिर्जापुर
7. गोरखपुर		1. गोरखपुर 2. बस्ती
8. रेंज-1, बरेली		1. बरेली सकिल, निम्नलिखित को अपवर्जित करके— (i) ख-वार्ड, बरेली (ii) घ-वार्ड, बरेली (iii) च-वार्ड, बरेली 2. नैनीताल 3. हल्दवानी
9. रेंज-2, बरेली		1. ख-वार्ड, बरेली 2. पीलीभीत 3. शाहजहांपुर
10. रेंज-3, बरेली		1. घ-वार्ड, बरेली 2. च-वार्ड, बरेली 3. लखीमपुर-खड़ी 4. सीतापुर 5. अल्मोड़ा 6. बदायूं
11. रेंज-1, मुरादाबाद		1. मुरादाबाद सकिल, निम्नलिखित को अपवर्जित करके— (i) ख-वार्ड, मुरादाबाद (ii) घ-वार्ड, मुरादाबाद (iii) ड-वार्ड, मुरादाबाद 2. नजीबाबाद
12. रेंज-2, मुरादाबाद		1. ख-वार्ड, मुरादाबाद 2. घ-वार्ड, मुरादाबाद 3. ड-वार्ड, मुरादाबाद 4. बुलन्दशहर 5. रामपुर 6. काशीपुर

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तर्गत हो गया हो वहां उस आय-कर सकिल, वार्ड या जिले या उसके

किसी भाग में किए गए, निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तर्गत कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तर्गत कर दी जाएगी जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 1-2-1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

सहायक आयुक्त (अपील) रेंज—3, बरेली के रूप में तैनात नये सहायक आयुक्त (अपील) की अधिकारिता का उपबन्ध करने के लिए और अन्य सहायक आयुक्तों (अपील) को उनके बीच अधिकारिता में कार्यभार के उत्तम वितरणार्थ पारिणामिक समायोजन करने के लिए ये संशोधन आवश्यक हो गए हैं।

[सं 13 (फा० सं० 261/2/71-आई टी जे)]

New Delhi, the 25th February 1971

S.O. 1778.—In exercise of the powers conferred by section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes transferred the head quarters of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Dharwar Range. Dharwar to Hubli with effect from 1st February, 1971.

[No. 62 (F. No. 261/5/71-ITJ).]

नई दिल्ली, 25 फरवरी 1971

एस० ओ० 1778—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सहायक आयकर आयुक्त (अपील) धारवाड़ रेंज, धारवाड़ का मुख्यालय स्थानान्तरित कर के 1 फरवरी, 1971 से हुबली कर दिया है।

[सं 62 (फा० सं०-261/5/71आई० टी जे)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th February 1971

S.O. 1779.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that in the Notification No. 11(261/1/71-ITJ), dated the 27th January, 1971, sub para 1 of para 1 shall be read as,

“In the said Schedule against Bhopal Range, Bhopal and A-Range, Jabalpur, the following entries shall be substituted viz.,”

against “In the said Schedule against A-Range, Jabalpur, the following entries shall be substituted viz.,”

[No. 61 (F. No. 261/1/71-ITJ).]

P. K. SHARAN, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1971

एस० ओ० 1779.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि अधिसूचना सं० 11 (261/1/71—आई टी जे) तारीख 27 जनवरी, 1971 में पैरा, 1 के उपपैरा 1 "उक्त अनुसूची में क—रेंज, जबलपुर के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्" के स्थान पर

"उक्त अनुसूची में भोपाल रेंज, भोपाल और क, रेंज, जबलपुर के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् "

पढ़ा जाएगा ।

[सं० 61 (फा० सं० 261/1/71—आई० टी० जे०)

पी० के० शरण, अपर सचिव ।

INCOME-TAX

New Delhi, the 11th February 1971

S.O. 1780.—In partial modification of Notification No. 9 dated 21st January 1971 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Additional Commissioner of Income-tax (Recovery I) Bombay will have jurisdiction over the ranges pertaining to Commissioners charges of City I and Central, Bombay and the Additional Commissioner of Income-tax (Recovery II) Bombay will have jurisdiction over the ranges pertaining to Commissioners charges of City II and III. The Additional Commissioner of Income-tax (Recovery I) Calcutta will have jurisdiction over the ranges pertaining to Commissioners charges of West Bengal I and II and the Additional Commissioner of Income-tax (Recovery II) Calcutta will have jurisdiction over the ranges pertaining to Commissioners charges of West Bengal III and Central Calcutta.

[No. 41 (F. No. 187/2/71-IT(AI).]

B. MADHAVAN, Under Secy.

आयकर

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1971

एस० ओ० 1780.—अधिसूचना सं० 9 तारीख 21-1-71 का आंशिक उपान्तरण और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि मुम्बई के अपर आयकर आयुक्त (वसूली 1) की अधिकारिता सिटी और सेन्ट्रल मुम्बई का भारसाधन रखने वाले आयुक्तों से सम्बद्ध रेंजों पर और मुम्बई के अपर आयकर आयुक्त (वसूली 2) की अधिकारिता सिटी 2 और 3 का भारसाधन रखने वाले आयुक्तों से सम्बद्ध रेंजों पर, होगी । कलकत्ता के अपर आयकर आयुक्त (वसूली 1) की अधिकारिता पश्चिम बंगाल 1 और 2 का भारसाधन रखने वाले आयुक्तों से सम्बद्ध रेंजों पर और कलकत्ता के अपर आयकर आयुक्त (वसूली 2) की अधिकारिता पश्चिम बंगाल 3 और सेन्ट्रल कलकत्ता का भारसाधन रखने वाले आयुक्तों से सम्बद्ध रेंजों पर, होगी ।

[सं० 41 (फा० सं० 187/2/71—आई० टी० ए० आई०)]

बी० माधवन, उप सचिव ।

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1781.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government with the consent of the Government of the State of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the State of Maharashtra for the investigation of offences punishable under section 2 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 (23 of 1961).

[No. 228/2/71-AVD(II).]

संश्लेषण सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1971

क्र० आ० 1781.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा-6 के साथ पठित धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त से उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का दंडिक विधि-नियम संशोधन अधिनियम, 1961 (1961 का 23) की धारा—2 के अधीन दंडनीय अपराधों के अन्वेषण के लिए, महाराष्ट्र राज्य में विस्तार करती है।

[संख्या 228/2/71-ए० वी० डी० -II]

S.O. 1782.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

- (a) offences punishable under section 2 of the Criminal Law Amendment Act 1961 (23 of 1961).
- (b) attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/2/71-AVD(II).]

B. C. VANJANI, Under Secy.

क्र० आ० 1782.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा—3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अपराधों को उन अपराधों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, अर्थात् :—

- (क) दंडिक विधि-नियम संशोधन अधिनियम, 1961 (1961 का 23) की धारा-2 के अधीन दंडनीय अपराध ;
- (ख) खण्ड (क) में वर्णित अपराधों और एक ही तथ्यों से उद्भूत होने वाले एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध से सम्बन्धित या संलग्न में प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयन्त्र :

[संख्या 228/2/71-ए० वी० डी० -II]

बी० सी० वनजानी, अवर सचिव ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th April 1971

S.O. 1783.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Police Training College (Non-gazetted—Ministerial Staff) Recruitment Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Police Training College (Non-gazetted—Ministerial Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Police Training College (Non-gazetted—Ministerial Staff) Recruitment Rules, 1961,—

(i) for the words “Central Police Training College”, wherever they occur, the words “National Police Academy” shall be substituted;

(ii) in the Schedule, below the entry in column 6 against the post of “Lower Division Clerk (including Steno Typist), the following note shall be inserted, namely:—

“NOTE.—10 per cent of the vacancies in the grade of Lower Division Clerks shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment), subject to the following conditions, namely:—

(a) Selection shall be made through a departmental examination confined to such Class IV employees as fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely, Matriculation or equivalent;

(b) the maximum age for this examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates);

Provided that for the first two examinations to be conducted under this scheme, the upper age limit shall be 45 years (50 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates);

(c) at least 5 years' service in Class IV shall be essential;

(d) the maximum number of recruits by this method shall be limited to 10 per cent of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over”.

[No. 38/2/70-Pers. I.]

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1783.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित—अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1961 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित—अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

2 (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित—अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1961 में—

(1) जहाँ कहीं भी “केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय” शब्द आएँ, उनके स्थान पर “राष्ट्रीय पुलिस अकादमी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) अनुसूची में, स्तम्भ 6 में की प्रविष्टि के नीचे निम्न श्रेणी लिपिक (जिसमें ग्राशु टंकक सम्मिलित हैं) के पद के सामने, निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—“टिप्पण—निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी की 10 प्रतिशत रिक्तियां, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, वर्ग 4 के (नियमित स्थापन पर के कर्मचारियों द्वारा भरी जाने के लिए आरक्षित होंगी; अर्थात् :—
- (क) चयन विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाएगा जो ऐसे वर्ग 4 के कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अर्थात्—मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, की अपेक्षा पूरी करते हों ;
- (ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की वशा में 45 वर्ष) होंगी :
- परन्तु इस स्कीम के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली प्रथम दो परीक्षाओं के लिए उच्चतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष) होगी ;
- (ग) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी ;
- (घ) इस प्रकार से भर्ती होने वालों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिकों के काडर में रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होंगी और न भरी गई रिक्तियां आगे नहीं ले जायी जाएंगी ।”

[सं० 38/2/70—कार्मिक-1]

के० त्यागराजन,

उप सचिव ।

New Delhi the 21st April 1971

S.O.1784.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Class III posts (Directorate of Co-ordination) (Police Wireless) Recruitment Rules, 1962 namely:—

1. (1) These rules may be called the Class III Posts (Directorate of Co-ordination) (Police Wireless) Recruitment (amendment) Rules 1970
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Class III Posts (Directorate of Co-ordination) (Police Wireless) Recruitment Rules, 1962, after serial No. 27, and the entries relating thereto, the following shall be inserted thereto:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Librarian	One]	General Central Service Class III non-gazetted	Rs. 150-10-250-EB-10-290-15-335-EB-15-380	Not applicable	Direct recruitment	18-25 years	(a) Higher Secondary or equivalent examination of a recognised University or Board. (b) Certificate in Library Science issued by a recognised Institution/University.	2 Yrs.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

[No. A. 21/20/70-Wireless (Pers. I)]

P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1971

एस०ओ० 1784.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग 3 पद (समन्वय निदेशालय) पुलिस बेतार भर्ती (संशोधन) नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) ये नियम वर्ग 3 पद (समन्वय निदेशालय) पुलिस बेतार भर्ती (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वर्ग 3 पद (समन्वय निदेशालय) (पुलिस बेतार) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में क्रम संख्या 27 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किए जाएंगे :—

1	2	3	4	5	6	7	8
28	पुस्तकाध्यक्ष	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग—3 अराजपक्षित	150-10- 250-द०रो० 10-290- 15-335- द०रो०-15- 380	लागू नहीं सीधी होता भर्ती द्वारा		18-25 वर्ष

9	10	11	12	13
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की हायर सेकेण्डरी या समतुल्य परीक्षा	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दिया गया प्रमाणपत्र ।				

[सं० क० 21/20/70-बेतार (पसं-1)]

पी० के० जी० काह्लमल,

अवर सचिव ।

NOTICE

New Delhi, the 15th April 1971

S.O. 1785.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ajit Kumar Datta, Advocate, 74/1, Acharyya Jagdish Bose Road, Calcutta for appointment as a Notary to practise in Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F.22/24/70-Judl.III.]

B. SHUKLA, Competent Authority.

नोटिस

नई दिल्ली 15 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1785.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री अजीतकुमार दत्ता, अधिवक्ता 74/1, आचार्य जगदीश बोस मार्ग, कलकत्ता ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, कलकत्ता में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[संख्या 22/24/70—न्यायिक-III]

(ब्रह्मानन्द शुक्ल,)

सक्षम प्राधिकारी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1786.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following amendment in Part II of the Third Schedule to the said Act, namely:—

In the said Part of the Third Schedule, after the entry "M.D. (Manila, Philippines)", the following entry shall be inserted, namely:—

"C.M.S. (Licentiate of the State Medical Faculty, Sind, West Pakistan)".

[No. F.19-33/69-M.P.T.]

P. C. ARORA, Under Secy.

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1786.—भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय

चिकित्सा परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम, की तृतीय अनुसूची के खण्ड 2 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

तृतीय अनुसूची के उक्त खण्ड में, “एम० डी० (मनिला, फिलिपाइन्स)” की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि दर्ज की जायेगी, नामतः :—

“सी० एम० एस० (लाइसेंसियेट आर दो स्टेट मेडिकल फैकाल्टी, सिंध पश्चिम पाकिस्तान)”

[सं० फ० 19-33/68-एम० पी० टी०]

पी० सी० अरोरा, अवर सचिव ।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st May 1971

S.O. 1787.—The following modification which the Central Government proposes to make in the zonal development plan for zone D-5(D.I.Z. area—Gole Market area) is hereby published for public information. Any person may send the objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification

An area measuring about 1.46 hec. (3.63 acres) designated for Club and for the expansion of electric sub-station in the zonal development plan, bounded by about 60 meters (200') wide strip of parks and play-grounds, in the north, 13.1 meters (43') wide road in the south, 24.38 meters (80') wide Baird Road in the east and 7.85 meters (25') wide service road in the west off Market Road to be changed to residential.

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays within the period referred to above.

[No. F.3(348)/86-MP.]

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1971

एस० ओ० 1787.—निम्नलिखित संशोधन जो कि केन्द्रीय सरकार जोन डी-5 (डी० आई० जेड—एरिया—गोल मार्केट) के जोनल डवलपमेंट प्लान में करना चाहती है, आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है : यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन में कोई आपत्ति है या सुझाव देना है तो वह अपनी आपत्तियों सुझाव लिखित रूप से सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली को इस सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर भेज दें। जो व्यक्ति आपत्ति या सुझाव भेजे वह अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन

जोनल डवलपमेंट प्लान में लगभग 1.46 हेक्टेयर (3.63 एकड़) भूमि क्लब तथा इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन के विस्तार के लिये निर्दिष्ट की गई है, इसके उत्तर में लगभग 60 मीटर (200') चौड़ी पार्कस तथा खेल के मैदानों की पट्टी है, दक्षिण में 13.1 मीटर (43') चौड़ी सड़क है, पूर्व में 24.34 मीटर (80') चौड़ी बेयर्ड रोड है तथा पश्चिम में मार्केट रोड से परे 7.85 मीटर (25') चौड़ी सर्विस लेन है इस क्षेत्र को 'आवासीय' में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

2. उक्त प्रस्तावित संशोधन दर्शाते हुए प्लान निरीक्षण के लिये प्राधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के भीतर शनिवार को छोड़ कर सभी कायशील दिनों में प्राप्य होगा।

[संख्या एक० 3(348) 66-एम० पी०]

S.O. 1788.—The following modification which the Delhi Development Authority proposes to make in the zonal development plan for zone D-1 (Connaught Place and its extension) is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification

In the text of the zonal development plan in the chapter "Land use and Zoning Regulations" the sentence 'Commercial office space will not be allowed on a cinema plot, but a restaurant attached to it with facilities incidental to the cinema shall be allowed' occurring in the second sub-para (b) of para 1 headed "Cinemas", the following words shall be substituted, namely:—

"Subject to the parking requirements of prescribed standards being available, construction of office accommodation shall be allowed on cinema plots with the condition that twice the floor area utilised for cinema hall shall be deducted from the permissible F.A.R. Only the residue thereof shall be permitted for commercial offices. A restaurant attached to the cinema, with facilities incidental to the cinema, may also be allowed".

[No. F. 16(24)/71-MP.]

M. L. MONGIA, Secy.

एस० ओ० 1788.—निम्नलिखित संशोधन जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जोन डी-1 (कनाट प्लेस तथा एक्सटेंशन) के जोनल डेवलपमेंट प्लान में करना चाहता है, आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन में कोई आपत्ति है या सुझाव देना है तो वह अपनी आपत्तियां सुझाव लिखित रूप से सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली विकास भवन इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली को इस सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर भेज दें। जो व्यक्ति आपत्ति या सुझाव भेजे वह अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन :—

जोनल डेवलपमेंट प्लान में "भूमि उपयोग और क्षेत्र नियमों" के अध्याय में यह वाक्य आया है "सिनेमा भूखण्डों में व्यवसायिक कार्यालय के लिये स्थान नहीं दिया जायेगा किन्तु उससे लगा हुआ रेस्टोरेंट (जलपान गृह) हो सकेगा और उसके साथ साथ ऐसी सुविधाएं होगी जिनका सिनेमा से आनुषंगिक रूप से सम्बन्ध हैं।" उक्त वाक्य "सिनेमा" शीर्षक पैरा—1 के दूसरे उपपैरा (बी) में है, उक्त शब्दों के स्थान में नीचे लिखे शब्द होंगे :—

"सवारी गाड़ियों के ठहरने के लिये निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्थान होने पर भूखण्ड पर कार्यालय-भवन के लिये अनुमति दी जा सकेगी किन्तु शर्त यह होगी कि सिनेमा घर के लिये जितने स्थान (प्लोर) का उपयोग हुआ है उसका दुगुना एक० ए० आर० से घटा दिया जायेगा और तब जो स्थान बचेगा उसमें व्यवसायिक कार्यालय बनाये जा सकेंगे। सिनेमा घर से लगे हुए रेस्टोरेंट बनाने की भी अनुमति ऐसी सुविधाओं के साथ दी जायेगी जिनका सिनेमा घर से आनुषंगिक रूप से सम्बन्ध हो।

[संख्या एक० 16(24) 71-एम० पी०]

मदन लाल मोंगिया, सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 16th April 1971

S.O. 1789.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 9th April, 1971.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	4,82,93,000
		Rupee Coin	2,28,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	3,29,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
		(a) Internal	10,92,57,000
		(b) External	
		(c) Government Treasury Bills	9,35,91,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund .	37,00,00,000	Balances held abroad*	83,34,05,000
		Investments**	103,73,31,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	(i) Central Government
		(ii) State Governments@	414,65,64,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	270,26,15,000
(i) Central Government	352,19,72,000	(ii) State Co-operative Banks††	264,63,79,000
(ii) State Governments	4,20,57,000	(iii) Others	11,85,93,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 9th day of April 1971

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
			Gold Coin and Bullion :—		
Notes held in the Banking Department	4,82,93,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
			(b) Held outside India	
Notes in circulation	<u>4360,98,86,000</u>		Foreign Securities	<u>273,42,00,000</u>	
TOTAL Notes issued		4365,81,79,000	TOTAL		455,95,11,000
			Rupee Coin		47,17,37,000
			Government of India Rupee Securities		3862,69,31,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper
TOTAL LIABILITIES		<u>4365,81,79,000</u>	■ TOTAL ASSETS		<u>4365,81,79,000</u>

Dated the 14th day of April, 1971.

(Sd.) S. JAGANNATHAN,
Governor.
[No. F. 3(3)-BC/71]

वित्त मंत्रालय

(वैकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1789—9 अप्रैल, 1971 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वैकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	क्रास्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	4,82,93,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,28,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण—		छोटा सिक्का	3,29,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण—		(क) देशी	10,92,57,000
(स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(ख) विदेशी
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण—		(ग) सरकारी खजाना बिल	9,35,91,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	83,34,05,000
जमा राशियां —		निवेश**	103,73,31,000
		ऋण और अप्रिम :—	
(क) सरकारी—			
(i) केन्द्रीय सरकार	352,19,72,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
(ii) राज्य सरकारें	4,20,57,000	(ii) राज्य सरकारों को @	414,65,64,000
(ख) बैंक—		ऋण और अप्रिम :	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	190,75,35,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	270,26,15,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	12,57,73,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	264,63,79,000
		(iii) दूसरों को	11,85,93,000

(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	73,86,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से— ऋण, अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	31,66,000	(क) ऋण और अग्रिम	
		(i) राज्य सरकारों को	41,91,77,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,19,35,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को
(ग) अन्य		(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	9,59,42,000
देय बिल	86,17,49,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
अन्य देयताएँ	75,66,73,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	4,27,73,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से	
		ऋण, अग्रिम और निवेश	29,83,71,000
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश
	145,34,96,000	अन्य आस्तियां	47,50,24,000
		रुपये	रुपये
	1326,98,07,000		1326,98,07,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी विलों पर अग्रिम दिये गये 143,05,30,000/- रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 14 अप्रैल, 1971

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अप्रैल, 1971 की 9 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा इस विभाग

देयताएं	रुपये	क्रास्तियां	रुपये	रुपये
वैकिंग विभाग में रखे हुए नोट	4,82,93,000	सोने का सिक्का और बुलियन :— (क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000 ₹	
संचलन में नोट	43,60,98,86,000	(ख) भारत के बाहर रखा हुआ विदेशी प्रतिभूतियां	273,42,00,000	
जारी किये गये कुल नोट	4365,81,79,000	जोड़		455,95,11,000
		रुपये का सिक्का		47,17,37,000
		भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		3862,69,31,000
		देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्यपत्र		..
कुल देयताएं	4365,81,79,000	कुल क्रास्तियां		4365,81,79,000

(ह०) एस० जगन्नाथन,
गवर्नर ।

तारीख : 14 अप्रैल, 1971

[सं. फा० 3(3)-बी० सी०/71]

S.O. 1790.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply, till the 5th January, 1972, to the Cochin Commercial Bank Ltd., Cochin, in respect of the properties bearing survey Nos. 17/33/16 & 28 and measuring 10 cents held by it at Pandunagaram, Chittur Taluk, Palghat District.

[No. F. 15(5)-BC/71]

एस० ओ० 1790.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, कोचीन कर्माशियल बैंक लिमिटेड, कोचीन पर, जिनका पालास, बिजुर तालुका के पुन्नुनागराम स्थित सर्वेक्षण संख्या 17/33/16 तथा 28 की 10 सेंट्स सम्पत्तियों पर, 5 जनवरी, 1972 तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या एक० 15(5)-बी०सी० /71]

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1791.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply till the 15th March, 1972, to the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur in respect of the property (plot of land) held by it at Dholpur.

[No. F. 15(9)-BC/71.]

K. YESURATNAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1791.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, हिन्दुस्तान कर्माशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर पर जहाँ तक उनका सम्बन्ध, उसके अधीन धौलपुर स्थित सम्पत्ति भूमि (खण्ड) से है, 15 मार्च, 1972 तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या एक० 15(9)-बी० सी०/71]

के० येसुरत्तम, अवर सचिव।

(Department of Banking)

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1792.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Sankeshwar Urban Co-operative Credit Bank Ltd., Sankeshwar for a further period of one year with effect from 1st March, 1971.

[No. F. 15-6/71 AC.II.]

L. D. KATARIA, Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1792.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 के दसवें) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा

11 की उपधारा (1) के उपबन्ध दीसकेश्वर अर्बन कोओपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, संकेश्वर पर 1 मार्च, 1971 से लेकर 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[संख्या एफ० 15-6/71-ए०सी० II]

एल० डी० कटारिया, उपसचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

INSURANCE

New Delhi, the 16th March 1971

S. O. 1793—In pursuance of the provisions of sub-section (2) of Section 64F of the Insurance Act, 1938 (IV of 1938), the Central Government hereby nominates the following persons to the Executive Committee of the General Insurance Council of the Insurance Association of India namely:—

1. Shri A. Rajagopalan, Officer on Special Duty & Chairman (Under clause (a) of sub-section (2) Ex-officio Additional Secretary to the Govt. of India, Ministry of Finance, Deptt. of Revenue & Insurance, New Delhi.
2. Shri C. S. Anantapadmanabhan, Controller of Member (Under clause (a) of sub-section (2) Insurance, New Delhi.
3. Shri D. B. Whittingham, Commercial Union Member (Under clause (d) of sub-section (2) Assurance Company Ltd., 3, Middleton Street, Calcutta-16.
4. Shri H. A. Whittle, Royal Insurance Co. Ltd., Member (Under clause (d) of sub-section (2) 5 & 7, Netaji Subhas Road, Calcutta.
5. Shri H. D. R. Edwards, Royal Exchange Assurance Member (Under clause (d) of sub-section (2) 6, Lyons Range, Calcutta.
6. Shri G. V. Jannah, General Manager, Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd., Oriental Building, Mahatma Gandhi Road, Bombay. Member (Under clause (d) of sub-section (2)
7. Shri A. L. Govindarajulu, Pioneer Fire & General Insurance Co. Ltd., Coimbatore. Member (Under clause (d) of sub-section (2)

[No. F. 51(I)-Ins. 1/71].

M. L. WADHAWAN, DY. SECY.

(राजस्व और बीमा विभाग)

बीमा

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1971

क्र० आ० 1793—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64F की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय बीमा संगम की साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के लिए एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करती है, अर्थात् —

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. श्री ए० राजगोपालन | अध्यक्ष [उपधारा (2) के खण्ड (क) |
| विशेष ड्यूटी पर अधिकारी और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व और बीमा विभाग, नई दिल्ली । | के अधीन] |

- | | |
|---|---|
| 2. श्री सी० एस० अनन्तपद्मनाभन,
बीमा नियंत्रक, नई दिल्ली | सदस्य [उपधारा 2 के खण्ड (क) के
अधीन] |
| 3. श्री डी० ई० व्हिटिंगम,
कमर्शियल यूनियन एस्योरेस कम्पनी लिमिटेड,
3, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 | सदस्य [उपधारा 2 के खण्ड (ब) के
अधीन] |
| 4. श्री एच० ए० व्हिटल,
रायल इन्श्योरेस कम्पनी लिमिटेड, 5 और 7
नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता । | सदस्य [उपधारा 2 के खण्ड (घ) के
अधीन] |
| 5. श्री एच० डी० ग्रार० एडवर्डस,
रायल एक्सचेंज एस्योरेस, 6, लोईन्स रेंज,
कलकत्ता । | सदस्य [उपधारा 2 के खण्ड (घ) के
अधीन] |
| 6. श्री जी० बी० जन्नाह,
महाप्रबन्धक, ओरियेन्टल फायर एण्ड जनरल
इन्श्योरेस कम्पनी लिमिटेड, ओरिएन्टल
बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, बम्बई । | सदस्य [उपधारा 2 के खण्ड (घ) के
अधीन] |
| 7. श्री ए० एल० गोविन्दराजुलु,
पायनीयर फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेस कम्पनी
लिमिटेड, कोयम्बतूर । | सदस्य [उपधारा 2 के खण्ड (घ) के
अधीन] |

[सं० फा० 51 (1)-इंश्यो०-1/71]

मन मोहन बघावन, उप सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 31st March 1971

S.O. 1794.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 89G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Sri Kengal Eamumantharayaswamy Temple, Kengal to be a place of public worship of renown for the purpose of the said section.

[No. 105 (F.No. 176/5/71-IT(AI).]

B. MADHAVAN, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

आज्ञा

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1971

एस० प्रो० 1794—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री केंगल हनुमन्तराया स्वामी मन्दिर केंगल को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए विख्यात लोकपूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 105/फा० सं० 176/5/71-आई० टी० (ए० 1)]

बी० माधवन, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 19th April 1971

S.O. 1795.—In pursuance of the provisions of item (iii) of paragraph 15 of the Part B states (Taxation Concession) Order, 1950, read with clause (i) of sub-section (2) of Section 297 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Finance (Revenue Division) No. S.R.O. 1619, dated the 14th May, 1954, namely;

In the Table annexed to the said notification in the entries relating to S. No. 55, in Column 2, item (i), relating to Rangmahal Durbargadh including Building Grounds, stables and out houses, shall be omitted.

[No. 117/F. No. 22/21/63-ITA(II).]

S. N. NAUTIAL, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1795.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 297 उपधारा (2) के खण्ड () के साथ पठित, भाग व राज्य (कराधान रियायतें) आदेश, 1950, के पैरा 15 की मद (iii) के उपबन्धों के अनुसरण में भूतपूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) की अधिवृचना संख्या का० नि० आ० 1619, तारीख 14 मई, 1954 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिवृचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 55 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 2 में, रंगमहल दरबारगढ़, जिसमें निर्माण भूमि, अस्तबल और बहिगृह सम्मिलित हैं, से सम्बन्धित मद (i) लुप्त कर दी जाएगी।

[सं० 117/फा० सं० 22/21/63 आई० टी० ए० (ii)]

एम० एन० नोटियाल,

उप सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1796.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri M. V. Sohoni, Managing Director, Life Insurance Corporation of India, as a Member of the Life Insurance Corporation of India for the period upto 12th April, 1972 or upto the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement whichever is earlier vice Shri V. H. Vora resigned.

[No. F.1(5)-Ins.II/70.]

R. K. MAHAJAN, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1971

एस० ओ० 1796.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी० एच० वोरा के त्यागपत्र दे

देने के कारण उसके स्थान पर श्री एम० वी० सोहनी, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम को 12.4.72 तक या उस तारीख तक जिसको वह सेवा निवृत्त से पूर्व छुट्टी पर जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, को अग्रधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का सदस्य एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 1(5)-बी० II/70]

आर० के० महाजन,

उप सचिव ।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

Panjim, 19th March 1971.

S.O. 1797.—M/s. Carey & Franklin, Panjim were granted import licence No. P/E/0140984/C/XX/37/G/31-32 dated the 15th October, 1970 on General Area for the import of motor vehicle parts valued at Rs. 1,000/- under I.T.C. Sr. No. 293-95-97/IV. They have applied for duplicate copies of Custom and Exchange Control Purposes of the above mentioned licence on the ground that the original Custom and Exchange Purposes copies of the licence have been lost. It is further stated that the original Custom Purposes copy and Exchange Control copies of the licence were not registered with any Custom Authority and not utilised at all.

In support of their contention the applicants have filed an affidavit on stamped paper duly attested before the First Class Magistrate, Panjim. The undersigned is satisfied that both the copies of the original licence No. P/E/0140984/C/XX/37/G/31-32 dated 15th October, 1970 have been lost or misplaced and direct that a duplicate Custom Purposes Copy and Exchange Control Purposes copy of the said licence should be issued to the applicants.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(cc) of Import (Control) Order 1955, I order the cancellation of the original Custom Purpose copy and Exchange Control Purposes copy of the licence No. P/E/0140984/C/XX/37/G/31-32 dated 15th October, 1970.

The applicants are now being issued a duplicate copy of Custom Purpose and Exchange Control Purposes of this licence in accordance with the provisions contained in para 313(I) of the I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1970.

[No. EI/293-95-97-IV/64/AM 71.]

C. K. RAMACHANDRA RAO.

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

(उप-मुख्य निर्यात, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

पंजीम, 16 मार्च, 1971

एस० ओ० 1797.—सर्वश्री कैरी एण्ड फ्रेक्लिन, पंजीम को सामान्य क्षेत्र से आयात व्यापार नियंत्रण क्रम संख्या 293-95-97/चार के अन्तर्गत मोटर वाहन के पुर्जों के आयात के लिए 1,000 रुपये का आयात लाइसेंस संख्या पी/ई/0140984/सी/एक्स एक्स/37/जी/31-32 दिनांक 15-10-1970 स्वीकृत किया गया था उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क तथा शुद्ध विनियम नियंत्रण प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क तथा

मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं की गई थी और उनका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था ।

अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, पंजिम के समक्ष विधिवत साक्षात्कृत स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र जमा किया है अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/ई/0140984/सी/एक्स एक्स/37/जी/31/32, दिनांक 15-10-1970 की दोनों मूल प्रतियां खो गई हैं अथवा अस्थानस्थ हो गई हैं और निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि, सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिए ।

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंस संख्या पी/ई/0140984/सी/एक्स एक्स/37/जी/31-32, दिनांक 15-10-1970 की मूल सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

आवेदक को अब, आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्य विधि हैडबुक, 1970 की कड़िका 313(1) में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जा रही है ।

[संख्या ई० आई०/293-95-97-4/64/ए० एम० 71]

सी० के० रामचन्द्र राव,

उपमुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 19th March 1971

S.O. 1798.—M/s. Kesoram Rayon, Calcutta were granted licence No. P/D/2170459/C/XX/32/H/29-30 dated 8th July, 1969 for Rs. 1,85,000- for the import of Raw material/Components from General Currency Area. They have requested for issue of duplicate Exchange Purpose Copy of the licence on the ground that the original Exchange Purpose Copy has been lost by them. It has been further reported by the licensee that the licence was lost after utilising Rs. 1,48,435/-. The licence has been registered with Collector of Customs, Calcutta.

In response of their contention the applicant have filed an Affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange Purpose Copy of licence No. P/D/2170459/C/XX/32/H/29-30 dated 8th July, 1969 has been lost and directs that a duplicate Exchange Purpose Copy of the said licence should be issued to them. The Original Exchange Purpose Copy is cancelled (A duplicate Exchange Purpose Copy of the import licence is being issued separately).

[No. Rayon/5(2)/69-70/RM-6.]

SARDUL SINGH,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

(मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च 1971

एस० ओ० 1798.—सर्वश्री केसवराम रेयन, कलकत्ता को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से कच्चा माल/संघटकों के आयात के लिए 1,85,000 रुपये के लिए एक लाइसेंस सं० पी/डी/2170459/ सी एक्स एक्स/32/एच/29-30 दिनांक 8-7-69 जारी किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उन से खो गई है। लाइसेंस धारी द्वारा आगे यह सूचना दी गई है कि लाइसेंस 1,48,435 रुपये का उपयोग होने के बाद खोया गया था। लाइसेंस सीमाशुल्क समाहर्ता, कलकत्ता से पंजीकृत कराया गया है।

अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं० पी/डी/2170459/सी/एक्स एक्स/32/एच/29-30 दिनांक 8-7-69 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि उनको उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है (आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है)।

[संख्या रायन/5(2)/69-70/आर० एम०-6]

सरद्वल सिंह,

उपमुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 22nd March 1971

S.O. 1796.—Mr. Jivan Jiva Hathalia, P.O. Box 320 Tororo Uganda was granted Custom Clearance Permit No. P/J/2370612/N/MP/34/H/29-30, dated 9th March, 1970 for Rs. 5,000 for import of a 1959 Chevrolet Saloon Car has applied for a duplicate copy of the Custom clearance permit as the original Customs Clearance Permit has been lost. It is further stated that the original Customs Clearance Permit was not registered with any Custom House and not utilised.

In support of this contention Mr. Hathalia has filed an affidavit. He has undertaken to return the Custom Clearance Permit if traced later to this office for record. I am satisfied that the original Custom Clearance Permit No. P/J/2370612/N/MP/34/H/29-30, dated 9th March 1970, has been lost and direct that a duplicate Custom Clearance permit should be issued to him. The original Custom Clearance Permit may be treated as cancelled.

[No. F. 2(R-356)/69-70/BLS/256.]

K. N. KAPOOR,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

(मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च 1971

एस० ओ० 1799.—श्री जीवन जीवा हथालिया, पो० ओ० बाक्स, 320, तोरोरो, युगान्डा को एक 1959 शेवरेट सैलून कार के आयात के लिए 5000 रुपये मात्र के लिए एक सीमा शुल्क

फि कासी परमिट संख्या पी/जे/2370612/एन/एम/पी/34/एच/29-30, दिनांक 9-3-70 प्रदान किया गया था। उन्हें सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि के लिए इस लिए आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है। आगे यह उल्लिख किया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी सीमा शुल्क कार्यालय से पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका उपयोग नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में श्री हदालिया ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। उन्होंने ने बाद में सीमा शुल्क निकासी परमिट मिल जाने पर रिकार्ड के लिए कार्यालय को लौटा देने का बचन दिया है। मैं संतुष्ट हूँ कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या पी/जे/237062/एच/एम/पी/34/एच/29-30, दिनांक 9-3-70 खो गया है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट को रद्द सम्मना जाए।

[संख्या 2(आर-356)/69-70/बी० एल० एस०]

के० एन० कपूर,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 27th March 1971

S.O. 1800.—M/s. Chowgule and Co. Private Ltd. Mormagao Harbour were granted licence No. P/CG/2040161/D/WG/18/C/H/17/CG-IV, dated 29th October, 1963 for Rs. 2,09,76,552.00 for import of Pelletization Plant and Machinery from West Germany. They have requested for the issue of duplicate Exchange Control copy of the licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the licence has been lost by them. It has been further stated by the licensee that the licence was lost after being utilised for Rs. 1,77,61,023.35. The licence has been registered with Collector of Customs, Mormagao.

2. In support of their contention the licensee have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control copy of the licence No. P/CG/2040161 dated 29th October, 1963 has been lost and directs that a duplicate Exchange Control Copy of the said licence may be issued to them. The original Exchange Control Copy of the import licence is also hereby cancelled.

[No. 2A(59)/63-64/CG-IV.]

H. D. GUPTA,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आवेश

नई दिल्ली, 27 मार्च 1971

एस० ओ० 1800.—सर्वश्री चौगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, मोमगोआ हार्बर को० पश्चिम जर्मनी से पेलिटिजेशन प्लान्ट तथा मशीन के आयात के लिए 2,09,76,552 रुपये का आयात लाइसेंस संख्या पी०/सी० जी०/2040161/डी/डब्लू जी/18/सी/एच/17/सी जी—4, दिनांक 29-10-1963 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा-विनिमय-नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल-मददा विनिमय नियंत्रण प्रति उनके द्वारा खो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस के मूल्य का 1,77,61,023.35 रुपये तक उपयोग करने के पश्चात् खो गया है। लाइसेंस सीमा-शुल्क समाहर्ता, मोमगोआ के पास पंजीकृत किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र जमा किया है। अधोहस्ताक्षरी इससे संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/सी जी/2040161, दिनांक 29-10-1963 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और उन्हें उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या 2-ए (59)/63-64/सी० जी०-4]

एच० डी० गुप्ता,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च 1971

का० प्रो० 1421.—आवश्यक वस्तुएं/लोहा और इस्पात आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश 1956 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम लोहा और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 होगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 में :—

(i) खंड 4 उसके उपखंड (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) कोई व्यक्ति ऐसे स्टॉक के सिवाय जिसके लिए उसे उपखंड (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है, लोहे या इस्पात का कोई स्टॉक नहीं रखेगा” ;

(ii) खंड 7 में —

(क) “खंड 4 के उपबन्धों के अनुसार” शब्द और अंक लुप्त हो जायेंगे।

(ख) अन्त में “या ऐसे अर्जन के लिए उससे द्वारा किए गए आवेदन में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न” शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ;

(iii) खंड 9 में, “व्ययन और अर्जन” शब्दों के स्थान पर “व्ययन, कब्जा या अर्जन” शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(iv) खंड 10 में, विद्यमान टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् ;

“टिप्पण 2—लोहे और इस्पात के उन प्रवर्गों की बाबत जिन्हें इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दी जाए, इस खंड के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नियंत्रक द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वनुमोदन पर किया जायेगा ;

परन्तु यदि नियंत्रक की राय हो कि तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह, जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा किन्तु वह शक्तियों के ऐसे प्रयोग के इक्कीस दिन के भीतर इस तथ्य की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा जिस पर केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।”;

(V) खंड 11 को उसके उपखंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा, और,—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखंड (1) में, “नियंत्रक आदेश कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर “इस भाग में या लोहे या इस्पात के किन्हीं प्रवर्गों के व्ययन को शासित करने वाली शर्तों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक आदेश कर सकेगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) लोहे या इस्पात के इन प्रवर्गों की बाबत जिन्हें इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दी जाए, उपखंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नियंत्रक द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन पर ही किया जाएगा :

परन्तु यदि नियंत्रक की राय हो कि तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह, जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा किन्तु वह शक्तियों के ऐसे प्रयोग के इक्कीसवें दिन के भीतर इस तथ्य की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा, जिस पर केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे;

(VI) खंड 16 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस खंड के अधीन नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई शर्त उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से या तो असंगत, या सिंवा दी नहीं होगी” ;

(VII) खंड 17 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

“17क. उत्पादकों प्राप्ति की निवेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति.—केन्द्रीय सरकार लोहे या इस्पात के किसी प्रवर्ग के उत्पादकों और स्टाकधारियों को या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जिन्हें वह उत्पाद, स्टाक करने, प्रेषण और उत्पादकों या स्टाकधारियों पर आर्डर करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निदेश देना आवश्यक समझे, निदेश दे सकेगी कि क्या लोहे या इस्पात का ऐसा प्रवर्ग इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन के अधीन है या उसे सनसे छूट दी गई है :

17ख. समितियाँ आदि बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति (1) इस आदेश के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए लोहे या इस्पात के किसी प्रवर्ग की बाबत, कि क्या ऐसा प्रवर्ग ऐसे उपबन्धों के प्रवर्तन के अधीन है या उसे सनसे छूट दी गई है, केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर ऐसी

समितियां, निकाय या प्राधिकारी स्थापित या नियुक्त कर सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे :

- (2) उपखंड (1) के अधीन स्थापित समिति, निकाय या नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कृत्य करेगा जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों, जिसके अधीन ऐसी समिति, निकाय या प्राधिकारी की स्थापना या नियुक्ति की गई हो”

(VIII) खंड 22 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् .

“22, सीधे विक्रय की शक्ति—(1) नियंत्रक, लिखित आदेश द्वारा, स्टॉक का स्टाक धारण करने वाली किसी व्यक्ति से, चाहे उसने वह खंड 18 के उपबन्धों के अनुसार या अन्यथा अर्जित किया हो स्टॉक को संग्रह या कोई भाग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं विक्रीत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

- (2) स्टॉक के उन प्रवर्गों की बाबत जिन्हें इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों से तत्समय छूट दी जाए, उपखंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किया जायेगा ।

परन्तु यदि नियंत्रक की राय हो कि तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह, जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कर सकेगा किन्तु वह शक्तियों के ऐसे प्रयोग के इक्कीसवें दिन के भीतर इस तथ्य की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा जिस पर केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।”

(IX) खंड 23 उसके उपखंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

- “(2) स्टॉक के उन प्रवर्गों की बाबत जिन्हें इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्धों से तत्समय छूट दी जाए, उपखंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नियंत्रक द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन पर ही किया जायेगा :

परन्तु यदि नियंत्रक की राय हो कि तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो, वह जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, ऐसी शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कर सकेगा । किन्तु वह शक्तियों के ऐसे प्रयोग के इक्कीस वीन के भीतर इस तथ्य की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा जिसपर केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे ।”

[सं० फा० एस० सी० (1) 9(1)/69]

एम० प्रसाद, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

New Delhi, the 20th March 1971

S.O. 1801.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the

following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 1971.

(2) Regulations 2 and 3 shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1969 and regulations 4 and 5 shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, clause (c) shall be omitted.

3. In the said regulations, for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

"7. Subscriber to the Fund.—Every employee of the Corporation shall subscribe to the Fund from the date of his joining the service under the Corporation:

Provided that any person in receipt of remuneration from the Corporation other than casual remuneration may subscribe to the fund if so permitted by the Committee."

4. In the said regulations, after regulation 14, the following regulation shall be inserted, namely:—

"14A. Withdrawal from the Fund.—Subject to the conditions specified herein, withdrawals may be sanctioned by the Committee for special reasons at any time after the completion of twenty years of service (including broken period of service, if any, and the service, if any, rendered, while in the Government service, before his permanent absorption in the service of the Corporation) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely:—

- (a) Meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of any child of the subscriber in the following cases, namely:—
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years.
- (b) Meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's sons or daughters and if he has no daughter, of any other female relation dependent on him.
- (c) Meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber or any person actually dependent on him.
- (d) Building or acquiring a suitable house for his residence including the cost of the site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date, or reconstructing, or making additions or alterations to a house already owned or acquired by a subscriber.
- (e) Purchasing a house-site or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose before the date of receipt of the application for withdrawal but not earlier than twelve months of that date.
- (f) For constructing a house on a site purchased utilising the sum withdrawn under clause (e):

Provided that a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Department of Works, Housing and Urban Development, for the grant of advances for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other Government source, shall not be eligible for the grant of final withdrawal under clause (d), (e) and (f) except for the express purpose of repayment of any loan taken under the afore-said Scheme.

- (2) Any sum withdrawn by a subscriber at one time for one or more of the purposes specified in sub-regulation (1) from the amount standing to his credit in the Fund shall not exceed two-thirds of such amount. The Committee may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto three-fourths of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount standing to his credit in the Fund.
- (3) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under this sub-regulation (1) shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum together with interest thereon by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the sanctioning authority."

5. In sub-regulation (2) of regulation 15 of the said regulations, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

- "(b) the subscriber voluntarily leaves his employment otherwise than on account of ill health or other unavoidable causes before the expiration of the term of his service or within five years of his entry into the service of the Corporation (including service, if any, rendered while in the Government service before his permanent absorption in the service of the Corporation), as the case may be."

Explanatory Memorandum

Regulation 3 of the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 1971, is intended to bring regulation 7 of the Central Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulations, 1962, *on par with the rule in this behalf applicable to non-pensionable servants of the Central Government* and is being given effect to from the 1st August, 1969, i.e., the month following in which it was decided to make this amendment. The omission of clause (c) of regulation 3 of the principal regulations is only consequential. The employees of the Corporation had been demanding this for quite some time. Thus, the interests of any person already in the service of the Corporation will not be prejudicially affected by reason of the retrospective operation of regulations 2 and 3 of these regulations.

[No. F. 26-8/67-SC.II.]

M. SHAMS-UD-DIN, Under Secy.

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(लाघ विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1971

का०प्र० 1801.—भाण्डागारण नियम—अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, केन्द्रीय भाण्डागारण निगमकर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) विनियम 2 और 3 अगस्त, 1969 के प्रथम दिन से प्रवृत्त समझे जायेंगे और विनियम 4 और 5 शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में विनियम 3 में खण्ड (ग) सप्त कर दिया जायगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

7. “निधि में अंशदायक :—निगम का हर एक कर्मचारी निगम के अधीन सेवा में आने की तारीख से निधि में अंशदाय करेगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो निगम से आकस्मिक पारिश्रमिक से भिन्न पारिश्रमिक पाता है, यदि समिति वैसे अनुज्ञा दे तो निधि में अंशदाय कर सकेगा।”

4. उक्त विनियमों में, विनियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

“14—क निधि में से धन निकालना :—इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन, समिति अंशदायी के बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् (जिसमें निगम की सेवा में उसके स्थायी रूप से शामिल किए जाने से पूर्व का खंडित सेवाकाल, यदि कोई हो, और सरकारी सेवा के दौरा की गई सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित है) या अधिवृत्ति पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से दस वर्ष के भीतर, इनमें जो भी पहले पड़े, किसी भी समय, विशेष कारणों से यह मंजूरी दे सकेगी कि निधि में अंशदाय के नाम जमा रकम में से निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से धन निकाला जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) अंशदायक के किसी बालक की उच्चशिक्षा के व्यय, जिसमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ उस बालक के यात्रा-व्यय भी सम्मिलित हैं, को निम्नलिखित दशाओं में पूरा करना अर्थात् :—

(i) हाई स्कूल स्तर से आगे के शैक्षणिक, तकनीकी, वस्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम की भारत से बाहर शिक्षा के लिए, और

(ii) भारत में हाई स्कूल स्तर से आगे के चिकित्सा, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह तब जब अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो।

(ख) अंशदायक के पुत्रों या पुत्रियों के और यदि उसकी कोई पुत्री नहीं है तो किसी अन्य स्त्री नातेदार के, जो उस पर आश्रित है, विवाह के सम्बन्ध में—व्ययों को पूरा करना।

(ग) अंशदायक की या किसी अन्य व्यक्ति की जो उस पर वस्तुतः आश्रित है, बीमारी के सम्बन्ध में व्ययों को जिनमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ यात्रा व्यय भी सम्मिलित है, पूरा करना।

(घ) अपने निवास के लिए उपयुक्त गृह बनाना या अर्जित करना जिसमें स्थल की लागत या किसी बकाया रकम की वापसी भी सम्मिलित है, जो धन निकालने के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व, किन्तु उस तारीख से बारह मास से पूर्व नहीं इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिये गए ऋण भद्दे हों, या पहले से ही अंशदायक के स्वामित्व वाले उसके द्वारा अर्जित गृह का पुनर्निर्माण करना या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन कराना।

- (ङ) गृह स्थल खरीदना या किसी ऐसी बकाया रकम की वापसी जो धन निकालने के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व, किन्तु उस तारीख से बारह मास से पूर्व नहीं, इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त रूप से लिए गए ऋण बन्ध हो।
- (च) ऐसे स्थल पर, जिसे खण्ड (ड) के अधीन निकाली गई राशि को उपयोग में लाकर खरीदा गया हो गृह का निर्माण :

परन्तु वह अंशदायक जिसने निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग की गृह निर्माण प्रयोजन के लिए उधार देने की स्कीम के अधीन उधार लिया है, या जिसे किसी अन्य सरकारी ज़ोनों से इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी गई है, खण्ड (घ) (ड) और (च) के अधीन अन्तिम रूप से धन निकालने की मंजूरी के लिए, पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए किसी ऋण को वापस करने के अभिव्यक्त प्रयोजन के सिवाय, पात्र नहीं होगा।

- (2) निधि में अंशदायक के नाम जमा रकम में से उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एक समय में उसके द्वारा निकाली गई राशि ऐसी जमा रकम की दो तिहाई से अधिक नहीं होगी। फिर भी, समिति (i) जिस उद्देश्य के लिए धन निकाला जा रहा है उसे (ii) अंशदायक की हैसियत को और (iii) निधि में उसके नाम जमा रकम की सम्यक रूप में ध्यान में रखते हुए इस सीमा से अधिक किन्तु निधि में उसके नाम जमा अतिशेष की तीन चौथाई रकम तक निकाले जाने के मंजूरी दे सकेगी।

- (3) वह अंशदायक जिसे उपविनियम (1) के अधीन निधि में से धन निकालने की अनुज्ञा दी गई है, मंजूरकर्ता प्राधिकारी का ऐसी यक्तियुक्त अभिष्टि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए यह समाधान करायगा कि धन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह निकाला गया था और यदि वह ऐसा नहीं करता तो अंशदायक द्वारा इस प्रकार निकाली गई कुल राशि या उसका उतना भाग, जो उस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है जिसके लिए वह निकाला गया था, निधि में एक मुश्त राशि के रूप में, उस पर ब्याज सहित तुरन्त वापस कर दिया जायगा और ऐसी वापसी न किए जाने पर उसे मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी उपलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी मासिक किश्तों में जितनी मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, वसूल करने का आदेश दिया जायगा।”

5. उक्त विनियमों के विनियम 15 के उपविनियम (2) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) अंशदायक ऐसे कारणों से, जो अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारणों से भिन्न हों, यथास्थिति, अपनी सेवावधि के अवसान से पूर्व या निगम की सेवा में आने से पांच वर्ष के भीतर (जिसमें निगम की सेवा में उसके स्थायी रूप से आमेलित किए जाने से पूर्व सरकारी सेवा के दौरान की गई सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित है) अपनी नौकरी स्वेच्छापूर्वक छोड़ देना है।”

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1971 के विनियम 3 का आशय केन्द्रीय भाण्डागारण निगम कर्मचारी भविष्य निधि, विनियम, 1962

के विनियम 7 को इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के पेंशन आयोध्य सेवकों को लागू नियम के स्तर पर लाना है और इसे 1 अगस्त 1969 से अर्थात् उस मास से अगले मास से जिसमें यह संशोधन कर का विनिश्चय किया गया था। प्रभावी किया जा रहा है। मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (ग) का लीप केवल पारिणामिक है। विगम के कर्मचारी इसकी मांग बहुत पहिले से कर रहे थे। अतः निगम की पहिले से ही सेवा कर रहे किसी व्यक्ति के हितों पर इस विनियमों के विनियम 2 और 3 के प्रवर्तन को भूतलक्षी प्रभाव देने के कारण कोई प्रतिकूल प्रभावी नहीं पड़ेगा।

[सं० फा० 26-8/67-एस० जी० II]

मु० रामसुद्धीन, अवर सचिव ।

(Department of Cooperation)

New Delhi, the 27th March 1971

S.O. 1802.—In exercise of the powers conferred by section 5B of the Multi-Unit Co-operative Societies Act, 1942 (6 of 1942), and in supersession of all previous notifications on the subject, the Central Government hereby directs that all the powers and authority exercisable by the Central Registrar of Cooperative Societies under the said Act, shall in relation to the cooperative societies specified in column (2) of the Table below, be exercisable also by the officers specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, subject to the following conditions, namely:—

- (1) that the powers and authority so delegated shall in respect of the following co-operative societies be exercisable by the said officers only in relation to matters pertaining to audit, settlement of disputes, appeals, revision and review and execution of awards, decisions, decrees and orders:

1. All India Central Land Development Banks' Cooperative Union Limited, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2. All India State Cooperative Banks' Federation Limited, Bombay, Maharashtra.
3. National Cooperative Union of India Limited, Delhi.
4. National Agricultural Cooperative Marketing Federation Limited, Delhi.
5. National Cooperative Consumers' Federation Limited, Delhi.
6. National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited, Delhi.
7. National Federation of Industrial Cooperatives Limited, Delhi.
8. National Cooperative Housing Federation Limited, Delhi.
9. Indian Farmers' Fertiliser Cooperative Limited, Delhi.

- (2) that in the exercise of the powers and authority so delegated in relation to the matters specified in (1) above (other than appeals, revision and review), the said officers shall comply with such directions as may be issued by the Central Registrar of Cooperative Societies.

TABLE

Officers	Multi-unit cooperative societies
1	2
1 Registrar of Co-operative Societies for the State of Andhra Pradesh appointed under section 3 of the Andhra Pradesh Co-operative Societies Act, 1964.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Andhra Pradesh.
2 Registrar of Co-operative Societies for the State of Assam appointed under section 3 of the Assam Co-operative Societies Act, 1949	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Assam.
3 Registrar of Co-operative Societies for the State of Bihar appointed under section 6 of the Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, 1935.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Bihar.
4 Registrar of Co-operative Societies for the State of Gujarat appointed under section 3 of the Gujarat Co-operative Societies Act, 1961.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Gujarat.
5 Registrar of Co-operative Societies for the State of Haryana appointed under section 3 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the State of Haryana.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Haryana.
6 Registrar of Co-operative Societies for the State of Himachal Pradesh appointed under section 3 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1956.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Himachal Pradesh.
7 Registrar of Co-operative Societies for the State of Kerala appointed under section 3 of the Kerala Co-operative Societies Act, 1969.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Kerala.
8 Registrar of Co-operative Societies for the State of Madhya Pradesh appointed under section 3 of the M. P. Co-operative Societies Act, 1960.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Madhya Pradesh.
9 (i) Registrar of Co-operative Societies for the State of Maharashtra appointed under section 3 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960. (ii) Divisional Joint Registrar of Co-operative Societies, Bombay Division, Bombay.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Maharashtra.
10 Registrar of Co-operative Societies for the State of Mysore appointed under section 2A of the Mysore Co-operative Societies Act, 1959.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Mysore.
11 Registrar of Co-operative Societies for the State of Orissa appointed under section 3 of the Orissa Co-operative Societies Act, 1962.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Orissa.
12 Registrar of Co-operative Societies for the State of Punjab appointed under section 3 of the Punjab Co-operative Societies Act 1961.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Punjab.
13 Registrar of Co-operative Societies for the State of Rajasthan appointed under section 3 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965.	All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Rajasthan.

- | | |
|---|--|
| <p>14 (i) Registrar of Co-operative Societies for the State of Tamil Nadu appointed under section 3 of the Tamil Nadu Co-operative Societies Act, 1961.</p> <p>(ii) Joint Registrar of Co-operative Societies (Intensive Agricultural Area Programme), Tamil Nadu, Madras.]</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Tamil Nadu.</p> |
| <p>15 Registrar of Co-operative Societies for the State of Uttar Pradesh appointed under section 3 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of Uttar Pradesh.</p> |
| <p>16 (i) Registrar of Co-operative Societies for the State of West Bengal appointed under section 9 of the Bengal Co-operative Societies Act, 1940.</p> <p>(ii) Additional Registrar of Co-operative Societies, West Bengal, Calcutta.]</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the State of West Bengal.</p> |
| <p>17 Registrar of Cooperative Societies for Chandigarh appointed under section 3 of the Punjab Cooperative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory of Chandigarh.</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union territory of Chandigarh.</p> |
| <p>18 Registrar of Co-operative Societies for Delhi appointed under section 4 of the Bombay Co-operative Societies Act, 1925 as extended to Delhi.</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union territory of Delhi.</p> |
| <p>19 Registrar of Co-operative Societies for Goa, Daman and Diu, appointed under section 3 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, as applied to the Union territory of Goa, Daman & Diu.</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union territory of Goa, Daman and Diu.</p> |
| <p>20 Registrar of Co-operative Societies for Manipur appointed under section 3 of the Assam Co-operative Societies Act, 1949, as extended to Manipur.</p> | <p>All multi-unit cooperative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union territory of Manipur.</p> |
| <p>21 Registrar of Co-operative Societies for Pondicherry appointed under section 3 of the Pondicherry Co-operative Societies Act, 1965.</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union territory of Pondicherry.</p> |
| <p>22 Registrar of Co-operative Societies for Tripura appointed under section 4 of the Bombay Co-operative Societies Act, 1925, as extended to Tripura.</p> | <p>All multi-unit co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in the Union territory of Tripura.</p> |
| <p>23 (i) The Director of Industries and Commerce, Tamil Nadu.</p> <p>(ii) The Joint Director of Industries and Commerce, Tamil Nadu.</p> | <p>All multi-unit Industrial co-operative societies which actually are or are deemed to be registered in Tamil Nadu.</p> |

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1971

एस० ओ० 1802.—बहुएकक सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1942 (1942 का 6) की धारा 5ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्व अधिसूचनाओं की अधिकांश करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रयोक्तव्य प्राधिकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सहकारी सोसाइटियों के संबंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोक्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(1) कि निम्नलिखित सहकारी सोसाइटियों की बाबत इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियां और प्राधिकार उक्त अधिकारियों द्वारा केवल संपरिक्षा, विवादों का निपटारा, अपील पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन और पंचादों, विनिश्चयों, शिष्टियों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित मामलों के संबंध में प्रयोक्तव्य होंगे :

1. अखिल भारतीय केन्द्रीय भूमि विकास बैंक सहकारी संघ लिमिटेड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2. अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र ।
3. भारतीय सहकारी संघ लिमिटेड, दिल्ली ।
4. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली ।
6. राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली ।
7. राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली ।
8. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली ।
9. भारतीय कृषक उरवर्क सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली ।

(2) कि उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट मामलों (अपील पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन विषय) से संबंधित इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जैसे कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए जाएं ।

सारणी

क्रम सं०	अधिकारी	बहुएकक सहकारी सोसाइटियां
1		2
1	आन्ध्र प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी ।	वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।

- | | | |
|-------|--|---|
| 2 | असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन नियुक्त असम राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो असम राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 3 | बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 6 के अधीन नियुक्त, बिहार राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो बिहार राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 4 | गुजरात सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त गुजरात राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो गुजरात राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 5 | हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त हरियाणा राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो हरियाणा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 6 | हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो हिमाचल प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 7 | केरल सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अधीन नियुक्त केरल राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो केरल राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 8 | मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त मध्य प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| 9 (i) | महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त महाराष्ट्र राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । | वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो महाराष्ट्र राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं । |
| (ii) | मध्य प्रदेश संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, मुम्बई मण्डल, मुम्बई । | |

1

2

- 10 मैसूर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1969 की धारा 2क के अधीन नियुक्त मैसूर राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो मैसूर राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 11 उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अधीन नियुक्त उड़ीसा राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो उड़ीसा राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 12 पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त पंजाब राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो पंजाब राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 13 राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1965 की धारा 3 के अधीन नियुक्त राजस्थान राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो राजस्थान राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 14 (i) तमिल नाडू सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, तमिल नाडू राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो तमिल नाडू राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- (ii) संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी (सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम) तमिल नाडू मद्रास ।
- 15 उत्तर प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन नियुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो उत्तर प्रदेश राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 16 (i) बंगाल सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1940 की धारा 9 के अधीन नियुक्त पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी ।
- (ii) अपर रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो पश्चिमी बंगाल राज्य में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।

- 17 पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 जैसा चन्डीगढ़ राज्य क्षेत्र में प्रबल है, की धारा 3 के अधीन नियुक्त चन्डीगढ़ के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो चन्डीगढ़ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 18 दिल्ली पर यथा विस्तारित मुम्बई सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 की धारा 4 के अधीन नियुक्त दिल्ली के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 19 गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में लागू महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अधीन नियुक्त गोवा, दमन और दीव के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 20 मणिपुर पर यथा विस्तारित असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन नियुक्त मणिपुर के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 21 पांडिचेरी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अधीन नियुक्त पांडिचेरी के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी : वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 22 त्रिपुरा पर यथा विस्तारित मुम्बई सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1925 की धारा 4 के अधीन नियुक्त त्रिपुरा के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- 23(i) निदेशक उद्योग और वाणिज्य, तामिल-नाडू । वे सभी बहुएकक सहकारी सोसाइटियां जो तामिल नाडू में वास्तविक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हैं ।
- (ii) संयुक्त निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, तामिल नाडू :

[सं० एल० 11011/2/70—की आर्ड]

स० सत्यभामा, उप सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 16th April 1971

S.O. 1803.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to Messrs Shantilal Khushaldas and Brothers, Vasco-da-Gama and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st March, 1971.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY.

REFERENCE No. CGIT-17 of 1968

PARTIES:

Employers in relation to M/s. Shantilal Khushaldas and Bros. Vasco-da-Gama

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri A. T. Zambre, Presiding Officer.

STATE.—Union Territory of Goa. **INDUSTRY:** Stevedoring Major Ports and Docks.

Bombay dated 22nd March 1971

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, have by their Order No. 29(5)/68-LR/II dated 27th July 1968 referred to this Tribunal for adjudication an industrial Dispute existing between the employers in relation to M/s. Shantilal Khushaldas and Brothers, Vasco-da-Gama and their workmen in respect of the matter specified in the schedule thereto annexed.

SCHEDULE

“Whether the following demands of the office staff engaged in the stevedoring-cum-shipping work of Messrs. Shantilal Khushaldas and Brothers, Vasco-da-Gama are justified? If so, to what relief are they entitled, and from what date?”

- (i) The existing scales of pay should be revised.
- (ii) Dearness allowance and Interim Relief should be paid as per the recommendations of the Central Wage Board for Port and Dock Workers.
- (iii) The staff should be paid house rent allowance.
- (iv) The staff should be granted National Holidays and Port Trust holidays as enjoyed by the staff of the Port.
- (v) The staff should be granted 30 days privilege leave, which should be allowed to accumulate upto 90 days, 20 days sick leave and 12 days casual leave per year.
- (vi) The staff and their families should be entitled to free medical attention.
- (vii) Bonus should be paid as per the Payment of Bonus Act, 1965.
- (viii) A scheme of gratuity should be introduced by which every employee who has put in 5 years of service should be paid 15 days wages per year and those who have put in 10 years and 15 years of service should be paid 20 days and 30 days wages respectively as gratuity.
- (ix) The staff should be paid overtime at double the ordinary rates, particularly Drivers, Peons, for duty beyond 8 hours.”

2. After the receipt of this reference order on 22nd August 1968 the first notice to the parties was issued on 28th August 1968 requiring them to file their written statements relating to the issues within two weeks of the notice and fixing the first hearing of the dispute on 7th November 1968. However, the parties did not file any written statement nor did they appear before this tribunal.

3. Subsequently, various notices were issued but neither party appeared or filed any statement. Ultimately the Tribunal issued a notice to both the parties dated

17th September 1970 fixing the hearing at Panjim on 28th September 1970 specially mentioning in the notice that the reference order was dated 27th July 1968 and various notices had been issued to the parties but they had neither attended the proceedings nor had filed any written statement so far and it appeared that they were not interested and the matter was therefore fixed for final hearing and in case the parties failed to attend the matter **would be heard and decided *ex-parte* on the basis of the material available on record.** In spite of this notice the parties did not appear nor did they file any statement. But again a chance was given to the parties to appear in the proceedings and notice dated 3rd March 1971 fixing the hearing on 18th March 1971 was issued. But they have not appeared nor have they filed any statement or made any request for adjournment and it appears that the parties are not interested in the dispute.

4. The reference order shows that the workmen had raised various demands in respect of their terms and conditions of service. There were about nine demands and the fact that they have not put forth any statement of claim shows that they are not interested. They have not filed any statement nor have they applied for adjournment of the hearings. They have not also appeared at any time. It therefore appears that the parties are not interested in the reference and there is no dispute subsisting between them. Hence my award accordingly.

No order as to costs.

(Sd.) A. T. ZAMBRE

Presiding Officer.

[No. 29/5/68-LR.III/P&D.]

S.O. 1804.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (No. I) Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st March, 1971.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT DHANBAD

In the matter of a Reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947).

REFERENCE No. 56 OF 1968

PARTIES:

Employers in relation to the Calcutta Port Commissioner, Calcutta.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers.—Shri G. V. Karlekar, Chief Labour Officer.

For the Workmen.—Shri Makhan Chatterjee, General Secretary, Calcutta Port Sharmik Union.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Dock/Port.

Dhanbad, dated, the 23rd March, 1971.

AWARD

The following dispute has been referred to this Tribunal under Section 10(2) of the Industrial Disputes Act:—

SCHEDULE

“Whether the claim for promotion of Shri Batukeswar Banerjee, Tindal, Crane Vessel to the post of Crane Driver of Crane Vessel on and from the 21st March, 1964 was justified? If so, what should be the relief?”

2. The reference was made by the Central Government by its Order No. 23/51/68-LRIII dated the 9th July, 1968, and the said order was received in this Tribunal on 18th July 1968.

3. The facts are not disputed and they lie within a narrow compass. Shri Batukeswar Banerjee, the workman concerned, while working as Fireman (promoted to temporary greaser) applied by a letter on 7th February 1964 for the inclusion of his name as a candidate for one of the vacancies of crane trainees. The said letter was addressed to the Chief Mechanical Engineer, Calcutta Port Commissioners. Para 1 of the letter runs as follows: "In connection with your circular No. M/1904 of 5th February 1964 I beg to offer myself as a candidate for one of the vacancies of Crane Trainees. I am working in the capacity of Fireman."

4. The Board held a trade test for the selection of the candidates for the posts of crane driver's trainees on the crane vessel 'Virbahu' on 24th February 1964. Batukeswar Banerjee refused to appear at the trade test. The report submitted by the Board shows that in the trade test held on 24th February 1964, out of 13 candidates, 6 appeared at the test and 7 others including Batukeswar Banerjee refused to appear at the test, and only three candidates, viz., Sankarpada Mazumdar, Fireman, C. V. Atlas, Nikhil Krishna Biswas, Fireman, C. V. Atlas and Ranjit Kumar Das, Engine room Tindal, C. V. Samson passed the trade test.

5. Those who refused to appear including Batukeswar Banerjee at the trade test held on 24th February 1964 later on changed their mind and made a request for another chance to appear at the trade test. Another trade test was held at their request for the selection of candidates for the posts of crane trainees. After a theoretical test on 28th February 1964 and a practical test on 1st March 1964 Batukeswar Banerjee was found suitable for the post of a crane trainee along with two others. Thereafter Batukeswar Banerjee along with others was posted as a crane trainee.

6. After the training these crane driver's trainees were trade tested to find out their suitability for appointment to the posts of crane drivers. The first trade test was held on 21st March 1964. At this test Batukeswar Banerjee failed to qualify. Only one candidate, viz., Sankar Pada Majumdar was found suitable. At the subsequent test held on 6th May 1964 Nikhil Krishna Biswas was found suitable and at another test held on 9th September 1964 all the candidates including Batukeswar Banerjee got plucked. Thereafter by a letter dated 29th September 1964 Batukeswar Banerjee and another were asked to take keen interest in learning the job of crane driver so as to pass the trade test within two months from the date and were further informed that otherwise their names would be removed from the posts of crane driver's trainee. Subsequently at a trade test held on 9th December 1964 Batukeswar Banerjee along with Bhibhuti Bhusan Paul passed the test.

7. Batukeswar Banerjee submitted a petition to the Chief Mechanical Engineer, on 18th March, 1964 complaining against the posting of two of the junior men, Sankarpada Mazumdar and Nikhil Kumar Biswas as crane Drivers in supersession of his claim. Last two paragraphs of the said petition run thus:

"That amongst the 4 crane Trainees including myself I am the senior most one. But to my utter surprise it is noted that 2 junior men have been posted to work as Crane Drivers superseding me.

Under the circumstances I shall be highly obliged if you will kindly look into the matter and arrange for my posting as a Crane Driver which is my legitimate claim being the senior most one."

8. It is not disputed that Sankarpada Mazumdar, one of the crane driver's trainees, passed the trade test for the selection of crane drivers from among the trainees on 21st March 1964 and Nikhil Kumar Biswas passed a similar test on 6th May 1964. It is also not disputed that Batukeswar Banerjee passed a similar test at the third chance on 9th December 1964.

9. It is the common case that the question of promotion in this case is to be decided in accordance with the rules laid down in the award of the Central Government Industrial Tribunal at Calcutta (Das Gupta Tribunal) given in Reference No. 1 of 1956. In support of the claim of Batukeswar Banerjee Mr. Chatterji appearing on behalf of the workmen referred to the following rules laid down in the said award:

"27(b). Vacancies in higher grades shall be filled up from among the lower grades. Direct recruitment to the higher grades may be resorted to only when suitable persons are not available from among the workmen in the lower grades.

27(c)...Promotion to a post shall be from the grade just below and the claim of workmen further down shall be considered only when a suitable man is not available from the grade just below."

Reference was made to this rule to indicate the suitability of Batukeswar Banerjee for the post of a crane driver, because all the relevant time he was not in a grade just below the post of a crane driver. I may point out that the employers too do not dispute the suitability of Batukeswar Banerjee for the post of a crane driver. The only question involved in this case is whether he should have been appointed a crane driver with effect from 21st March 1964 in preference to Sankarpada Mazumdar. The relevant rule for this purpose is contained in clauses (e), (f) and (g) of rule 27 of the rules laid down in the Award in Reference No. 1 of 1956. Those clauses are quoted below:

"(e) The existing practice of holding tests to determine suitability of persons for a job shall continue.....

(f) If at a particular test more workmen than what are required are found suitable for a job, those who could not be taken in at the time shall be placed in a waiting list in order of seniority and shall be called upon to fill up vacancies as and when they crop in future. A list of successful candidates indicating the names of those who have been taken in and of those who are in the waiting list shall be posted on the Notice Board of the Recruiting Office.

(g) A workman once passed over shall not be debarred permanently for promotion. He may be admitted to a subsequent test and if he passes the test, he will be considered for promotion only after all the persons who had passed the previous tests as well as those who are senior to him and have qualified at the subsequent test been absorbed."

10. At the test held on 21st March 1964, Sankarpada Mazumdar alone passed and Batukeswar Banerjee failed to qualify. Therefore on 21st March 1964 Batukeswar Banerjee could not claim to be appointed as a crane driver in preference to Sankarpada Mazumdar even if it be conceded that on that date he was senior to Sankarpada Mazumdar. I am, therefore, constrained to hold that the claim for promotion of Batukeswar Banerjee to the post of Crane Driver of Crane Vessel on and from the 21st March, 1964 was not justified. That being the position he is not entitled to any relief. It transpires from the service book of Batukeswar Banerjee that he acted as a crane driver for 10 days from 4th September 1964 to 13th September 1964 prior to his passing the trade test. But that is wholly irrelevant to the present dispute.

11. My award, therefore, is as follows. The claim for promotion of Batukeswar Banerjee to the post of Crane Driver of Crane Vessel on and from the 21st March, 1964 was not at all justified and consequently he is not entitled to any relief.

12. A copy of this award may be forwarded to the Central Government under Sec. 15 of the Industrial Disputes Act.

(Sd.) A. C. SEN,

Presiding Officer.

[No. 28/51/68-LR.III/P&D.]

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1805.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:—

1. This Scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971.

2. In clause 45 of the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 (hereinafter referred to as the said Scheme), for item (b) of sub-clause (3) the following item shall be substituted, namely:—

"(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were

on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances."

3. In clause 46 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (4-A) the following item shall be substituted, namely:—

"(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances."

4. In clause 51 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (3-A) the following item shall be substituted namely:—

"(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances."

[No. 528/183/65-Fac. II/P & D.]

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 1971

का० आ० 1805—डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मद्रास डांक कर्मकार-नियोजन का विनियमन) स्कीम 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. स स्कीम का नाम मद्रास डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1971 होगा।

2. मद्रास डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है, () के र _____ की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिसे

"(ख) जहाँ किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन _____ गया हो, वहाँ उसे निम्नलिखित की तारीख _____

उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के लिये आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात अध्यक्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो।

परन्तु जहां ऐसी जांच, ऐसे कारणों से, जिन के लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर, आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 46 में, उपखण्ड (4-क) की मद (क) के स्थान पर निम्न-लिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो ;

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से जिन के लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्त को घटा कर आधारिक मजदूरी महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

4. उक्त स्कीम के खण्ड 51 में उपखण्ड (3-क) की मद (क) के स्थान पर निम्न-लिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो ।

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिन के लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

S.O. 1806.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:—

1. This Scheme may be called the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971.

2. In clause 44 of the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 (hereinafter referred to as the said Scheme), for item (b) of sub-clause (3) the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourth of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

3. In clause 45 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (5) the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

4. In clause 50 of the said scheme, for item (a) of sub-clause (3)(iii) the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

[No. 528/183/65-Fac. II/P & D.]

का० प्र० 1806.— डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मुम्बई छंटाई और रंगाई कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही काशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम मुम्बई छंटाई और रंगाई कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1971 होगा।

2. मम्बई छंटाई और रंगाई कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खण्ड 44 में उपखण्ड (3) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“(ख) जहां किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया हो वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर, आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 45 में, उपखण्ड (5) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

4. उक्त स्कीम के खण्ड 50 में उपखण्ड (3) (iii) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसी उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधार्तिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक

की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारीक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

[सं० 528/183/65-फैक० 2/पी एंड डी]

S.O. 1807.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:

1. This Scheme may be called the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971.

(2) In clause 44 of the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 (hereinafter referred to as the said Scheme), for item (b) of sub-clause (3) the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

3. In clause 45 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (4-A) the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

4. In clause 50 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (3-A), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

[No. 528/183/65-Fac.II/P&D.]

का० आ० 1807—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1971 होगा।

2. मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खण्ड 44 में, उपखण्ड (3) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) जहां किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अध्यक्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच, ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटाकर, आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा ।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 45 में, उपखण्ड (4-क) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर, आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा ।”

4. उक्त स्कीम के खण्ड 50 में, उपखण्ड (3-क) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अध्यक्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो ।

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा ।”

S.O. 1808.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:—

1. This scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971.

2. In clause 46 of the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 (hereinafter referred to as the said Scheme), for item (b) of sub-clause (3), the following item shall be substituted namely:—

“(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

3. In clause 47 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (5), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances;

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

4. In clause 53 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (2)(iii), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

[No. 528/165/65-Fac. II/P&D.]

का० आ० 1808.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1971 होगा।

2. कान्डला डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खण्ड 46 में, उपखण्ड (3) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(ख) “जहां किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी, सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो।

परन्तु जहां ऐसा जांच, ऐसे कारणों से जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 47 में, उपखण्ड (5) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उस के पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

4. उक्त स्कीम के खण्ड 53 में, उपखण्ड (2) (iii) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अध्यक्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो।

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

S.O. 1809.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1959, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:—

1. This scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) First Amendment Scheme 1971.

2. In clause 44 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 (hereinafter referred to as the said Scheme, for item (b) of sub-clause (3), the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

3. In clause 45 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (4-A), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

4. In clause 50 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (2)(iii), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

[No. 528/183/67-Fac. II/P&D.]

का० प्रा० 1809.—डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विशाखापत्तनम डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) प्रथम संशोधन स्कीम, 1971 होगा।

2. विशाखापत्तनम डांक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खण्ड 44 में उपखण्ड (3) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) जहां किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अध्यक्ष, आसाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच, ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर, आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 45, उपखण्ड (4-क) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष आसाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो।

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर, आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों का एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

4. उक्त स्कीम के खण्ड 50 में, उपखण्ड (2) (iii) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष, आसाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

S.O. 1810.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:—

1. This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971.

2. In clause 46 of the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965 (hereinafter referred to as the said Scheme), for item (b) of sub-clause (3), the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

3. In clause 47 of the said Scheme for item (a) of sub-clause (5), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

4. In clause 53 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (2)(iii), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

[No. 528/183/65-Fac. II/P&D.]

का० घा० 1810—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मोरमूगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 में श्रीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. इस स्कीम का नाम मोरमूगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1971 होगा।

1111 2. मोरमगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खण्ड 46 में, उपखण्ड (3) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) जहां किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता। और उसके पश्चात् अध्यक्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच, ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों का एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 47 में, उपखण्ड (5) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर, आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

4 उक्त स्कीम के खण्ड 53 में, उपखण्ड (2) (iii) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह-भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी-सहित-छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अध्यक्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधार्मिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा।”

S.O. 1811.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, the same having been previously published as required by the said sub-section, namely:—

1. This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1971.

2. In clause 45 of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 (hereinafter referred to as the said Scheme), for item (b) of sub-clause (3), the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Where a worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

3. In clause 46 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (4-A), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the workers, the subsistence allowance shall for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

4. In clause 51 of the said Scheme, for item (a) of sub-clause (3-A), the following item shall be substituted, namely:—

“(a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances:

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.”

[No. 528/183/65-Fac II/P&D.]

AJIT CHANDRA, Under Secy.

का० आ० 1811—ड.क.कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कोचीन डक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम, जिसे उक्त उप-धारा द्वारा यथा अपेक्षित पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, एतद्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. इस स्कीम का नाम कोचीन डक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1971 होगा।

2. कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खण्ड 45 में, उपखण्ड (3) की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) जहां किसी कर्मकार को मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अर्धवर्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच, ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा ।”

3. उक्त स्कीम के खण्ड 46 में, उपखण्ड (4-क) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता और उसके पश्चात् अर्धवर्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई, और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन में अधिक की अवधि वाले निर्वाह-भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा ।”

4. उक्त स्कीम के खण्ड 51 में, उपखण्ड (3-क) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लम्बित रहने तक निलम्बित किया गया हो वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा, जिसका वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होने की दशा में हकदार होता, और उसके पश्चात् अर्धवर्ष, असाधारण दशाओं में, ऐसा उच्चतर निर्वाह-भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच ऐसे कारणों से, जिनके लिए कर्मकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, नब्बे दिन की अवधि के बाद भी चलती रहे तो वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि वाले निर्वाह भत्ते को घटा कर आधारिक मजदूरी, महंगाई और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के समतुल्य कर दिया जाएगा ।”

[संख्या 528/183/65 फैक0 2/पी० एंड डी०]

अजीत चन्द्रा, अवसर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1812.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 7 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited,

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri S. B. Sanyal, Legal Adviser.

On behalf of Workmen—Shri Benarashi Singh Azad, General Secretary of Khan Shramik Congress.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/83/70-LR.II, dated December 24, 1970, the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal Company Limited, Post Office Ukhra District Burdwan was justified in stopping the work of Shri Sk. Akbar, Cleaning Mazdoor from 29th June, 1970

If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The workmen represented by the Khan Shramik Congress filed a written statement. The management also filed a rejoinder thereto. Thereafter, parties arrived at a settlement fully and completely settling the dispute and filed the petition of settlement before this Tribunal.

3. Now, that there is no further dispute between the parties, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

Dated, April 5, 1971.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

REFERENCE No. 7 OF 1971

Management of Bankola Colliery of the Burrakur Coal Co. Ltd., P.O. Ukhra,
Distt. Burdwan

Vs

Their workmen represented through the Khan Shramik Congress, P.O. Ukhra,
Distt. Burdwan.

Most Respectfully Sheweth,

1. That the parties to the dispute have settled and resolved the differences on the following terms:

(a) That the concerned persons named in the order of Reference shall be paid a sum of Rs. 150/- each as full and final settlement.

(b) The Union shall have no further claim what-so-ever in relation to the dispute.

(c) That in case of a vacancy arising of cleaning mazdoor in the colliery the concerned persons shall be given first preference for their employment.

For, Workmen

(Sd.) Illegible

Genl. Secy.

Dated, April 5, 1971

For Management

(Sd.) Illegible

Personnel Officer and Principal Officer.

[No. 6/83/70-LRII.]

S.O. 1813.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Benalee Colliery of Messrs Nimcha Coal Company Limited, Post Office Nandi, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE NO. 2 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Benalee Colliery of Messrs Nimcha Coal Company Limited,

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. K. P. Mukherjee, Counsel.

On behalf of Workmen—Shri Jagannath Dubey, one of the concerned workmen.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 1/33/70-LR-II, dated December 9, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Benalee Colliery of Messrs Nimcha Coal Company Limited, and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Benalee Colliery was justified in not allowing Shri Kamala Kant Misra, Time Keeper with effect from the 24th March 1970 and Shri Jagannath Dubey, Driller and Shri Ramanand Pandey, Guard with effect from the 28th March, 1970, to resume their duties?

If not, to what relief these workmen are entitled?”

2. The management of Benalee colliery filed a written statement. In paragraph 1 of the written statement it was stated as follows:

“That the Nimcha Coal Co. Ltd., is the owner of two collieries, viz. Nimcha Colliery and Benalee Colliery. By a notice of closure, dated the 28th August, 1970, the Benalee Colliery has been completely closed down with effect from the 29th August, 1970. Such closure is real and the Company has got no intention to run the Colliery in future.”

The reason for not allowing the three concerned workmen to resume their duties was explained by the management in paragraph 6 of the written statement. Shorn of verbiage, the explanation substantially is that the three workmen went on leave but over-stayed the sanctioned leave. Thereupon, they lost their lien on their respective appointments and were put on the *badli* list, in accordance with the provisions of Clause 16(2) of the certified Standing Orders of Benalee colliery.

3. The workmen, at the time the dispute was raised, were represented by a trade union called Colliery Mazdoor Congress (HMS) Later on, they came to be represented by another trade union called Colliery Mazdoor Congress (HMP), which later trade union filed a written statement. I do not propose to refer to this written statement because the case pleaded therein was not proved by anybody.

4. I did not have the assistance of the trade union filing the written statement on behalf of the workmen because they did not appear on the date fixed for hearing. The circumstances under which I had to proceed in the absence of the trade union have already been discussed in my Order dated March 30, 1971 and I need not repeat the same again in this award.

5. I need, first of all, find out whether the story of closure is a real story. It is settled law that where a business has been closed and the closure is real, any dispute arising with reference thereof would not fall within the purview of the jurisdiction of the Industrial Disputes Act and that will *a fortiori* be so, if a dispute arises—if such can be conceded—after the closure of the business between a quondam employers and employees. In the case of *Indian Hume Pipe Co. Ltd. vs. their Workmen*, 1969, 1 LLJ 242 (245) the Supreme Court further observed:

“In our opinion, it was not open to the Tribunal to go into the question as to the motive of the appellant in closing down its factory at Barakar and to enquire whether it was *bona fide* or *mala fide* with some oblique purpose, namely, to punish the workmen for the union activities in fighting the appellant. It has been laid down by this Court in a series of decisions that it is not for industrial tribunals to enquire into the motive to find out whether the closure is justified or not.”

I have already observed in another reference between the management of Benalee colliery and their workmen, in Reference No. 49 of 1970, that the closure of the colliery is a real one. It has again been proved before me by the evidence of D. R. Sakuja, one of the Directors, that the colliery has been closed. That also appears from the minutes of the meeting of the Board of Directors of Nimcha Coal Co. Ltd., owning the Benalee colliery, dated August 27, 1970, a copy of which is marked Ex. 2. Therefore, I have to proceed on the basis that the Benalee colliery has been closed with effect from August 29, 1970, as pleaded in paragraph 1 of the written statement.

6. I have next to see whether the case pleaded by the management in justification of not allowing the concerned workmen to resume their duties has been proved. In this respect however, the management is in a disadvantageous position. In paragraph 9 of the written statement, the management pleaded that in view of the complete closure of Benalee colliery relevant records were unavailable, nevertheless, it was hoped to collect them. This hope did not materialise. Biman Kanti Bagchi, witness No. 1 for the employers, stated in his evidence that the records were in the colliery under his control but they somehow became misplaced. He does not appear to be a well informed witness and had nothing to offer in support of his oral evidence. D. R. Sakuja, one of the Directors, who was called as a Court witness however, was more than did. In answer to certain questions put by the learned Counsel for the management, he said “when this written statement was drafted, the materials were collected from what appeared in the Failure report copy of which was sent to me from the Labour Ministry at New Delhi”. The correctness or otherwise of the facts stated in the failure report is anybody's guess. In these circumstances, I am not satisfied with the plea of the management in explanation of their refusal to allow the concerned workmen to resume their duties.

7. Although this is so, colliery now stands closed and it would be useless to direct the management to allow the concerned workmen to resume their duties in a closed colliery, even if I hold that I have jurisdiction over the misdeeds of the management prior to the closure.

8. D. R. Sakuja, the Director witness, however, made an offer to give appointment to one of the workmen, namely, Jagannath Dubey in the same capacity at Nimcha colliery which was only three miles away from Benalee colliery. Jagannath Dubey, the concerned workman, who was present before the Tribunal, readily agreed to accept such an appointment. The other two workmen were not present before the Tribunal and D. R. Sakuja did not offer anything for them. The case pleaded on behalf of the workmen has not been proved before this Tribunal. The colliery is a closed one. Therefore, I do not think I can make any order in favour of the remaining workmen.

9. In the result, I hold that I direct the management to give a fresh appointment to Jagannath Dubey, Driller, as driller in Nimcha colliery, with effect from April 1, 1971. I uphold the action of the management in all other respects. Save as aforesaid, the workmen are not entitled to any other relief.

This is my award.

Dated, April 2, 1971.

(Sd.) B. N. BANERJEE, Presiding Officer.

[No. 1/33/70-LRII.]

S.O. 1814.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Selected Fatka Colliery, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th April, 1971.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT
DHANBAD**

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

REFERENCE No. 51 of 1968

PARTIES :

Employers in relation to the Selected Fatka Colliery, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad

AND
Their workmen

PRESENT :

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate, with Shri P. K. Bose, Advocate.

For the Workmen—Shri S. K. Mukherjee, Advocate.

STATE: Bihar.

INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, dated the 31st March, 1971

AWARD

The present Reference arises out of Order No. 2/49/68-LR11, dated New Delhi, the 28th June, 1968 passed by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, whereby the following dispute between the parties hereto was referred to this Tribunal for adjudication:

“Whether the management of the Selected Fatka Colliery, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad was justified in dismissing its workman, Shri Sunil Baran Shell, Mining Sirdar, with effect from the 13th September, 1967? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. The order of the Ministry was received in this Tribunal on 9th July, 1968. The written statement on behalf of the workmen was filed on 7th December, 1968. The written statement-cum-rejoinder of the management was filed on 12th December, 1968.

3. The case for the workmen may thus be stated briefly. The workman concerned while working in the Selected Fatka Colliery as a Mining Sirdar tried to follow strictly the safety rules, mines regulations and provisions laid down in the Mines Act. The management was not satisfied with such conduct, because this particular management was after raising extra coal by means fall or foul so as to increase its profit. The workman concerned on account of some violation of safety rule and irregularities in the mining operations verbally made a report to the Mining Department, Dhanbad, whereupon there was a thorough inquiry into the matter. The management, according to the workmen, issued a charge sheet in getting a scent of this enquiry. The charge sheet dated 23rd August, 1967 was received by the workman per registered post on 26th August, 1967.

4. Their further case is that there was no proper enquiry. Para 6 of the written statement dealing with the enquiry runs thus: “That there was no proper enquiry with regard to the aforesaid frivolous charges levelled against this workman as per charge sheet dated 23rd August, 1967. It was simply told that the Director in charge will hold the enquiry but as a matter of fact there was no enquiry at all into the matter in issue. No witness have been examined nor they were allowed to be cross-examined by the workman nor he was given opportunity to adduce evidence as laid down in the standing orders and domestic enquiry procedure.”

5. On the question of dismissal their case is that the management issued a letter of dismissal dated 4th September, 1967 dismissing the workman concerned retrospectively with effect from 23rd August, 1967 and such retrospective dismissal was bad in law.

6. The management in their written statement-cum-rejoinder has stated that as the workman concerned was extracting money from the miners and allowing them to rob pillars a charge sheet dated 23rd August, 1967 was issued to him and he was suspended pending enquiry, and that he submitted an explanation dated 26th August, 1967 denying the charge.

7. On the question of the departmental enquiry the management has stated that a notice dated 30th August, 1967 was issued to the workman concerned fixing the departmental enquiry on 2nd September, 1967, that the departmental enquiry was held on 2nd September 1967 by the Director in presence of the workman giving him full chance and opportunities to cross-examine the witness and defend himself, that at the departmental enquiry the misconduct mentioned in the charge sheet was satisfactorily established, and that consequently the workman concerned was dismissed by a letter dated 4th September, 1967 with effect from the date of his suspension.

8. The workman concerned in his cross-examination has admitted that he got the notice of enquiry proceedings, that he attended the place of enquiry at the colliery office and that Shri T. R. Agarwala conducted the enquiry. It is in evidence that T. R. Agarwala is the Director of the Selected Fatka Colliery. He has also admitted that T. R. Agarwala called him and asked him as to who had drafted the reply to the chargesheet and that after he had replied to the question of T. R. Agarwala he was asked to sign on a paper and he signed. Therefore it is clear that he was examined and that he himself put his signature on the enquiry proceedings.

9. The only dispute is whether two witnesses were examined on behalf of the management and whether the workman concerned had opportunity to cross-examine them. The enquiry proceedings have been proved by T. R. Agarwala himself and they have been marked as Ext. M. 3. The enquiry was conducted in Hindi. The proceedings show that two witnesses, namely Lakhiram Majhi and Fucha Majhi deposed on behalf of the management, and that the concerned workman refused to cross-examine them and refused to put his signatures at the end of their depositions. T. R. Agarwala has stated in his deposition that at first the two miners were examined that the concerned workman was asked to cross-examine the witnesses of the employers, and that he refused to do so.

10. I have no reason to disbelieve the evidence of T. R. Agarwala. From the evidence on record, both oral and documentary, it appears that the departmental enquiry was properly held and that the letter of dismissal was issued by T. R. Agarwala himself. But still I refrain from passing any final opinion as to the validity of the enquiry proceeding and of the letter of dismissal and as to the truth or otherwise of the misconduct alleged in the charge sheet as, in my opinion, for the reason to be presently stated, there was and is no industrial dispute between the employers and its workmen. The Central Government was not justified in making the reference in the absence of such dispute and this Tribunal is not competent to entertain the reference. But before I enter upon the validity of the reference I may dispose of another objection as to the validity of the order of dismissal. It is contended on behalf of the workmen that the order of dismissal being retrospective in its operation is void in toto. This contention must fail in view of the following observation of the Supreme Court in Jeevaratnam V. State of Madras, (1967) 1 L.L.J. 391 at 393: "An order of dismissal with retrospective effect is in substance, an order of dismissal as from the date of the order with the superadded direction that the order should operate retrospectively as from an anterior date. The two parts of the order are clearly severable. Assuming that the second part of the order is invalid, there is no reason why the first part of the order should not be given the fullest effect. The Court cannot pass a new order of dismissal, but surely it can give effect to the valid and severable part of the order."

11. The workman concerned has stated in his cross-examination that he did not write any letter of protest to the company after getting the letter of dismissal. T. R. Agarwala categorically stated in his examination in chief that no protest was made either by the workman concerned or by any trade union before the management protesting against the dismissal of Sunil Baran, the workman concerned. He was not even cross-examined on this point.

12. From the report of the Assistant Labour Commissioner (Central), Dhanbad-II to the Secretary to the Department of Labour and Employment, New Delhi dated the 2nd April, 1968, reporting the failure of the conciliation proceeding it is clear that an industrial dispute was raised by the union before the Assistant Labour Commissioner (C), Dhanbad-II. The Supreme Court has held in Sindhu Resettlement Corporation Ltd. Vs. Industrial Tribunal, Gujrat, (1968) 1 L.L.J. 834 that the Government is not entitled to make any reference on a mere demand made by the workmen to the Assistant Labour Commissioner. The relevant portion from the

judgment of the Supreme Court in the aforesaid case is quoted below: "It may be that the conciliation officer reported to the Government that an industrial dispute did exist relating to the reinstatement of respondent 3 and payment of wages to him from 21st February, 1958, but, when the dispute came up for adjudication before the Tribunal, the evidence produced clearly showed that no such dispute had ever been raised by the respondents with the management, any request sent by them to the Government would only be a demand by them and not an industrial dispute between them and their employer. An industrial dispute as defined, must be a dispute between employers and employers, employers and workmen and workmen and workmen. A mere demand to a Government without a dispute being raised by the workmen with their employer, cannot become an industrial dispute. Consequently, the material before the tribunal clearly showed that no such industrial dispute, as was purported to be referred by the State Government to the tribunal, had ever existed between the appellant Corporation and the respondents and the State Government, in making a reference obviously committed and error in basing its opinion on material which was not relevant to the formation of opinion."

13. I, therefore, hold that the workman is not entitled to any relief in the present reference even if the workman succeed in establishing that the departmental enquiry was not properly held or that the charge against the workman concerned has not been proved on that the order of dismissal has not been passed in accordance with law. This is my award. But I make it clear that nothing contained in this award shall debar the workman from raising a proper dispute before the management and from procuring a fresh reference on such dispute.

14. Let a copy of this award be sent to the Central Government in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) A. C. SEN.
Presiding Officer.

[No. 2/49/68-LRII.]

S.O. 1815.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem, (Andhra Pradesh) and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th April, 1971.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Sri T. Chandrasekhara Reddy, B.A., B.L., Chairman, Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

INDUSTRIAL DISPUTE No. 36 OF 1969

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.

AND

The Management of Singareni Collieries Company, Limited, Kothagudem.

APPEARANCES:

Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for the Workmen,

Sri P. S. Jayachander Rao, Divisional Personnel Officer, Singareni Collieries Co., Ltd., Kothagudem and Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate and Hony. Secretary of the Federation of Andhra Pradesh Chambers of commerce and Industry, Hyderabad—for the Management.

AWARD

By an Order, dated 15th October, 1969, the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) referred the following dispute between the Employers in relation to Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem, and their Workmen for adjudication to Sri Mohammad Najmuddin, my predecessor in office. After his retirement it was referred to me. The dispute referred is as follows:—

"With regard to the nature of duties performed by Sarvasri Golla Iyalu, Lambadi Somalu and Rapalli Bondiyalu as Trolley Attenders, whether

the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem is justified in placing these workmen in New Category II under the Central Wage Board Recommendations? If not, to what relief these workmen are entitled and from what date?"

2. The Workmen have filed a claims statement through the President, Andhra Pradesh Colliery Mazdoor Sangh, Kothagudem, alleging that the workmen Golla Iyaloo, Lambadi Somalu and Rapalli Bondyaloo were permanent employees of the Singareni Collieries Company and were working in V Incline, C.S.P. for several years; that they were engaged as conveyor drivers and were placed in old Category III under the Mazumdar Award on par with other conveyor drivers and were designated as trolley attendants as they were operating trolleys. But the management contended that they were fitter helpers at the time of implementing the Wage Board Recommendations. The Management changed the designation of the above workmen as fitter helpers in records of the Company with the ulterior motive of depriving them of their legitimate category of wages under the Wage Board Recommendations. Hence the action of the management was *mala fide* and illegal. The workmen in question were engaged in controlling the conveyor belts by means of trollies from one end to another in order to fill the bunkers in C.S.P. and they had to control and operate the gear of the trolley as required in the process of filling the bunkers. Further, these workers were provided with mazdoors. According to the workmen, the above workers had to be placed in Category III as recommended by the Central Wage Board with retrospective effect and so they prayed that an award might be passed accordingly.

3. The Management filed a reply statement alleging that the reference of the dispute for adjudication had been made erroneously under the assumption that the workers involved in the dispute were not placed in the proper category under the Wage Board's recommendations; that the nature of duties performed by them were purely manual and unskilled and the appropriate category for the job was only Category I but in view of the circumstance that they were in old Category III they had been placed in New Category II even though workers on similar jobs in other coal screening plants were given Category I only. The Unions had claimed new Category III only to these workers in I.D. No. 30 of 1967 on the ground that no provision had been made in the Wage Board Recommendations as these workmen were not covered by the Wage Board Recommendations. As admitted by the Union, what the Union was seeking was only a modification of the category on the plea of special conditions. Hence there was no justification for any reference as the present one to the Tribunal as it was covered by I.D. No. 30/67 wherein the subject matter was regarding what further modifications and changes in the categorisation and wage structure recommended by the Wage Board for the West Bengal and Bihar Coal fields were necessary to make the said categorisation and wage structure applicable to the workmen of the Singareni Collieries Company Limited having regard to the special conditions obtaining in the Andhra Pradesh coal fields. The Management admitted without prejudice to the submissions already made, that the three workmen were permanent employees of the Company and were working in V Incline but denied that they were engaged as conveyor drivers. According to the Management, the trolley attendant had nothing to do whatsoever with the driving of the conveyor and there were conveyor operators/switch boys in Category III in the past as well as at present other than the above workmen to operate the belt passing through the trolley. The workmen in question had been placed in Category II as per the general formula adopted by equating the posts and the allotment of Category II was personal to them only. The Management further averred that to avoid unreasonable and vexatious claims, such as the present one, the Management suitably changed their designations as helpers who were also in old Category III and allotted to New Category II under the Wage Board Recommendations and it made no difference even if their designation was changed as trolley attendants as before. They denied that they had any ulterior motive in changing the designation. According to them, the workmen in question were required to adjust the wiper against the required bunker and the wiper was mounted on a travelling trolley which was moved manually against the required bunker placed in a row. The trolley was a chute mounted on wheels and threaded through a belt conveyor driven separately and away from the trolley and was adjusted against bunkers set out in a row. It had no driving mechanism of its own either electrical or mechanical and so the workmen's job was mainly unskilled manual labour and thus it was distinguishable from that of conveyor drivers or switch boys, whose job description was shown in Appendix V of the Report of the Central Wage Board Recommendations. They denied that the workmen in question were provided with mazdoors. According to them, there were some mazdoors working at the spot for cleaning of lifting spill over coal along the belt and the workmen in question

were not supervising the work of those mazdoors. So there was no justification for allotment of Category III to the workmen in question either on the basis of the Wage Board Recommendations or on the basis of the nature of the work carried out by them. The work of conveyor khalasis was entirely different and could not be compared with the work of the workmen in question. So they prayed that the claim of the workmen may be dismissed.

4. Each side has examined one witness. The workmen have exhibited Exs. W1 to W4, which are no other than those issued to Golla Iylu under Coal Mines Regulations 1957 and they are the bonus cards for the IVth quarter 1963, IIIrd Quarter 1964 and 2nd Quarter 1965 respectively.

5. The main question is: Having regard to the nature of the duties of the above workmen, whether the Management of the Singareni Collieries Company is justified in placing them in new Category II under the Central Wage Board Recommendations.

6. The duties of these three workmen are given out in detail by W.W.1 Golla Iyalu, one of the claimants, and M.W. 1 the Junior Engineer. According to W.W. 1 trolley attender operates the trolley by a handle which has a mechanical appliance which had to be operated by the hand. There were 68 bunkers of 1000 feet in length each bunker 15' x 15' x 15' and there will be rails on the bunkers and the trolley runs on rails. The trolley attender operates the clutch liver once for each bunker. The duty of the workmen in question, according to W.W.1, is to see that the coal falls in the bunkers. If the coal lumps obstruct the line or if the bolts are not in proper condition, there is the danger of the trolley falling or going off without control. Then the workman in question (trolley attender) gives a signal to the mazdoor, who in turn gives a signal to the switch boy and the switch boy puts off the switch and then the movement of the trolley is stopped. He also added that if the conveyor belt is stopped the trolley also stops. According to him, the mazdoor works under him. The trolley moves if the switch is put on for the conveyor belt. The trolley does not have a switch or motor but it works by pressing the clutch. According to him, the work of a trolley attender like himself and the conveyor khalasis is the same. There are two conveyor belts and two trolleys and he operates the two trolleys. He also puts grease to the conveyor belts. The conveyor driver is also called conveyor khalasis whose duty is to switch on or switch off to operate the conveyor belt. Prior to the Wage Board the switch boy or the conveyor khalasi was in Category III and even after the Wage Board Recommendations are implemented, he is given the same category but he admitted in cross-examination that the conveyor khalasi operates 4, 5 or 10 switches.

7. M.W.1 the Junior Engineer, Central Screening Plant, V Incline, Rudrampur Division, Kothagudem, deposed that the trolley is a movable chute mounted on wheels and threaded to a belt conveyor and driven separately away from the trolley and adjusted against bunkers set out in a row and the trolley is not having any mechanism of its own. It cannot be driven independently of the conveyor belt. In other words, he says that, unless the conveyor belt runs the trolley does not move. It moves only with the aid of the belt. There are gears which are intended to change the direction of the trolley, i.e., towards front or back. The trolley attender merely stands on the trolley and operates the lever. According to him, conveyor belt need not be greased but a trolley had to be greased. It was the duty of the trolley attender to grease the trolley. He too stated that there are 68 bunkers each bunker being 15 feet long. There was one mazdoor for each shift who works along with the trolley attender to clear the spilled coal. According to him, the conveyor khalasi has to operate the electrical switches about 26 in number to run the prime movers of the conveyors and the other machinery. There are six switch boys in the C.S.P. at the rate of 2 per shift and they operate the switches. They are in Category III now. Even M.W.1 says that if the trolley is in operation the trolley attender attends to the work of signalling. He denied that it was the mazdoor that signals when the trolley is operated. According to him, if the trolley went wrong the trolley attender had to send for the fitter, who attends to the repairs. It is clear from the evidence of W.W.1 and M.W.1 that originally the three workmen in question were designated as trolley attenders and that they were designated as fitter-helpers later. M.W.1 has stated that even before he came to the C.S.P. V Incline, about 8 years ago, the three workmen in question were working as trolley attenders and it is not denied by the management that all of them were permanent employees of the Company.

8. Sri Lakshmanrao the learned advocate for the workmen contends that the three workmen in question were operating the trolleys, that a trolley attender was given the assistance of one mazdoor to give signals, that he has to see that 68

bunkers of 1000 feet length for filling with coal and that if the coal lumps obstruct the line or if the bolts are not in proper condition there is the danger of the trolley falling down and that in those circumstances the trolley attendant gives a signal to the mazdoor, who in turn gives signals to the conveyor driver also called switch boy, who puts off the switch. According to Sri Lakshmanrao, when the switch boy who has merely to put on or put off the switches and who was also previously placed in old Category III, was now given new Category III after the implementation of the Wage Board Recommendations, it is just and proper that the trolley attenders, whose duties had been mentioned above, should also be placed in new Category III, as recommended by the Wage Board. He drew my attention to the occupational nomenclatures and job description of Trammers, pump khalasis haulage and conveyor khalasis as found in Appendix 13 of the Mazumdar Award and submits that trolley attenders were also on par with them being in old Category III and referred me to the designation and job description of pump khalasis and conveyor khalasis as recommended by the Central Wage Board and urged that the trolley attenders should also be placed in new Category III as recommended by the Central Wage Board having regard to their nature of duties, vide Appendix V. He also submits that the trolley drivers in question were doing the work of fitters and not helping any one and that the designation of trolley attenders had been changed during conciliation as fitter-helpers deliberately with the object of depriving them of the category to which the three workmen were legally entitled. So he prayed that the trolley drivers should be given new Category III and that the Management was unjustified in placing them in new Category II. But Sri K. Srinivasamurthy argued with some insistence that the three workmen in question were described as trolley attenders and not trolley drivers as described in the claims statement, that there was no evidence on record to the effect that they were operating the switches, that the trolley attender does not even start or stop the trolley as a Fan khalasi in New Category III does. On the basis of the evidence of M.W.1 the Junior Engineer, he urged that the work done by the trolley attenders in question is purely unskilled work and that they were so designated as trolley attenders in the Wage Board Recommendations and that the job description of the trolley attenders in question was not equal to that of fan khalasis No. 4 in Category III, pump khalasis No. 5 in Category III and conveyor khalasis No. 13 in Category III, Appendix V as recommended by the Wage Board. He further submitted that no mazdoor is placed under the trolley attenders in question and that therefore their designation was changed to fitter-helper so that frivolous and unjust claims might not be made. The trolley had no independent motion that it moves with the conveyor belt and stops with it, that each of the workmen in question was to stand on the trolley and operate the gear to change its direction towards front or back as the case may be and adjust against the required bunker and that it had no mechanism whatsoever. He also argues that the duties of fan khalasis, pump khalasis and conveyor khalasis in new Category III were onerous as they had to start or stop the engine, or motor driving the fan or pump mechanism as the case may be besides remaining in attendance when it is in motion. Further, a fan khalasi had to take and record readings of instruments used in connection with the fans, and assist the fitter and electrician etc. when they were attending the fan and accessories, while a pump khalasis had to oil the necessary machine bearings besides starting the pump mechanism and remaining in attendance when the machinery was in motion. A conveyor khalasi according to the job description given by the Wage Board in Appendix V had to operate the driving gear of face or roadway conveyors of the belt, shaker (jigger) or scraper types. So Mr. Srinivasamurthy submits that they are rightly put in semi-skilled higher category III by the Wage Board and the company had allotted IInd Category to them.

9. In the instant case the workmen in question, even according to W.W.1, were not operating the conveyor belts and were not putting on or putting off the switches which amounted to starting and stopping the conveyor belt. Admittedly a trolley had no independent motion of its own. It had no driving mechanism, either electrical or mechanical of its own and it is started and stopped with the conveyor belt. Thus it is dependent upon the conveyor belt. The trolley attender was only to operate the lever and adjust it against the required bunkers which are set in a row. He had to operate the gear to change its direction forward or backward, and the trolley moves on the rails. According to M.W.1, there was no occasion when the trolley had fallen down. I do not see any reason to disbelieve the evidence of M.W.1 when he says that the trolley attender was not given the assistance of the mazdoor. According to M.W.1 the mazdoor was working at the spot for cleaning or lifting spill coal along the belt. If the trolley went out of order the trolley attender had to report to the fitter who had to attend to its repairs and it is not the case of even W.W.1 that he had to attend to the repairs. Even according to W.W.1, the duties of conveyor Khalasi or switch boy

were more onerous because he was assigned with the duty of starting or stopping the conveyor belt by putting on or putting off the switches as the case may be and it is needless to repeat that the trolley automatically stops when the conveyor belt stops. Hence the switch boy or the conveyor khalasi is categorised as semi-skilled higher according to the Central Wage Board Recommendations and is put in Category III new. Admittedly he is put in new category III after the wage board recommendations were implemented. Inasmuch as the duties of the trolley attender were less onerous than those of the switch boy or conveyor khalasi, the three workmen in question had been rightly placed in new category II i.e., semi-skilled lower as they had gained some experience. The nature of the duties performed by trolley attenders are not equal to those of fan khalasis, pump khalasis and conveyor khalasis who were placed in category III by the Central Wage Board.

10. According to the Management, there was no designation of trolley attender either in the Coal Award or in the Central Wage Board Recommendations. So their designation had been changed as fitter-helpers as they were in old Category II and were allotted new Category II as they were semi-skilled lower and not with any ulterior motive. So the Management is justified in placing the three workmen in question in Category II and is not guilty of any unfair labour practice. Consequently the demand made by the workmen in question that they should be placed in new category III having regard to the nature of duties done by them does not appear to be justified.

11. Sri K. Srinivasamurthy urges that the Union is demanding to the trolley drivers i.e., to the persons like the three workmen in question. New Category III recommended by the Wage Board and wages of new category III in I.D. 30/67 wherein the subject matter of the dispute was what further modifications and changes in the categorisation and wage structure recommended by the Wage Board for West Bengal and Bihar coal fields are necessary to make the said categorisation and wage structure applicable to the workmen of Singareni Collieries Company Limited having regard to the conditions obtaining in the Andhra Pradesh coal fields. Admittedly the Central Wage Board recommendations do not mention the designation of trolley attenders. I am of the opinion that the subject matter of the present I.D. is confined only to the three workmen in question and the case of the management also is that the allotment of Category II (new) is personal to them. In I.D. No. 30 of 1967 all the trolley attenders along with others are claiming modifications in categorisation and wage structure in the recommended as of the wage board having regard to the special conditions existing in the respondent Company.

12. In view of the above discussion, I hold that the workmen in question are not entitled to any relief in this industrial dispute.

Award passed accordingly.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this the 31st day of March, 371.

T. CHANDRASEKHARA REDDY,
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses examined for Workmen:	Witnesses examined for Employers:
W.W.1: Golla Iylu.	M.W.1: L. Viswanatham.
Documents exhibited for Workmen:	Documents exhibited for Employers:
Ex. W1: Authorisation of G. Iylu issued by the Management on 1-9-1969.	Nil.
Ex. W2: Bonus card of G. Iylu for IV quarter 1963 issued by the Management.	
Ex. W3: Bonus card of G. Iylu for III quarter 1964 issued by the Management.	
Ex. W4: Bonus card of G. Iylu for 2nd quarter 1965 issued by the Management.	

(Sd.) Illegible
Industrial Tribunal.
[No. 7/1/69-LRII.]

New Delhi, the 19th April 1971

S.O. 1816.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA
REFERENCE No. 9 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bankola Colliery,
AND
Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee—Presiding Officer

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. S. B. Sanyal, Legal Adviser.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/99/70-LR.II, dated January 6, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Bankola Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Bankola Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan are justified in stopping the work of S/Shri Choteylal Paswan and Taiyeb Hosan, Cleaning Mazdoors with effect from 13th May, 1970? If not, to what relief the workmen are entitled?”

2. The parties to the dispute filed their respective written statement. Thereafter, they entered into a compromise and filed a petition of compromise before this Tribunal, in token of the settlement. The compromise was proved by J. Sharan, personnel and Principal Officer of the Bankola Colliery. Now, that the dispute has been settled, I make an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated April 6, 1971.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA
REFERENCE No. 9 OF 1971

Management of Bankola Colliery of the Burrakur Coal Co. Ltd., P.O. Ukhra, Dt. Burdwan.

Vs.

Their workmen represented through the Khan Shramik Congress, P.O. Ukhra, Dt. Burdwan.

Most Respectfully sheweth:

1. That the parties to the dispute have settled and resolved the differences on the following terms:

- (a) That the concerned persons named in the order of Reference shall be paid a sum of Rs. 150 each as full and final settlement.
- (b) The Union shall have no further claim what-so-ever in relation to the dispute.
- (c) That in case of a vacancy of cleaning mazdoor arising in the colliery the concerned persons shall be given first preference for their employment.

For Workmen.

(Sd.) Illegible

Genl. Secy.,

Khan Shramik Congress,
Ukhra.

Dated April 5, 1971.

For Management.

(Sd.) Illegible

Personnel Officer

and

Principal Officer.

[No. 6/99/70-LR.II.]

S.O. 1817.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Lodna Colliery Company (1920) Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 6 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the Lodna Colliery Company (1920) Limited,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. D. Basu Thakur, Advocate.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By order No. 6/71/70-LRII, dated December 24, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred an industrial dispute between the employers in relation to the Lodna Colliery Company (1920) Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

"Keeping in view the recommendations of the Wage Board for Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their Resolution No. WB-16(5)/66, dated the 21st July, 1967, whether the management of Rana Colliery of Messrs Lodna Colliery Company (1920) Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan was justified in placing the following Coal Cutting Machine Drivers in Category V? If not, to what relief are these workmen entitled?"

Sl. No.	Name	Designation
1.	Nizam Mia	Coal Cutting Machine Driver
2.	Etwari	-do-
3.	Jaul Haque	-do-
4.	Amir Hajam	-do-
5.	Dhaneshwar Turi	-do-
6.	Sayub Mia	-do-
7.	Imamuddin	-do-
8.	Jasimuddin Khan	-do-
9.	Mangal Kora	-do-
10.	Nisar Ahmed	-do-
11.	Lachmi Singh	-do-
12.	Ramchandra Kora	-do-
13.	Madho Rout	-do-
14.	Ramashish Bin	-do-
15.	Kamal Khan	-do-
16.	Bashir Hossain	-do-
17.	Wahid Khan	-do-

2. The workmen adopted a strange attitude of non-cooperation. In spite of service of notice, they did not file their written statement. Then again, in spite of notice they did not appear on the date fixed for settling a date of hearing. Lastly, they did not appear today which was fixed as the date of peremptory hearing. In these circumstances, I think it is useless to wait further for the workmen. The circumstances are such as mean that there is no further dispute between the workmen and the management at the present moment.

3. I, therefore, pass a "no dispute" award in this reference.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

Dated, April 1, 1971.

[No. 6/71/70-LRII.]

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1818.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shankarpur Colliery of Messrs Ukhra Minerals Private Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

REFERENCE NO. 10 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Shankarpur Colliery of Messrs. Ukhra Minerals Private Limited,

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employees—Shri N. Das, Advocate.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE: WEST BENGAL.

INDUSTRY: COAL MINES.

AWARD

By Order No. 6/51/70-LR.II., dated December 11, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Shankarpur Colliery of Messrs Ukhra Minerals Private Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

“Whether the management of Shankarpur Colliery of Messrs Ukhra Minerals Private Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in dismissing Shri Kanta Harijan, Pickminer from the 19th May, 1970? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. The workmen, represented by the Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), adopted an attitude of non-cooperation with this Tribunal. They did not appear at any stage before this Tribunal nor did they file their written statement. Today, which was fixed as the date of peremptory hearing, the workmen went unrepresented.

3. The management filed a written statement. It was alleged in the written statement that the designation of the concerned workman was wrongly stated in the order of Reference and that he was not a pick-miner but a balling mazdoor, as appearing in the books of the employer company. The further case pleaded by the management will appear from paragraphs 4 and 5 of the written statement, which are set out hereinbelow:

“4. * * * that the said Kanta Harijan applied for 20 days leave with effect from 2nd March, 1970 to 21st March, 1970 and submitted his application before the Colliery Manager in the prescribed form on 16th February, 1970 and the said leave was sanctioned as will appear from the order of the Colliery Manager, passed on the aforesaid application and Leave slip (***) for 13 days with pay and 7 days without pay

5. That the workman was due to return on the expiry of his leave and resume his work on and from 23rd March, 1970 as 22nd March 70 was a Sunday and weekly day of rest in the Colliery but he overstayed his leave and came back on 26th March, 1970 and met the Manager on that day and offered explanation for his delay. The Manager directed him to resume his work from 27th March, 1970.”

It was alleged, in the written statement, that the concerned workman did not resume his work on March 27th, 1970 and absented himself from that day without permission. As his unauthorised absence had exceeded 10 days, which was a misconduct as per Standing Order, he was charged with misconduct and a charge-sheet was issued against him on April 10, 1970. The workman received the

chargesheet and submitted his explanation on April 17, 1970. The explanation was found unsatisfactory and the management decided to hold a domestic enquiry against him, on April 28, 1970, with due notice to the workman. On the first date fixed for the domestic enquiry, the workman did not appear. Thereupon, the enquiry was adjourned and the notice of adjournment was also duly sent and received by the workman. The domestic enquiry was held on the adjourned date, namely May 9, 1970. The workman attended the enquiry. He was said to have been given an opportunity to cross-examine witnesses produced by the management and to produce his own witnesses but he did not avail of the opportunities. The Enquiry officer found that the charge was proved against him. The management accepted the enquiry report and ordered his dismissal.

4. The management examined Kajal Kr. Sarkar, Manager of the colliery, who proved the relevant documents, namely the leave application (Ex. 1), order upon the workman to resume his duty from March 27, 1970, even though he had overstayed his leave (Ex. 2), the chargesheet (Ex. 3), the explanation of the workman (Ex. 4), the first notice to the workman stating that a domestic enquiry would be held against him on April 28, 1970 and the postal acknowledgement receipt thereof (Exts. 5 and 5a), the second notice and postal receipt thereof (Ex. 6 and 6a), the proceedings of the domestic enquiry (Ex. 7), the enquiry report (Ex. 8), the order of the Director accepting the report of the Enquiry officer and ordering dismissal (Ex. 9), and the letter of dismissal (Ex. 10).

5. On the materials on record, I have little to doubt that the concerned workman had gone on leave, had overstayed his leave, was still then permitted to resume his duties but he did not do so, and as the unauthorised absence thereafter amounted to misconduct, he was charged therefor. I have also little to doubt that the chargesheet was duly served upon the workman, so also was the notice of enquiry. The only doubt that I feel is about the manner in which the domestic enquiry was conducted. Kajal Kumar Sarkar, the Manager of Shankarpur Colliery, the only witness on behalf of the management, did not appear to me to be a candid and truthful witness. In answer to a question put by the Tribunal, the witness at first stated that the workman had cross-examined the witnesses produced by the management. When he was confronted with the proceedings of enquiry (Ex. 7), he was forced to admit that the workman did not cross-examine the witnesses and even refused to make any statement before the domestic tribunal. The records of the enquiry proceedings do not bear the signature of the workman or his thumb impression. The manner in which the records and the proceedings were kept and the way in which Kajal Kumar Sarkar deposed raise a suspicion in my mind that the workman may not have been given all the opportunities at the domestic enquiry, which the rules of natural justice require. Mr. N. Das, learned counsel for the management, wanted to salvage the position with the argument that the workman was not really interested to proceed with the case. He invited my attention to Ex. 11 copy of a letter addressed by the workman himself to the Assistant Labour Commissioner, Asansol, which I set out hereinbelow:

"I beg to submit that an Industrial Disputes had been raised over my dismissal from my appointment in Sunkerpore Colliery, P.O. Ukhra by the General Secretary Colliery Mazdoor Sabha, G.T. Road Asansol before A.L.C. (C), Raniganj.

I learnt that the said Dispute registered as case No. COR-16(245)/70 has been transferred to you and you are going to take up it.

I beg to inform that I am no longer interested in the above dispute and I have accepted the Management's decision of dismissal and I have no further dispute. I have severed all connection with the Union, namely, Colliery Mazdoor Sabha G.T. Road, Asansol. Copy of this letter is also being sent separately to the Management and to the Union."

The thumb impression of the workman on the above letter bears the identification seal of the local Gram Sabha authorities. Mr. Das submitted that since the workman was not concerned with the dispute, he did not care to cross-examine witnesses although he attended the domestic enquiry.

6. It is difficult for me to place absolute reliance on Ex. 11. If the workman had communicated before the Assistant Labour Commissioner that he was not any further concerned with the dispute, I wonder how a reference could be made or a failure report submitted. Be that as it may, I cannot proceed on mere suspicion against the management. All other materials exhibited point to the fact that the concerned workman was dismissed for misconduct. The workman himself does

not contest. I have no materials before me to hold that the dismissal of Kanta Harijan was not justified.

7. In the view that I take, I hold that the management of Shankarpur Colliery of Messrs Ukhra Minerals Private Limited was justified in dismissing Kanta Harijan from 19th May, 1970 and he is not entitled to any relief.

This is my award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

[No. 6/51/70-LR.II.]

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1819.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery of Messrs Goenka Coal Company, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 33 of 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery,
AND
Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Shri S. N. Mishra, Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Shri Benarashi Singh Azad, General Secretary of the Union.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. L/1912/3/71-LRII, dated February 11, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred an industrial dispute between the employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery and their workmen to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Goenka Kajora Colliery of Messrs Goenka Coal Company, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in stopping from work Shri Nageswar Prasad, Coal Cutting Machine Driver from the 4th July, 1969, to the 6th July, 1969, and the 16th July, 1969? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. This Reference is taken up out of turn on the joint request of the parties.

3. Neither the management nor the workmen filed their written statements. Parties filed a petition of settlement to-day, thereby compromising the dispute, which was referred to this Tribunal, on certain terms. Now that the parties have come to terms and resolved their dispute, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

(Sd.) B. N. BANERJEE,

Dated, April 12, 1971.

Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CALCUTTA

REFERENCE No. 33 of 1971

Management of Goenka Kajora Colliery of Goenka Coal Company, P.O. Ukhra,
Distt. Burdwan,

Vs.

Their workman represented through the Khan Shramik Congress, P.O. Ukhra,
Distt. Burdwan.

Most respectfully *Sheweth*

1. That the parties of the dispute have settled and resolved the difference of the following terms:—

(a) That the Management agrees to pay the full wages to Shri Nageswar Prasad, C.C.M. Driver for the period from 4th July, 1969 to 6th July, 1969 and for dt. 16th July, 1969.

(b) That the Union shall have no further claim whatsoever in relation to the dispute.

For workmen.

(Sd.) B. S. AZAD,
General Secretary,
Khan Shramik Congress,
P.O. Ukhra, Dt. Burdwan.

Witness.

(Sd.) P. N. ACHARYA,
Khan Shramik Congress,
P.O. Ukhra (Burdwan).

For Management.

(Sd.) S. N. MISHRA,
Personnel Officer, and Principal Officer
Goenka Kajora Colliery of
Goenka Coal Company.

[No. L-1912/3/71-LR.II.]

New Delhi the 26th April 1971

S.O. 1820.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery of Messrs Goenka Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 12 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Goenka Kajore Colliery,

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri S. N. Mishra, Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Sri Benarashi Singh Azad, General Secretary of the Union.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/41/70-LR.II, dated December 11, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred an industrial dispute between the management of Goenka Kajora Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Goenka Kajora Colliery of Messrs Goenka Coal Company, Post Office Ukhra, District Burdwan was justified in stopping from work Savashri Nageswar Prasad and Satanolal Gope, Coal Cutting Machine Drivers and Dukhan Thakur, Coal Cutting Machine Mazdoor from the 17th April, 1970? If not, to what relief these workmen are entitled?”

2. One written statement was filed on behalf of the workmen. Employers did not file any written statement. To-day, which was fixed as the date of peremptory hearing, the parties filed a petition of compromise, thereby settling the dispute referred to this Tribunal, on certain terms. Now that the parties have come to

terms, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

Dated, April 12, 1971.

(Sd.) B. N. BANERJEE,

Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CALCUTTA

REFERENCE No. 12 OF 1971

Management of Goenka Kajora Colliery of Goenka Coal Company, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.

Vs.

The workmen represented through the Khan Shramik Congress, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.

Most Respectfully sheweth

1. That the parties of the dispute have settled and resolved the difference on the following terms:

- (a) That the concerned workmen, Shri Nageswar Prasad and Shri Satanlal Gope, C.C. Machine Drivers shall be reinstated on their original jobs from 21st April, 1971 and Shri Dukhan Thakur, C.C.M. Mazdoor of the dispute shall be paid a sum of Rs. 100/- as full and final settlement.
- (b) That the period of non-employment of the workmen Shri Nageswar Prasad and Shri Satanlal Gope shall be treated as leave without pay with the continuity of their services.
- (c) A sum of Rs. 100/- each shall be paid as *Ex-gratia* to the workmen, Shri Nageswar Prasad and Shri Satanlal Gope, C.C. Machine Drivers.
- (d) That the union shall have no further claim whatsoever in relation to the dispute.

For Workmen.

(Sd.) B. S. AZAD,
General Secretary,
Khan Shramik Congress,
P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.

For Management:

(Sd.) S. N. MISHRA,
Personnel Officer,
and Principal Officer,
Goenka Kajora Colliery of
Goenka Coal Company.

Witness:

(Sd.) P. N. ACHARYA,
Khan Shramik Congress.
(Sd.) A. N. UPADHYAY,
G. K. Colly.

[No. 6/41/70-LR.II.]

S.O. 1821.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery, Post Office Ukhra, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 46 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery.

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri S. N. Mishra, Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Sri Benarashi Singh Azad, General Secretary of the Union.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. L/1912/17/71-LR.II, dated March 11, 1971, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Goenka Kajora Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Goenka Kajora Colliery Post Office Ukhra District Burdwan are justified in not providing employment to Shri Ajodhya Singh, Coal Cutting Machine Mazdoor with effect from the 23rd October, 1970? If not, to what relief the workmen is entitled?”

2. This reference is taken up out of turn on the joint request of the parties.

3. Neither the management nor the workmen filed their written statements. Parties filed a petition of settlement to-day, thereby compromising the dispute which was referred to this Tribunal, on certain terms. Now that the parties have come to terms and resolved their disputes, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

Dated, April 12, 1971.

(Sd.) B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

REFERENCE No. 46 OF 1971

Management of Goenka Kajora Colliery of Goenka Coal Company, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.

Vs.

Their workman represented through the Khan Shramik Congress, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan.

Most respectfully sheweth

That the parties of the dispute have settled and resolved the difference on the following terms:

- (a) That the workman, Shri Ajodhya Singh, C.C.M. Mazdoor shall be reinstated on his original job from 21st April, 1971 and the management shall maintain the continuity of the services of the workman.
- (b) The management agrees to pay a sum of Rs. 50/- as *ex-gratia*.
- (c) The period of non-employment of the workman shall be treated as authorised leave without pay.
- (d) That the Union have no further claim whatsoever in relation to the dispute.

For workman,

For Management.

(Sd.) B. S. AZAD,
General Secretary,
Khan Shramik Congress,
P.O. Ukhra, Burdwan.

(Sd.) S. N. MISHRA,
Personnel Officer,
Goenka Kajora Colliery,
P.O. Ukhra (Burdwan).

Witness.

(Sd.) P. N. ACHARYA,
Khan Shramik Congress,
P.O. Ukhra, Burdwan.

S.O. 1822.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ghanshyam Colliery, Post Office Baktarnagar, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 11 of 1971

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ghanshyam Colliery.

AND

Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Sri S. N. Murarka, Managing Director.

On behalf of Workmen—Sri R. B. Singh, concerned workman.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Coal Mines.

AWARD

By Order No. 6/25/70-LR11, dated December 21, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following dispute between the employers in relation to the management of Ghanshyam Colliery and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:

“Whether the management of Ghanshyam Colliery, Post Office Baktarnagar, District Burdwan is justified in terminating the services of Shri R. B. Singh, Overman-in-charge with effect from the 10th April, 1970, and if not, to what relief is he entitled?”

2. Both the parties filed their respective written statement. On the date of hearing, however, parties settled their dispute and in token thereof filed a petition of compromise before this Tribunal. Now, that the dispute between the parties stands settled, I pass an award in terms of the settlement. Let the petition of settlement form part of this award.

(Sd.) **B. N. BANERJEE,**
Presiding Officer.

Dated April 16, 1971.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

In the matter of:

REFERENCE No. 11 of 1971

BETWEEN

The employers in relation to the management of Ghanshyam Colliery.

AND

Their workmen represented by the Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), P.O. Raniganj, Burdwan.

The parties, above named most Respectfully Sheweth:

Without prejudice to the factual contentions raised by either of the parties, it is agreed:

1. That the management will pay to Sri R. B. Singh, Overman, the concerned workman, and the workman will accept a sum of Rs. 1,107:69 P. (Rupees One thousand one hundred and seven and sixty-nine paise) in full and complete satisfaction of all the claims by the workmen against the management.
2. The above sum of Rs. 1,107:69 P. shall be deposited by the management with this Tribunal within April 16, 1971, and the workman shall be at liberty to withdraw the amount from this Tribunal.

The parties, therefore, pray that an award in terms of above be passed in the matter under reference.

For Management,
(Sd.) S. N. MURARKA,
Mg. Director.

(Sd.) R. B. SINGH,
Concerned workman.

Dated April 8, 1971.

[No. 6/25/70-L.R.-II]

ORDERS

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1823.—In exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby rescinds the order of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1175, dated the 24th December, 1970 published in the Gazette of India, Part-II Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th March, 1971.

[No. 5/13/70-LR.II.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 1971

का० आ० 1823—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 1175 तारीख 24 दिसम्बर, 1970 को जो भारत के राजपत्र के भाग, 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुआ था, एतद्वारा विखण्डित करती है।

[सं० 5/13/70-एल० आर० 2]

New Delhi, the 19th April, 1971

S.O. 1824.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Coal Washing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whereas the dismissal of Shri Dwarika Prasad, Weighbridge Clerk by the management of Central Coal Washing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Jamadoba, Post Office Jealgora, District Dhanbad with effect from the 25th October, 1969 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. 2/114/70-LR.II.]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1971

का० आ० 1824—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जामादोबा, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद के सेंट्रल कोल वांशिंग प्लांट के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण, (सं० 2) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जामादोबा, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद के सेंट्रल कोल वांशिंग प्लांट के प्रबन्धतन्त्र द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद, बेब्रिज क्लर्क की 25 अक्टूबर, 1969 से पदच्युति न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? ”

[संख्या 2/114/70-एल० आर० 2]

S.O. 1825.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Equitable Coal Company Limited, Post Office, Dishergarh, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether having regard to the duties performed by Shri S. P. Dey, Clerk Grade-II, the management of Equitable Coal Company Limited, Post Office Dishergarh, District Burdwan is justified in not placing him in Grade-I as per Wage Board recommendations? If not, to what relief is the workman entitled and from what date?”

[No. 6/70/70-LRII.]

का० आ० 1825—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर दिशेगढ़, जिला बर्दवान के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या श्री एस० पी० डे, क्लर्क ग्रेड 2 द्वारा किए जाने वाले काम को ध्यान में रखते हुए, इक्विटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर दिशोरगढ़, जिला बर्दवान का उक्त मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार ग्रेड 1 में न रखना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है?”

[संख्या 6/70/70-एल० आर० 2]

S.O. 1826.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Ena Colliery of Messrs North West Coal Company Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Ena Colliery of Messrs North West Coal Company Limited Post Office, Dhansar, District Dhanbad in rendering Shri Damodar Sao, Munshi, idle with effect from the 16th March, 1970, was justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

[No. 2/110/70-LRII.]

का. शा० 1826—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स नार्थ वेस्ट कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर धनसार, जिला धनबाद की एना कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ?

अनुसूची

“क्या मैसर्स नार्थ वेस्ट कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर धनसार, जिला धनबाद की एना कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र की श्री दामोदर साओं, मुशी को 16 मार्च, 1970 से बेकार करने की कार्यवाही न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?”

[संख्या 2/110/70-एल० आर० 2]

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1827.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Ambajore, District Shahabad (Bihar) and their workmen represented by the Pyrites, Phosphates & Chemicals Staff Association;

And whereas the said employers and their workmen entered into a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 13th April, 1971.

Agreement

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties:

(1) Representing the Employers:

Shri T. N. Jaggi, Chief Mining Engineer.
Shri S. S. Gill, Mines Manager (Mines).
Shri M. L. Rajak, Administrative Officer.

(2) Representing the workmen:

- (1) Shri A. Dey, President, PPC Staff Association.
- (2) Shri R. Prasad, General Secretary, PPC Staff Association.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri Sarju Prasad Singh, Retired High Court Judge, Patna.

(I) Specific matters in dispute and Terms of Reference:

1. What should be the criteria for absorbing (as monthly rated regular staff) the monthly rated ad-hoc staff and the daily rated staff working since long against the post of monthly rated staff
2. Keeping in view the criteria, that may be decided by the Arbitrator, the demand of the PPC Staff Association for regularising as monthly rated staff all the ad-hoc staff and daily rated staff, is justified or not?

(II) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment/Undertaking:

- (a) Management of Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd., Amjhore, Distt. Shahabad (Bihar); and
- (b) Monthly rated and regular staff represented by PPC Staff Association.

(III) Name of the Union, if any, representing the workmen in question:

P.P.C. Staff Association.

(IV) Total No. of workmen employed in the Undertaking affected:

About 2170.

(V) No. of the workmen affected or likely to be affected by the dispute:

About 35.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall give his award within 3 months or within such further time as extended by mutual agreement in writing. In case the award is not made within the period aforesaid the reference to the arbitrator shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Management's Representatives:

Representatives of the monthly rated workers:

- (1) (Sd.) T. N. JAGGI
- (2) (Sd.) S. S. GILL
- (3) (Sd.) M. L. RAJAK

- (1) (Sd.) A. DEY,
- (2) (Sd.) R. PRASAD,
- General Secretary.

Witness:

(Sd.) Illegible

Date: 29-1-71.

Place: Amjhore.

नई दिल्ली 21 अप्रैल, 1971

का० या० 1827.—यतः पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ग्रामझोर जिला शाहाबाद (बिहार) के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स स्टाफ एसोसियेशन करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यम के लिए निर्देशित कर दिया है और उक्त माध्यस्थ करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थ करार को, जो उसे 13 अप्रैल, 1971 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

करार

पक्षकारों के नाम :

उनमें से एकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

- 1—श्री टी० एन० जम्ही, मुख्य खनन इंजीनियर ।
- 2— श्री एस० एस० गिल, खान प्रबन्धक (खान)
- 3—श्री एम० एल० राजक, प्रशासन अधिकारी मा

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

करने वाले :

- 1—श्री ए० डे, अध्यक्ष, पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन ।

- 2—श्री आर० प्रसाद महासचिव, पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री सरजु प्रसाद सिंह, उच्च न्यायालय के पटना के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

- 1— विनिर्दिष्ट के विवाद ग्रस्त 1—विषय और विचारार्थ विषयः

लम्बे समय से काम करने वाले मासिक दर के तदर्थ कर्मचारियों और दैनिक दर के कर्मचारियों को मासिक दर के कर्मचारियों के पदों पर खपाने (मासिक दर के नियमित कर्मचारियों के रूप में) के लिए क्या कसौटी होनी चाहिए?

2. उस कसौटी को ध्यान में रखते हुए जो मध्यस्थ द्वारा तय की जाए, क्या सभी तदर्थ कर्मचारियों और दैनिक दरों के कर्मचारियों को मासिक दर के कर्मचारियों के रूप में नियमित करने के लिए पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन की मांग अभ्यस्त है या नहीं?

2-क्रिया के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्-
वर्षित स्थापन, उपक्रम का नाम और पता भी
सम्मिलित है।

क-पाइराइट्स, फ स्फोट एण्ड कैमिकल्स,
लिमिटेड, अमझोर, जिला शाहाबाद (बिहार)
के प्रबंधक और

ख-मासिक दर के और नियमित कर्मचारी, जिनके
प्रतिनिधित्व पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन
करती है।

3-यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व
करता हो तो उसका नाम।

पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन

4-प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मचारों की कुल
संख्या लगभग 2170

5-विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः
प्रभावित होने वाले कर्मचारों की प्राक्कलित
संख्या लगभग 35

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर बंधनकारी होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच
पारस्परिक विवाद का कारण बनेगा, देगा। यदि पूर्व निर्धारित कालावधि के भीतर पंचाट
नहीं दिया जाता तो माध्यस्थ्य के लिए निदेश स्वतः रह जायगा और हम नए माध्यस्थ्य के लिए बात
चीत करने को स्वतंत्र होंगे।

निर्वाहकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मासिक दर के कर्मचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

(ह०) (1) टो० एन० जगो	(ह०) (1) ए० डे, अध्यक्ष
(ह०) (2) एस० एस० गिल	(ह०) (2) अरु प्रसाद,
(ह०) (3) एम० एल० राजक	महासचिव।

1-ह०.....

2-ह०.....

अमझोर तारीख : 29-1-71

[सं एल-29013/1/71-एल० आर०-4]

S.O. 1828.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Amjhore, District Shahabad (Bihar) and their workmen represented by the Pyrites, Phosphates and Chemicals Staff Association;

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), referred the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 13th April, 1971.

Agreement

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN.

Name of the Parties:

(1) Representing the Employers:

Shri T. N. Jaiswal Chief Mining Engineer.

Shri S. S. Gill. Mines Manager (Mines).

Shri M. L. Rajak, Administrative Officer.

(2) Representing the workmen:

(1) Shri A. Dev, President, PPC Staff Association.

(2) Shri R. Prasad, General Secretary PPC Staff Association.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri Sarju Prasad Singh, Retired High Court Judge, Patna

(I) *Specific matters in dispute and Terms of Reference:*

1. "Whether the demand of the PPC Staff Association that the following category of technical staff of the PPC Ltd., Amjhore, should be given **the same scales of pay including interim relief, if any, as are applicable to their counter-parts working under NMDC** is justified?

1. Mech. Foreman.
2. Head Mechanic.
3. Mechanic.
4. Electrical Supervisor.
5. Head Electrician.
6. Electrician.
7. Mine Foreman.
8. Mining Sirdar/Mate.
9. Shotfirer/Blaster.
10. Labour Assistant.
11. Assistant Surveyor.
12. Garage and Workshop Foreman.
13. Mine Surveyor.
14. Tyndal Supervisor.

2. If not, what should be their proper scale of pay as on 1st January, 1970?

The Arbitrator will be free to allow interim relief if he so thinks fit".

(II) *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment/Undertaking.*

(a) Management of Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., Amjhore, Distt., Shahabad (Bihar); and

(b) Monthly rated and regular staff represented by PPC Staff Association.

(III) *Name of the Union, if any, representing, the workmen in question:*

P.P.C. Staff Association.

(IV) *Total No. of workmen employed in the Undertaking affected:*

About 2170

(V) *No. of the workmen affected or likely to be affected by the dispute:*

About 100.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall give his award *within 3 months* or within such further time as is extended by mutual agreement in writing. In case the award is not made within the period aforesaid the reference to the arbitrator shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Managements Representatives:

- 1.(Sd.) T. N. JAGGI
- 2.(Sd.) S. S. GILL
- 3.(Sd.) M. L. RAJAK

Representatives of the monthly rated workers.

- 1.(Sd.) A. DEY,
 - 2.(Sd.) R. PRASAD,
- General Secretary.

Witness:

Place:—Amjhore.

Date:—29-1-71

[No. L-29013/2/71-LRIV.]

कां०आ० 1828.—यतः पाइराइट्स, फोस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०, अमझोर, जिला शाहाबाद (बिहार) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व पाइराइट्स फोस्फेट्स एण्ड केमिकल्स स्टाफ एसोसियेशन करता है एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, यतः उक्त नियोजकों और कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) 1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों अनुसरण में एक लिखित करार

द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार किया है और उक्त माध्यस्थ, करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थ करार को, ज उसे 13 अप्रैल, 1971 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है :

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

- 1 श्री टी० एन० जग्गी,
मुख्य खनन इंजीनियर
- 2 श्री एस० एस० गिल,
खान प्रबन्धक (खान) ।
- 3 श्री एम० एल० रजक,
प्रशासन अधिकारी ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

- 1 श्री ए० डे०,
अध्यक्ष, पी० पी० सी०, स्टाफ एसोसियेशन ।
- 2 श्री आर० प्रसाद,
महा सचिव,
पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन :

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री सरज प्रसाद सिंह सेवा-निवृत्त छत्त न्यायालय, न्यायाधीश, पटना के माध्यस्थ के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय और विचारार्थ विषय

“क्या पी० पी० सी० स्टाफ एसोसियेशन की यह मांग न्यायोचित है कि पी० पी० सी० लि० अमझोर खनन प्रायोजना के निम्नलिखित वर्ग के तकनीकी कर्मचारियों को, अन्तरिम सहायता सहित यदि कोई हों, वही वेतन-मान दिए जाने चाहिए जो कि एन० एम० डी० सी० के अधीन काम कर रहे उनके प्रतिस्थानियों को दिए जाते हैं :—

1. मेक० फोरमैन ।
2. हेड मेकेनिक ।
3. मेकेनिक ।
4. इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर ।
5. हेड इलेक्ट्रिशियन ।
6. इलेक्ट्रिशियन ।
7. माइन फोरमैन ।
8. माइनिंग सिरदार/मेट ।
9. शोर्टफायरर/ग्लास्टर ।

10. लेब० एसिसटेंट ।
11. एसिसटेंट सर्वेयर ।
12. गैरेज एन्ड वर्कशाप फोरमैन ।
13. माइन सर्वेयर ।
14. टिण्डल सुपरवाइजर ।

2. यदि नहीं, तो 1-1-1970 को उनका उचित वेतन मान क्या होना चाहिए ?

मध्यस्थ प्रास्तक्षि सहायता देने में स्वतंत्र होंगे यदि वह इसे उचित समझे ।

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें (क) पाइराट्स, फोस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स अर्तवर्लित स्थापन या उपक्रम का नाम और लि०, अमझोर, जिला शाहाबाद (बिहार) पता भी सम्मिलित है : के प्रबन्धक और

(ख) मासिक दर वाले और नियमित कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व पी० पी० सी०, स्टाफ एसोसियेशन करती है ।

3. यदि कोई तब प्रश्नगत क (कारों का प्रति- निधित्व करता हो तो उसका नाम ।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 2170

5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की प्राकलित संख्या । लगभग 100

हम यह कारण भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा / यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रह ही जायगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

1. ह०/- टी० एम० जग्गी

2. ह०/- एस० एस० गिल

3. ह०/- एम० एल० रजक

ह०/- ए० डे

अध्यक्ष,

ह०/-आर० प्रसाद

महा सचिव

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

मासिक दर पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले

साक्षी

1 ह०/-

स्थान : अमझोर

तारीख : 29-1-1971

New Delhi, the 26th April 1971

S.O. 1829.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Victory (G. L. Group) Colliery of Messrs Coal Products Private Limited, Post Office Gogla, District Burdwan (hereinafter referred to as the said **Employees**) and their workmen represented by the Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.), G.T. Road, Asansol, District Burdwan;

And whereas the said employers and workmen have by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration of the person specified therein and a copy of the said agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the said arbitration agreement, which has been received by it on the 19th April, 1971.

Agreement

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties:

Representing employers:

Shri A. Rahim, Manager, Victory (G.L. Group) Colliery, M/s. Coal Products (P) Ltd., P.O. Gogla, Dist. Burdwan.

Representing the workmen:

Shri Sunil Sen, Organising Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), G.T. Road, Asansol.

It is agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of Shri R. J. T. D'Mello, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

(1) Specific matters in dispute:

"Keeping in view the recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry as accepted by the Government of India in their Resolution No. WB-16(5)/66, dated the 21st July, 1967 as well as the financial position of Victory (G.L. Group) Colliery of M/s Coal Products (P) Ltd., P.O. Gogla, Dist. Burdwan (West Bengal) what should be the rate of D.A. payable to the workmen employed at Victory (G.L. Group) Colliery with effect from 1st April, 1970 and 1st October, 1970?"

- | | |
|--|--|
| (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking. | Victory (G.L. Group) Colliery, M/s. Coal Products (P) Ltd., P.O. Gogla, Dist. Burdwan. |
| (iii) Name of the union, if any representing the workmen in question. | Colliery Mazdoor Sabha (A.I.T.U.C.), G.T. Road, P.O. Asansol, Dist. Burdwan. |
| (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected. | 425 |
| (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. | 425 |

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his award within a period of one hundred thirty days or within such further time as is entered by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the

reference to Arbitrator shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties:

(Sd.) A RAHIM, Manager.

Representing the employers:

(Sd.) SUNIL SEN, Organising Secretary.

Representing the workmen:

Witnesses:

1. (Sd.) S. K. MUKHERJEE,
26-3-71.

2. (Sd.) G. C. SHARMA,
26-3-71.

Dated, the 26th March, 1971.

[No. L/1913/7/71-LRII.]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1971

का० घा० 1829—यतः मैसर्स कोल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर गोगला, जिला बर्दवान (इसके बाद उक्त कम्पनी के रूप में निर्देशित किया गया है) के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व कोलियरी मजदूर सभा (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस), जी० टी० रोड, आसनसोल, जिला बर्दवान (इसके बाद उक्त यूनियन के रूप में निर्देशित किया गया है) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यमस्थ के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यमस्थ करार को एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यमस्थ करार को जो उसे 19 अप्रैल, 1971 को मिला था एतद्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले :

1. श्री ए० रहीम, प्रबन्धक विक्टरी, (जी० एल० ग्रुप) कोलियरी मैसर्स कोल प्रोडक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड डाकघर गोगला, जिला बर्दवान ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

श्री सुनील सेन, संगठन सचिव, कोलियरी मजदूर सभा (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस), जी० टी० रोड, आसनसोल ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री आर० जे० टी० डीमेल्ली, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के माध्यमस्थ के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1 ; विनिर्दिष्ट विवाद अस्त विषय :

“भारत सरकार द्वारा अपने संकल्प संख्या डब्ल्यू० वी० 16(5)/166, तारीख 21 जुलाई

1967 में स्वीकृत कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों और मैसर्स कोल प्राइवेट्स (प्रा०) लिमिटेड डाकघर गोगला, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल की विक्टरी (जी० एल० ग्रुप) कोलियरी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विक्टरी (जी० एल० ग्रुप) कोलियरी में नियोजित कर्मकारों को देय महंगाई भत्ते की दर 1-4-1970 से 1-10-1970 तक क्या होनी चाहिए।”

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अर्त-बलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। विक्टरी (जी० एल० ग्रुप) कोलियरी मैसर्स कोल प्राइवेट्स (प्रा०) लिमिटेड, डाकघर गोगला, जिला बर्दवान।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका नाम। कोलियरी मजदूर सभा (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस) जी० टी० रोड, डाकघर आसनसोल, जिला बर्दवान।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या। 425

5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राप्तकालित संख्या। 425

हम यह करार भी करते हैं कि माध्यस्थ का विनश्चय हम पर बाबद्ध कर होगा।

माध्यस्थ अपना पंचाट एक सौ तीस दिन की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थ के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थ के लिए बातचीत करने का स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

(ह०।) ए० रहीम

प्रबंधक

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले।

ह०। सुनील सेन

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले।

साक्षी :

1. (ह०) एस० के० मुखर्जी

2. (ह०) जी० सी० शर्मा

तारीख : 26 मार्च, 1971

[संख्या एल० 1913 (7)/71 एल० आर० 2]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April 1971

S.O. 1830.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) S.O. No. 4057, dated the 10th December, 1970 published on page 5776 of the Gazette of India Part II, Section 3. Sub-section (ii), dated the 26th December, 1970, in the Schedule for "Singareni Collieries Company Limited" read "No. 1 Incline Somagudem Mine of Belampalli Division of Singareni Collieries Company Limited."

[No. 1/39/70-LR.II.]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 20th April, 1971

S.O. 1831.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bangalore, in the industrial dispute between the employers in relation to the Vijaya Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th April, 1971.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN MYSORE, BANGALORE

Dated 7th April, 1971

PRESENT:

Sri Narayan Rai Kudoor, B.A., B.L., Presiding Officer.

REFERENCE NO. 4 OF 1969 (CENTRAL)

I Party

The workmen of the Vijaya Bank Ltd., Mangalore, South Kanara.

Vs.

II Party

The Management of the Vijaya Bank Ltd., Regd. Office, Light House Hill Road, Mangalore-2, South Kanara.

APPEARANCES:

For the I Party—Sri A. L. Hebbar, General Secretary, The Vijaya Bank Employees' Association, Coast Road, Coondapoor, South Kanara.

For the II Party—Sri V. S. Ganeshan.

Reference

Order No. 23/98/69/LRIII dated 27th September, 1969, of the Under Secretary to Government, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment).

AWARD

The Central Government, as per their Order No. 23/98/69/LRIII dated 27th July, 1969, have referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the Vijaya Bank Limited and their workmen to this Tribunal for adjudication in exercise of the powers conferred by Section 7-A and Clause (d) of Sub-Section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947) **setting out the following point of dispute viz.**

"Whether the management of the Vijaya Bank Limited, Mangalore-3, was justified in transferring Shri C. Gopinathan Nair, President of the Vijaya Bank Employees' Association, Coondapoor from their Kalpetta Branch (Kerala State) to Aldur Branch (Mysore State)? If not, to what relief is he entitled?"

2. The cause of the concerned workman has been sponsored and taken up by the Vijaya Bank Employees' Association, Coondapoor, represented by its General Secretary, Sri A. L. Hebbar. This Association, as representation the aggrieved workman is the I Party and the Management of the Vijaya Bank Limited, is the II Party in these proceedings.

3. After the reference was received in this Tribunal, notices were caused to be issued to both the Parties calling upon them to file their Statement of Demands. In pursuance of the notices, the I Party and the II Party have submitted their statement of demands dated 12th November, 1969, and 28th November, 1969, respectively.

4. The case put forward by the I Party in their statement, briefly stated, is as follows:—

Sri C. Gopinathan Nair, President of the I Party Association, working in Kalpetta Branch in Kerala State of the II Party was transferred to their Aldur Branch (Mysore State) by their order dated 25th June, 1969. He was elected as the President of the Association by the General Body held on 22nd December, 1968, and his election was duly communicated to the II Party on 26th December, 1968, to recognise him as a 'protected workman'. The I Party had vast membership in the State of Kerala. He was guiding the members of the I Party in his capacity as President. His activities connected with the I Party-Association incurred the displeasure of the II Party. With a view to prevent him from taking active part in his Trade Union Activities the II Party disturbed him from the Kalpetta Branch by transferring him to Aldur Branch in Mysore State. His transfer was a deliberate act of victimisation and unfair labour practice employed by the II Party with an ulterior motive of disrupting the I Party. He was a protected workman and his transfer was not connected with the business interests of II Party and exigency of service. The II Party has committed breach of Rule 61 of the Industrial Disputes (Central) Rules 1957. Besides, the II Party also has violated the directions contained in paragraph 535 of the Sastry Award. The transfer order in question suffers from other irregularities and illegalities. Besides, his transfer beyond the language area and made without his consent and against his will is a clear contravention of the directions contained in para 536 of the Sastry Award. In these circumstances, the I Party urged to set aside the order of transfer passed against Sri C. Gopinathan and also prayed for granting such other reliefs as it deems fit and proper under the circumstances of the case, with costs.

5. The II Party in their Statement dated 28th November, 1969, emphatically denied the allegation of victimisation and their employing unfair labour practice levelled against them. Further, they also questioned in the *locus standi* of Sri A. L. Hebbar to represent the I Party-Association in these proceedings. Their case on this aspect, is that they were informed by the Vijaya Bank Employees' Association in the latter part of the year 1968 that new office bearers have been elected to the I Party-Association at an Extraordinary General Body Meeting held on 6th October, 1968, replacing the previous Office Bearers among whom Sri A. L. Hebbar the General Secretary of the Association, was one. So he ceased to be the General Secretary of the I Party-Association since 6th October, 1968. That being so, he is not competent to represent the I Party-Association muchless the concerned workman in these proceedings. Dealing with the question of transfer of Sri C. Gopinathan Nair, it is contended by the II Party that his transfer was necessitated by the exigencies of service and administration. Transfers are normal incident of the working of the Bank and what was done by the II Party was within the ambit of their discretionary powers. In the communication addressed by Sri A. L. Hebbar to the II Party, he has not stated that Sri C. Gopinathan Nair falls within the category of 'Protected Workman'. The allegations that the II Party had effected the transfer of Sri C. Gopinathan Nair with a view to cripple his trade union activities connected with the I Party-Association and that it was a deliberate act of victimisation and unfair labour practice are all contrary to realities and facts. It is equally incorrect to say that the II Party had frequently violated the directions contained in paragraph 535 of the Sastry Award. In fact, the II Party at no time has contravened the directions contained either in paragraph 535 or 536 of the said Award. The award only prohibits the transfer of subordinate staff beyond the language area and does not prohibit the transfer of clerical staff beyond the language area. The dispute raised by the I Party does not fall within the ambit of industrial dispute inasmuch as Sri A. L. Hebbar cannot lawfully represent the I Party-Association. Finally, it is prayed that the claim of the I Party be rejected with costs of the II Party.

6. The I Party has filed a reply dated 28th December, 1969, reiterating their stand taken in the statement of claim.

7. On the above pleadings, my learned predecessor had framed the following Issues in addition to the points of dispute scheduled in the Order of Reference:—

"1. Whether the transfer of Sri Gopinathan Nair is *mala fide* and deliberate act of victimisation and unfair labour practice on the Part of the II Party-Management?

2. Whether the transfer of Sri Gopinathan Nair is in contravention of paragraph 536 of the Sastry Award?

3. Whether the II Party management has transferred Sri Gopinathan Nair without complying with and in violation of the directions contained in paragraph 535 of the Sastry Award?
4. Whether, by transferring Sri Gopinathan Nair, the II Party management has committed breach of Rule 61 of the Industrial Disputes (Central Rules) 1957?
5. Whether Sri A. L. Hebbar is incompetent to represent the Vijaya Bank Employees' Association or the employees of the II Party, as alleged in the counter statement?
6. Whether the dispute in question is an industrial dispute within the meaning of Sec. 2 (k) of the Industrial Disputes Act, 1947?
7. To what reliefs are the Parties entitled?"

8. After the Issues were settled, the case was posted for Enquiry and the Parties were informed of the date of hearing. When the case was pending enquiry, an application was filed by one H. Sudhakar Shetty styling himself as the General Secretary of the Vijaya Bank Employees' Association dated 20th February, 1970, requesting to implead him in the place of Sri A. L. Hebbar as General Secretary of the I Party Union as he is the duly authorised representative of the I Party Association to take part in these proceedings. In the circumstances of the case, I feel it unnecessary to detail the grounds on which the application in question is grounded. The I Party filed their counter dated 4th March, 1970, and opposed the impleading application. The Intervenor has filed his reply dated 10th April, 1970. The application for impleading was also set down for hearing. While the matter was pending enquiry, the II Party has filed an additional statement dated 29th September, 1970, bringing to the notice of the Tribunal certain developments that have taken place subsequent to the Reference. It is averred therein that subsequent to the Reference, Sri Gopinathan Nair has ceased to be the Member of the I Party as he has joined the Vijaya Bank Employees Union (Registered) at a date earlier to 15th August, 1970, and the II Party has received the communication to that effect. According to the communication, the said Gopinathan Nair is the General Secretary (Aldur) of the Vijaya Bank Employees' Union which is a body affiliated to all India Bank Employees' Association. That being so, the I Party has no subsisting interest in pursuing the reference and as such, the Reference may be rejected. Thereafter, the I Party has filed a Memo dated 28th November, 1970, admitting the averments made by the II Party in their further statement and stated that the Issue is not pressed since the dispute referred for adjudication does not survive.

9. In view of the above memo filed by the I Party, I feel it unnecessary to consider the impleading application filed by the Intervenor, Sri H. Sudhakar Shetty or the main matter on merits, as the I Party has indicated in the Memo referred to above that the Issue is not pressed. That being so, the dispute involved in the reference does not survive for adjudication and hence the reference has to be rejected.

10. In the circumstances aforesaid, I pass an award rejecting the Reference. There will be no order as to costs.

(Sd.) NARAYANAN RAI KUDOOOR,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, B'lore.
[No. F. 23/98/69/LR. III.]

S.O. 1832.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th April, 1971.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

REFERENCE No. 5 OF 1971

PARTIES:

Employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited, Calcutta,
AND
Their workmen.

PRESENT:

Mr. B. N. Banerjee, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. M. S. Bala.

On behalf of Workmen—Mr. A. D. Singh.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY: Banking.

AWARD

By Order No. 23/116/70-LR-III, dated December 10, 1970, the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), referred the following industrial dispute between the employers in relation to the National and Grindlays Bank Limited, Calcutta and their workmen, to this Tribunal, for adjudication, namely:—

"Whether the action of the management of the National and Grindlays Bank Limited, Calcutta in appointing Shri Narayan Chandra Behara, in the sub-staff category, with effect from the 15th May, 1970 was justified, having regard to the existing procedure of giving an opportunity to sons/dependents of retired, disabled and retiring employees of the bank for consideration. If not, what procedure, if any, should be adopted by the Bank to fill the vacancy afresh?"

2. The National and Grindlays Bank Staff Union filed one written statement. In paragraph 2 of the said written statement, it was stated that a vacancy had occurred in the main Calcutta office of the Bank and notices were displaced on the notice boards of all the branches in Calcutta on April 25, 1970, notifying that such a vacancy existed and inviting applications within April 29, 1970. The grievance as regards this notice was pleaded in paragraphs 3 and 4 of the written statement, which are set out below:

"3. That the period for putting in the application was so short that most of the sons/dependents of the retired employees could not get sufficient time to apply before the scheduled date.

4. That the limitation of time was wilfully kept very short so that the candidates could not apply within the specified time because the management had already decided to recruit Shri Narayan Chandra Behara, and the display of the notice was merely an eye wash."

Nevertheless, it was pleaded in paragraph 6 of the said written statement, one application on behalf of one Rajeshwar Singh and another on behalf of one Sarkar Bahadur Singh were submitted, in time, respectively by Ram Deo Singh and Sree Prasad Singh. In paragraph 8 of the written statement it was stated:

"That the management finally filled up the vacancy by recruiting Shri Narayan Chandra Behara on 15th May, 1970, Sarvashri Rajeshwar Singh and Sarkar Bahadur Singh were not called for interview, because the bank knew fully well that they were more qualified, competent and experienced than Shri Behara."

3. The management also filed a written statement. In paragraph 5 of the said written statement, they alleged that the appointment of Narayan Chandra Behara in the subordinate cadre was justified as he was the son of a retired employee of the Bank and that recruitment of staff was in the sole discretion of the management. In paragraph 3 of their written statement the Bank justified the sufficiency of the notice, in the following language:

"With regard to para 3 of the petition, Management states the question of 'short' notice does not arise, as candidates seeking employment in the Bank always apply in anticipation of vacancies and these applications are filed and considered at the appropriate time. It is a matter of absolute discretion of the Management to fix any date by which applicants should apply."

In paragraph 10 of the written statement, the management explained the reason why they did not consider the other applications with the statement that the management was under no obligation to consider the applications submitted on behalf of the applicants.

4. In the background of these pleadings, I have to consider the industrial dispute referred to this Tribunal.

5. The question of appointing relatives of present or past workmen of the Bank in vacancies as they occur has been coming up again and again before this Tribunal. In Reference No. 108 of 1969 between the same parties, the dispute that was referred to this Tribunal was couched in the following language:

"Whether the action of the management of the National and Grindlays Bank Limited, Calcutta in making appointment to seven posts in the subordinate category of staff during the period from 27th January to the 7th April, 1969 was justified, having regard to the established practice of notifying the vacancies for the benefit of the relatives of the workmen and understanding reached on the 17th August, 1967 between the bank and the National and Grindlays Bank Staff Union.***"

In paragraph 5 of the said award the following observations appear:

"I have now to see whether there was, as alleged in paragraph 5, a gentleman's assurance and understanding given by the Bank to the National Grindlays Staff Union on 17th August, 1967. That document is a report of the Conciliation Officer, on a previous dispute with the Bank management and the present trade union, marked Ex. D by consent, and reads as follows:

Mr. A. S. Barrow, Accountant with Shri A. Roy Choudhury, Labour Adviser of the Bank on behalf of the management while S/Shri A. D. Singh and G. A. Singh, appeared on behalf of the union. The management agreed to ensure in future that union dues are not deducted from those employees who have not authorised the bank to do so. As regard recruitment to the sub-staff category, the bank should, whenever any vacancy arises, display a notice on the notice board for the general information of all eligible candidates. In the matter of recruitment the bank shall follow the provisions of the bipartite settlement dated 19th October, 1966 and their prevalent practice with regard to relations. The union is satisfied with this and in case there is any breach of such understanding they are free to take up the matter in accordance with law.

This case is not pursued further. "(Underlined by me for emphasis)."

I do not find from Ex. D that any agreement was made or any assurance was given by the Bank. The Assistant Labour Commissioner wished that whenever a new vacancy would arise, the Bank should display a notice on the notice Board for the general information of all eligible candidates. By not giving such a notice the Bank might have disregarded the wish of the Assistant Labour Commissioner but did not violate any agreement or disregarded any assurance."

I took note, in that award, of a letter, dated October 23, 1967 (marked Ex. E in that Reference), by which the Bank agreed:

"(1) In recruiting clerical staff the following criteria will be observed.

Other things being equal, preference will be given to one son or daughter or dependent; (a) of a retired employees, (b) any employee who has had to leave the service of the Bank through disablement/sickness, (c) an employee on point of retirement;

(2) In all such cases the applicant must sit with others and obtain a satisfactory pass and the otherwise fit for appointment.

In respect of recruitment of subordinate staff the conditions laid down in paragraphs 1(a), (b) and (c) will also apply."

About the aforesaid letter I made the following further observations:

"To do so is not to encourage hereditary claim to any office but when qualifications are equal, there is no reason why a particular candidate should not get the benefit of past loyal services put in by his predecessor relative or relatives."

In course of hearing of that Reference, the management of the Bank and the workmen showed a very reasonable frame of mind and basing upon their agreement the Tribunal awarded, "that in future the Bank would publish a notification of recruitment on the Notice Board of the local branches and on the Notice Board of the main office of the Bank it being distinctly understood that such notices will be published only in the branches of the particular locality. For example, if the recruitment is for Calcutta the notification will be published at the Calcutta branches and at no other place. Mr. A. D. Singh, appearing for the workmen,

was willing to accept the procedure as a proper procedure. In my opinion, the best thing to do in the circumstances of the case is to direct the Bank to do so hereinbefore stated". The said award was published in the Gazette of India on May 23, 1970 and became effective under Section 17A of the Industrial Disputes Act on the expiry of 30 days from the date of its publication under Section 17. Thus, the award did not become effective prior to June 23, 1970. It appears from the letter dated May 13, 1970 (Ex. A) that Narayan Chandra Behara was selected for appointment as a member of the subordinate staff with effect from May 15, 1970. Thus, at the time when the bank published the vacancy notice or made the appointment, the award in Reference No. 108 of 1969 was not operative.

6. Nevertheless, the procedure for appointment, of a sub-staff, in a vacancy in the Bank, conformed substantially to the procedure set out in letter dated October 23, 1967 (already set out). It appears from Ex. B, the application for employment submitted by Narayan Chandra Behara, that he is son of one Sonakar Behara, an ex-employee of the Bank. Therefore, ultimately the son of an ex-employee of the Bank was appointed in the vacancy.

7. Although that is so, I have still then to consider several other grievances made by Mr. A. D. Singh, appearing for the trade union. He submitted, in the first place, that the notice of vacancy, which gave only 4 days to apply was much too short a notice. In this grievance Mr. Singh is justified. All notices must be reasonable notices unless there be a limit thereon by a statute. If relatives of employees or ex-employees are to apply, they may not be readily available in Calcutta. They have to be informed and may have to send their applications by post. Four days time to apply seems to be wholly insufficient time for that purpose.

8. Although that is so, the award in Reference No. 108 of 1969 was not binding on the Bank on the date when the appointment was made and there was no obligation on the part of the Bank to display a notice at all. That being so, I can only take of the future and may ask the Bank that in future all notices of vacancies must give at least 15 days time to prospective applicants to apply.

9. Mr. Singh further contended that the appointment of Narayan Chandra Behara was a foregone conclusion. The display of notice of invitation for applications and interview of candidates were all eye washes. The management had a closed mind and were determined to appoint Narayan Chandra Behara. He invited my attention to letter Ex. 1, addressed by the trade union to the General Manager of the Bank in London, dated April 30, 1970, from which I set out the material portion:

"That the dominant proof of the collusion is the present recruitment case, which is yet to be made. The management displayed a notice for recruitment on the notice-board on 25th of this month and the last date of submitting the applications was fixed 29th April 1970. This short and unreasonable period was decided in order to avoid the sons/dependents of the retired staff, hailing from far off places in other provinces of the country.

That we have reason to believe that the management has already decided to recruit Shri Narayan Chandra Behara, son of Shri Sonakar Behara, at the instance of the said union and the notice is a mere formality and an eye wash."

Mr. Singh contended that if the appointment was made with effect from May 15, 1970, there was no point in having already chosen Narayan Chandra Behara as far back as on April 30, 1970. He submitted that unless the choice had already been made, they could not write a letter like Ex. 1 to the General Manager, London on April 30, 1970. Mr. Balu submitted that an inference of malafides should not lightly be made against the management. According to him, the selection was made on 30th April although the letter of appointment was later on issued. The news might have leaked out and that explains how the letter could be written to the London Manager on April 30, 1970. In my opinion, letter Ex. 1, raises a good deal of suspicion against the conduct of the management but suspicion is not proof and on that evidence alone, I cannot hold that the management proceeded in the matter of selection of candidate with a forewarned mind.

10. The last grievance made by Mr. Singh was that the application filed on behalf of Sarkar Bahadur Singh by his grandfather Sree Prasad Singh was not considered. An application must be made by the applicant himself. The application may mention past services rendered by the applicants relatives, as a matter of special consideration, but if the applicant does not apply himself, an application

on his behalf by somebody else need not be considered. This is all the more so because it appears that there is a prescribed form of application in the Bank, in which form the application was not made. I, therefore, make little of this grievance made by Mr. Singh.

11. In the view that I take, I hold that the action of the management of National and Grindlays Bank Limited, Calcutta in appointing Narayan Chandra Behara in the subordinate category with effect from 15th May, 1970 was justified. I, further, hold that although justified, the notice inviting application was insufficient and in future all notices inviting applications for vacancies must give at least 15 days notice in writing to enable prospective applicants to apply. That should be the procedure adopted by the Bank to fill up vacancies, in addition to the procedure prescribed in the award of this Tribunal in Reference No. 108 of 1969.

This is my award.

Dated, April 5, 1971.

Sd./- B. N. BANERJEE,
Presiding Officer.
[No. F.23/116/70-LRIII.]

S.O. 1833.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bangalore, in the industrial dispute between the employers in relation to the Vijaya Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th April, 1971.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN MYSORE, BANGALORE.

Dated 6th April, 1971

PRESENT:

Sri Narayan Rai Kudoor, B.A., B.L.,—Presiding Officer.

REFERENCE NO. 2 OF 1969 (CENTRAL)

I Party:

The workmen of the Vijaya Bank Ltd., Mangalore, South Kanara.

Vs.

II Party:

The Management of the Vijaya Bank Ltd., Regd., Office, Lighthouse Hill Road, Mangalore-2, South Kanara.

APPEARANCES:

For the I Party.—Sri A. L. Hebbar, General Secretary, The Vijaya Bank Employees' Association, Coast Road, Coondapoor, South Kanara.

For the II Party.—Sri V. S. Ganeshan.

REFERENCE

Order No. 23/78/69/LRIII dated 8th September, 1969, of the Under Secretary to Government, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment).

AWARD

The above Reference was received from the Central Government in exercise of the powers conferred upon them under Section 7-A and Clause (d) of Sub-Section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947) for adjudication an industrial dispute between the workmen and the management of the Vijaya Bank Ltd., setting out the undermentioned point of dispute viz.

“Whether the management of Vijaya Bank Limited, Mangalore-3, was justified in transferring Shri A. P. Tinalkar, Joint Secretary of the Vijaya Bank Employees' Association, Coondapoor from their Dharwar Branch to K. G. Road, Bangalore Branch? If not, to what relief is he entitled?”

2. The cause of the concerned workman has been sponsored and taken up by the Vijaya Bank Employees' Association, Coondapoor, (South Kanara). This

association, as representing the workman, is I Party and the Management of Vijaya Bank Limited, is the II Party in these proceedings.

3. After the reference was received in this Tribunal, on notices being served, the I Party and the II Party have submitted their Statements of Demands dated 14th October, 1969, and 28th November, 1969, respectively.

4. The case put forward by the I Party in their Statement briefly stated is as follows:—

The concerned workman Sri A. P. Tinaikar was the Joint Secretary of the I Party-Association working in the Dharwar Branch of the II Party. He was an active Member of the I Party which was in its formative stage. His Trade Union activities incurred the displeasure of the II Party. In order to prevent him from taking interest in the activities of the I Party, the II Party had displaced him from Dharwar by transferring him to its Branch at K. G. Road, Bangalore, by an order dated 4th October, 1968. The transfer in question was a case of victimisation. It transpired that on his transfer to Bangalore, he was even manhandled by Sri B. N. R. Hegde who is an employee of the II Party in the presence of the other employees. The conduct of the II Party in transferring Sri A. P. Tinaikar is in contravention of Section 28K of the Indian Trade Unions Act, as the said act of theirs is nothing but an attempt to disrupt the activities of the Trade Union of their employees. The II Party is guilty of unfair labour practice and they had flagrantly violated the directions contained in paragraph 535 of Sastry Award. Notice of transfer was not posted on the Notice Board. It does not indicate the special circumstances in which he was transferred. The representation of the Union was not even considered by the II Party. In these circumstances, the I Party requested to set aside the order of transfer of Sri A. P. Tinaikar and to restore him to his position at Dharwar Branch with such other reliefs as it deems fit and proper, with costs.

5. The II Party in their statement dated 28th November, 1969, denied the allegations levelled against them *inter alia* contending as follows:—

They questioned the very right of Sri A. L. Hebbar who is representing the I Party as its General Secretary on the ground that he ceased to be the General Secretary of the Vijaya Bank Employees' Association. Their case is that they were informed by the Vijaya Bank Employees' Association in the later part of the year 1968 that new office-bearers had been elected at an extra ordinary General Body Meeting of the Association held on 6th October, 1968, replacing the previous office bearers among whom Sri A. L. Hebbar, the General Secretary of the Union was one and hence, he is not competent to represent the Association in these proceedings. Dealing with the question of transfer of Sri A. P. Tinaikar out of which the present reference was founded it is contended by the II Party that his transfer was necessitated by the exigencies of service and administration. Transfers are normal incidents of the working of the Bank and what was done by the II Party was within their discretionary powers. His transfer has nothing to do with his Trade Union Activities as alleged. He was transferred to the more important place wherein at present the Administrative Office of the II Party is situated. The allegation of victimisation and unfair labour practice are all unfounded and denied. Further it is urged that the dispute raised by the I Party does not fall within the ambit of the Industrial Dispute in as much as Sri A. L. Hebbar cannot lawfully represent the Association. Finally, it is prayed that the claim of the I Party be rejected with costs of the II Party.

6. The I Party has filed a reply statement dated 28th December, 1969, reiterating their stand taken in their statement of claim.

7. On the above pleadings, my learned predecessor had framed the following Issues in addition to the points of dispute scheduled in the Order of Reference:—

- "1. Whether the transfer of Sri A. P. Tinaikar was *mala fide* and a deliberate act of victimisation and unfair labour practice on the part of the II Party-Management?
2. Whether the II Party management has transferred Sri A. P. Tinaikar without following the directions contained in paragraph 535 of Sastry Award? And if so, is the said transfer bad?
3. Whether Sri A. L. Hebbar is incompetent to represent the Vijaya Bank Employees' Association or the employees of the II Party as alleged in the Counter Statement?
4. Whether the dispute in question is an Industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947?
5. To what reliefs are the Parties entitled?

8. After the issues were settled, the case was posted for Enquiry and the parties were notified of the date of hearing. When the case was pending enquiry, an application was filed by one Sri H. Sudhakar Shetty styling himself as the General Secretary of the Vijaya Bank Employees' Association, dated 20th February, 1970, requesting to implead him in the place of Sri A. L. Hebbar as General Secretary of the I Party Union as he is the duly authorised representative of the I Party Association to take part in the proceedings. In the circumstances of the case, it is unnecessary to detail the grounds on which the application in question is grounded. The I Party has by their Counter dated 4th March, 1970, opposed the application. The Intervener has filed his reply dated 10th April, 1970. The application for impleading was also set down for hearing. In the meanwhile, on 26th September, 1970, the II Party has filed an additional statement bringing to the notice of the Tribunal certain developments that have taken place subsequent to the reference. It is averred therein that subsequent to the reference, Sri A. P. Tinaikar ceased to be the Member of the I Party as he has joined the Vijaya Bank Employees Union (Regd.) at a date earlier to 15th August, 1970, and the II Party had received a communication to that effect. According to the communication, the said A. P. Tinaikar is the Organising Secretary (Bangalore) of the Vijaya Bank Employees Union which is a body affiliated to All India Bank Employees' Association. That being so, the I Party has no subsisting interest in pursuing the reference and as such, the Reference may be rejected. Thereafter, the I Party has filed a Memo dated 28th November, 1970, admitting the averments made by the II Party in their further statement dated 29th September, 1970, and stated that the Issue is not pressed since the dispute does not survive.

9. In view of the above Memo filed by the I Party, there is no need to consider the impleading application filed by the Intervener, Sri H. Sudhakar Shetty, or the main matter on merits as the I Party has indicated in their Memo referred to above that the Issue is not pressed. That being so, the dispute involved in the Reference does not survive for adjudication and hence the reference has to be rejected.

10. In the circumstances aforesaid, I pass an Award rejecting the Reference. There will be no order as to costs.

(Sd.) NARAYAN RAI KUDDOOR,

Presiding Officer,
Industrial Tribunal Bangalore,
[No. F. 23/78/69/LRIII.]

New Delhi, the 21st April, 1971

S.O. 1834.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1277, dated the 24th March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification for Sl. No. 24 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
24.	Assistant Labour Commissioner (Central), Raipur.	The State of Madhya Pradesh."

[No. S. 11025/10/71-LRI.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1971

का० आ० 1834 — औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14)
की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के श्रम,

रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 1277 तारीख 24 मार्च, 1969 में निम्नलिखित संशोधन और करती है—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"24	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर।	म.प्र. प्रदेश राज्य।"

[सं. का. एस. 11025/10/71-एल. प्रार. 1]

S.O. 1835.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1971.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT DHANBAD.

In the matter of a Reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 47).

REFERENCE NO. 9 OF 1969

PARTIES:

Employers in relation to the Punjab National Bank Limited

AND

Their workmen.

PRESENT:

Shri A. C. Sen, Presiding Officer.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri A. Roy Choudhary, Staff Officer.

For the workmen—Shri C. L. Bhardwaj, General Secretary of the Union.

STATE: Bihar

INDUSTRY: Bank.

Dhanbad, dated, the 30th March, 1971.

AWARD

The Central Government by its Order No. 23/39/68-LRIII dated New Delhi, the 20th December, 1968 referred to the Central Government Industrial Tribunal, Delhi, the following dispute: "Whether the management of the Punjab National Bank Limited was justified in reverting Shri Kalika Prasad, working in the Jayanagar Pay Office of the Bank to the post of clerk with effect from the 22nd August 1967 after having allowed him to work as supervisor with effect from the 30th July, 1966. If not, to what relief is the workmen entitled?"

2. By Order No. 23/39/68-LRIII dated the 17th February, 1969 S.O. No. 813 the above dispute was transferred to this Tribunal, and the order of transfer was received in this Tribunal on the 17th March, 1969, whereupon it was registered as Reference No. 9 of 1969 in this Tribunal.

3. The written statement of the Bank was filed at Bombay on the 16th April, 1969. The written statement on behalf of the workmen appears to have been filed at Delhi before the Central Government Industrial Tribunal, Delhi on or about the 28th February, 1969.

4. In order to appreciate the nature of dispute it is necessary to state certain facts. Kalika Prasad, the workman concerned joined the service of the Bank as a clerk-cum-typist on 20th August, 1956 at the Jaynagar Branch, Jaynagar (vide Ext. M. 11). From 30th July, 1962 Rama Kanta Tewari, the permanent supervisor of the Pay Offices at Jaynagar, proceeded on medical leave and from the said date Kalika Prasad, the workman concerned, worked in his place as supervisor.

5. Rama Kanta Tewari, the permanent supervisor, died on 4th March, 1963 and Kalika Prasad, the workman concerned, continued to work as a supervisor in that vacancy. He worked as supervisor from 30th July, 1962 to 21st August, 1967, but from 22nd August, 1967 he has been working as a clerk.

6. The point for consideration is whether the Bank was justified in reverting the workman concerned to the post of clerk with effect from 22nd August, 1967 after having allowed him to work as supervisor with effect from 30th July, 1962. According to the Bank, the question of reversion cannot arise as Kalika Prasad was never promoted as a supervisor. It is for this reason that the Bank has taken the preliminary objection that the reference is bad in law and is liable to be dismissed in limine.

7. Let us see whether Kalika Prasad, the workman concerned, was at any time from 30th July, 1962 to 21st August, 1967 was promoted as a supervisor. The Bank's case is that he joined service of the Bank as a clerk-cum-typist on 20th August, 1956 and that he was allowed to work temporarily as supervisor (now called special assistant) in stop gap arrangements at Jaynagar from time to time on payment of special allowance as provided under the Bank Award, as he was the seniormost clerk at that office.

8. Ext. M. 101, being Staff Bulletin no. 31 of the Punjab National Bank dated 30th August, 1962 shows that at the Jaynagar Branch of the Bank Kalika Prasad, Clerk, worked as supervisor in the leave arrangement of R. K. Tewari from the 30th July, 1962 to the 28th August, 1962. This entry appears in serial no. 5 under the heading: "A" Temporary changes in staff comprising holders of P.A.'s & Specific Powers. Ext. M. 3 is the application by Rama Kanta Tewari for leave on the ground of illness from the 30th July, 1962 to the 28th August, 1962. Ext. M. 3(c) is an endorsement on that application to the effect that "Kalika Prasad will work in his place and the arrangement will be the same as on last Friday". There is another application for one day's leave by Rama Kanta Tiwari (Ext. M. 2) dated the 27th July, 1962. This application has been marked as Ext. M. 2. On this application of the 27th July, 1962 there is the following endorsement: "One day's C/L sanctioned:— Arrangement:— Shri Kalika Prasad. Duties of Tewari along with Despatch and Daily Extract." This endorsement has been marked as Ext. M. 2(a). These exhibits show that only a temporary arrangement was made on both the occasions when Tiwari took leave and according to that temporary arrangement Kalika Prasad was to work in the place of Tiwari. No distinction was made between a leave of one day and a leave of nearly one month in making the temporary arrangement.

9. The evidence on record shows that such temporary arrangements were made by the officer-in-charge of the Jaynagar Branch. For instance, office order no. 9/62 dated 5th June, 1962 in Ext. M. the order Book runs thus: "The undersigned, under instructions of the Parent Branch Manager, has handed over the charge of the office to Shri R. K. Tewari, and is proceeding to Darbhanga. With effect from tomorrow Shri R. K. Tiwari will work as Officer incharge and Shri Kalika Prasad as supervisor till further arrangements....." This order was passed by N. D. Gupta, Officer Incharge. The endorsements referred to in the next preceding paragraph were also made by N. D. Gupta. It is, therefore, clear that the concerned workman was allowed to work as supervisor in the place of R. K. Tiwari purely as a temporary measure. Ext. M. 100, being Bulletin no. 23 of the Bank, dated the 21st June, 1962 shows that R. K. Tewari, Supervisor and Kalika Prasad, Clerk, were working in the Jaynagar Branch as Officer Incharge and Supervisor respectively in place of Shri N. D. Gupta deputed to the Branch Office, Darbhanga from 5th June, 1962 to 24th June, 1962.

10. Ext. M. 101, being Bulletin no. 31 dated the 30th August, 1962 indicates that in the Jaynagar Branch Kalika Prasad, the concerned workman, worked as Supervisor in the leave arrangement of R. K. Tewari from 30th July, 1962 to 28th August, 1962. It transpires from Ext. M. 102, being Bulletin no. 33 of the Bank, dated the 17th October, 1962 that R. K. Tewari, Supervisor had been granted extension in leave on the existing arrangement upto 27th October, 1962. Kalika

Prasad, Clerk, was to work as Supervisor in leave arrangement of R. K. Tewari upto 31st March, 1963 (vide Ext. M. 103).

11. Ext. M. 104, being Bulletin no. 14 of the Bank dated 4th April, 1963 reveals an interesting thing. B. N. Sinha, Clerk, was to work in place of late R. K. Tewari, Supervisor, since expired from 25th March, 1963 to 17th April, 1963. Evidently Kalika Prasad did not work as supervisor from 25th March, 1963 till the 4th April, 1963 when Ext. M. 104 was issued. Hence workmen are not justified in saying, as they did in their written statement, that Kalika Prasad worked as a Supervisor from the 30th July, 1962 to the 21st August, 1967 without any break. From Ext. M. 105, being Bulletin no. 20, dated the 15th May, 1963 it appears that Kalika Prasad, Clerk was working as Supervisor with effect from 18th April, 1963. If Exts. M. 104 and M. 105 are read together it will be found that Kalika Prasad did not work as Supervisor from 25th March, 1963 to 17th April, 1963.

12. Exts. M. 37 to M. 41 are the Staff Statements of the Jaynagar Branch from October, 1962 to February 1963. R. K. Tiwari was alive during this period. All these Exhibits show that the substantive post of Kalika Prasad, the concerned workman, during this period was that of Clerk-cum-typist his officiating post was that of Supervisor and that he was officiating in the vacancy of R. K. Tiwari, Supervisor, who was on leave Exs. M. 12 to M. 36 are the Staff Statements of the Jaynagar Branch extending from September, 1963 to July, 1967; they also show that the substantive post of Kalika Prasad all these years was that of clerk-cum-typist and that he was holding the post of Supervisor in place of late R. K. Tiwari. All these office statements, Exts. M. 12 to M. 41 bear the signature of Kalika Prasad himself as Supervisor. All these exhibits show that the arrangement that was made during the leave vacancy of R. K. Tiwari continued without any change upto July, 1967. In other words from the 30th July, 1962 to July 1967 with a break from 25th March, 1963 to 17th April, 1963 he was officiating as the Supervisor of the Jaynagar Branch in the place of R. K. Tiwari, partly during the life time of Tiwari and partly after his death. Kalika Prasad too in his deposition admits that there is no arrangement recorded in the two registers, Exts. M. and M. 1, containing office orders of the Jaynagar Branch from 30th November, 1956 to 6th June, 1964 relating specifically to any arrangement for working as Supervisor in R. K. Tewari's place after the arrangement of 30th July, 1962.

13. Exhibits M. 43 to M. 54 are the leave applications of Kalika Prasad from 16th February, 1963 to 4th August, 1968. In all these applications for leave Kalika Prasad had described himself as clerk-cum-typist. He had, therefore, no illusion in his mind that he, during that period, held the substantive post of Supervisor. These Exhibits, M. 12 to M. 41 and M. 43 to M. 54, so also the Exts. 100 to 105 lend support to the contention of the management in their statement that Kalika Prasad continued to work temporarily as a Supervisor in the vacancy caused by the death of R. K. Tiwari, a permanent Supervisor, on 4th March, 1963.

14. It has been stated in preliminary objection no. (ii) in the reply of the Bank that in terms of clause 21 of the settlement dated 24th April, 1962 between the Bank and the All India Punjab National Bank Employees Association no clerk could be promoted as a supervisor permanently after 1st January, 1962 till the finalisation of the case of 338 Officers Grade II in respect of whom the aforesaid settlement dated 24th April, 1962 was arrived at. The workmen too in their statement of claim admit that the posting of Kalika Prasad was governed by clause 21 of settlement dated 24th April, 1962 and that his posting had to be treated as temporary till the finalisation of the Officers Grade II Dispute (O. Gr. II Dispute). The workmen further admit that as a result of the settlement dated 24th April, 1962 the O.G. II Dispute was finalised in December, 1965. The Bank too admits in its reply that the case of 338 O.G. II was finalised in December, 1965. Therefore it is the common case of the management and the workmen that Kalika Prasad was a temporary Supervisor till December, 1965.

15. It is also the common case of both the parties that the position of Kalika Prasad was governed by clause 21 of the settlement dated 24th April, 1962. The above settlement was brought about by the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi between the Bank and the two unions of the Bank employees under the following circumstances. The workmen of the Bank represented by two unions, namely the All India Bank Employees Association and the All India Punjab National Bank Employees Association alleged that the Management of the Bank had not properly implemented the judgment dated 6th December, 1960 of the Supreme Court of India on appeal against the award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi, dated 3rd October, 1958.

16. The case of the workman was that the Management should have set aside the promotion of 338 Officer Grade II employees and thereafter made a re-selection for these posts on the lines of para 529 of the Sastry Award. They also contended that the Management was not, entitled, as a result of Supreme Court Judgment, to make recoveries from or reduce the emolument of the employees to whom the Bank of its own accord had paid emoluments according to their own rules and scales.

17. The Management on the other hand contended that it had rightly implemented the judgment of the Supreme Court and had made proper re-selections and that it was within its rights to adjust the salaries of the staff concerned under the Award. It further contended that the Bank had paid arrears retrospectively where they were due and was likewise entitled to recover any sums due to it, and that reduction, where there was any, was a sequel to the judgment of the Supreme Court.

18. The Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, arranged a series of meetings between the parties. Elaborate discussions were held whereafter formal conciliation proceedings were initiated by him as a result of which the settlement dated 24th April, 1962 was arrived at Under clause 1 of the Memorandum of Settlement dated 24th April, 1962 the 338 employees promoted as Officers Grade II, during the period from 18th April, 1957 to 4th October, 1958 were to be reverted to their original positions i.e., the clerical positions and such reversions were to be enforced not later than 7th May, 1962. Under clause 2, those promoted supervisors or officers Grade II from 5th October, 1958 till 31st December, 1961 were not to be reverted. Clauses 5 to 20 of the Memorandum of Settlement laid down the manner in which the 338 vacancies were to be filled up.

19. Some interim arrangements were made to fill up the 338 vacancies pending finalisation of selection according to clauses 5 to 20. Clause 4 of the Memorandum of Settlement dealt with such interim arrangements. Sub-clause (a) of clause 4 provided that those having highest "priority marks" on 1st January, 1958 in the branch or office where vacancy would occur on account of the reversions of 338 Officers Grade II would be given officiating chances. Sub-clause (b) of clause 4 clearly laid down that officiating arrangements were only to be a stop-gap measure. Pending finalisation of selection in stages as detailed in clause 5 to 20 of the Memorandum of Agreement dated 24th April, 1962.

20. Clause 21 of the said Memorandum of Agreement reads as follows: "Promotions to the posts other than those caused by reversion of 338 O.G. IIs made or to be made by the Bank after 1st January, 1962 shall be regarded as temporary. After the conclusion of the final selection to be made as per clauses 5 to 20 above, the Bank will be free to make permanent promotions in place of the above temporary arrangements from amongst all the eligible clerks including those who failed to get promoted under the procedure as per the settlement."

21. In the Jaynagar Branch of the Bank the post of the Supervisor fell vacant on account of the death of the permanent supervisor, R. K. Tiwari on 4th March, 1963. Even if the Bank promoted the concerned workman, Kalika Prasad to the post of the Supervisor, the promotion would have been regarded by reason of clause 21 of the agreement dated 24th April, 1962 as temporary, and the Bank would have been, after the conclusion of the final selection to be made as per clauses 5 to 20 of the settlement dated 24th April, 1962, free to make permanent arrangements from amongst all the eligible clerks including those who failed to get promoted under the procedure as per the settlement Kalika Prasad could not have objected to the appointment on a permanent basis of some other person from among the eligible clerks. But in fact Kalika Prasad was not promoted, he was only allowed to officiate in the vacancy caused by the death of R. K. Tiwari, the permanent Supervisor of the Jaynagar Branch. His position cannot be better than what it would have been had he been promoted temporarily.

22. The Bank formulated rules for the promotion of clerks as supervisors on a permanent basis and also rules for allowing them to work temporarily in stop-gap arrangements and a staff Department Circular, being circular No. 561 dated 3rd March, 1964 was issued. There is no dispute between the parties that the aforesaid circular containing the rules for promotion etc. was circularised to all the offices of the Bank. In terms of the said Circular dated 3rd March, 1964 all supervisory vacancies had to be filled up on the basis of priority marks as on the 1st October, each year.

23. The rules relating to promotion of clerks as Supervisors were revised in accordance with an agreement dated 25th February, 1964 entered into between the

Bank and the All India Punjab National Bank Employees Federation. The terms of the agreement were circulated to all offices of the Bank by the aforesaid circular No. 561, dated 3rd March, 1964. Clause 3 of the Circular deals with the priority list. It provides as follows. A priority list shall be maintained region-wise on the basis of marks obtained under clauses (1) and (2) above as on the 1st October, each year and list of employees highest in the priority list numbering the three times the number of anticipated vacancies in each region shall be circulated to the branches in the respective regions. Clause 5 deals with promotion. Under that clause, an employee coming highest in the priority list and not assessed as "below average" shall be promoted subject to certain conditions, one of the conditions being that he has continuously served in clerical cadre for a minimum period of 7 years which period may be reduced suitably in regions where persons of this minimum service are not available. Clause 7 deals with officiating chances.

24. In paragraph 2(h) of the statement of claim filed by the workmen it has been stated that prior to the issuance of Bank's Circular No. 561, dated 3rd March, 1964, all temporary and/or permanent vacancies of Supervisors were filled up on the basis of items I, II and III of Bank's Circular no. 201 dated 8th August, 1956, and that in terms of the said circular after the sad demise of R. K. Tiwari the concerned workman was posted as officiating supervisor against the said permanent vacancy with effect from 30th July, 1962, but no specific period was conveyed to him against his signature that his posting was temporary for such and such specific period. The Circular No. 201, dated 8th August, 1956 is not on the record. It is not possible for me to say what were the provisions of items I, II and III of that circular. The workman concerned has said nothing in his deposition as to those provisions. Nor has he said that he was posted as officiating supervisor on the basis of items I, II and III of the Circular dated 8th August, 1956. R. K. Tiwari died on 4th March, 1963. There could not be any permanent vacancy in the post of the supervisor in the Jaynagar Branch before that date. Hence Kalika Prasad could not have been posted as an officiating Supervisor against any permanent vacancy before 4th March, 1963. The settlement dated 24th April, 1962 came into force long before Kalika Prasad was posted as an officiating supervisor against the permanent vacancy caused by the death of R. K. Tewari on 4th March, 1963. The settlement of 24th April, 1962 was followed by the settlement of 3rd March, 1964. Whatever might have been the provisions of items I, II and III of the Circular dated 8th August, 1956, Kalika Prasad's position as an officiating supervisor was governed by clause 21 of the settlement dated 24th April, 1962.

25. As a matter of fact Kalika Prasad was allowed to work temporarily as a supervisor with effect from the 30th July, 1962 in the leave vacancy of R. K. Tewari, the permanent supervisor, on whose death on 4th March, 1963 Kalika Prasad continued to work temporarily as a supervisor in the said vacancy. In his examination in chief he said so on this point: "I officiated for Ramakant Tewari when he went on one month's leave. The period of one month expired on 4th March, 1963. I continued to work as supervisor after the expiry of that period until 22nd August, 1967. No statement was taken from me after 30th August, 1962 that I would officiate as supervisor for such and such period."

26. No permanent arrangement could be made in view of clause 21 of the settlement dated 24th April, 1962. After the issuance of circular No. 561, dated 3rd March, 1964 he continued to work temporarily in terms thereof. The exhibits on record, discussed above, clearly show that he was fully aware of the continuance of this arrangement and that he was also aware that his substantive position during this officiating period was that of clerk-cum-typist. It is true that he was not told that his posting was temporary for such and such specific period. But as the arrangement was to continue until a permanent arrangement would be made as per settlements dated 24th April, 1962 and 3rd March, 1964 it was not possible to specify the period during which he was to officiate. In my opinion, nothing turns on that.

27. After the finalisation of the case of 338 O.G. II employees in terms of the settlement dated 24th April, 1962, a regional priority list as on 1st October, 1965 of clerks working in outside Calcutta offices in Eastern Circle was published in terms of the staff Department Circular No. 561 dated 3rd March, 1964 (Ext. M. 9). Kalika Prasad, the concerned workman having only 12 priority marks was holding the 60th position in the list though he being the senior most at Jaynagar office was allowed to officiate temporarily at this office as stated above. It is clear that he being very low in the regionwise priority list could not be selected for filling up on a permanent basis the vacancy in the post of supervisor caused by the death of R. K. Tiwari. H. R. Khurana of the Branch Office at Monghyr, holding the 18th position in the priority list with 15 priority marks was selected to fill up the

vacancy permanently at the Jaynagar Branch (Ext. M. 62). The relevant portion of Ext. M. 62, being a letter dated the 20th June, 1966 addressed to the Manager, B.O. Monghyr, runs thus: ".....it has been decided to post Shri Khurana as provisional supervisor at P.O. Jaynagar in a permanent vacancy..... You may, therefore, relieve him immediately with instruction to report to the officer Incharge P.O. Jaynagar"

28. Khurana, on receipt of promotion and transfer order approached the Bank for deferring his posting at Jaynagar Office on the ground of his wife's illness. His request was not granted and he was told that he would risk losing the chance of promotion if he did not accept the post (Ext. M. 73).

29. Since Khurana still expressed his inability to move on transfer on promotion from Monghyr to Jaynagar he was debarred from promotion and the next senior employee, Narain Prasad, also of the Monghyr Branch, was offered the post (Ext. M. 82). Narain Prasad also declined the offer (Ext. M. 85): He was also debarred from promotion.

30. Ultimately Khurana appealed to the management by a letter dated the 24th May, 1967 (Ext. M. 88) for re-consideration of his selection for Jaynagar and offered to proceed to that Station. His request was granted and orders were issued for the transfer of Khurana on promotion as Supervisor to Jaynagar (Ext. M. 92). He was relieved by the Monghyr Branch on the 19th July, 1967 (Ext. M. 93). Ext. M. 96 a memorandum dated 22nd August, 1967 shows that Khurana joined the Jaynagar Branch as special Assistant on 22nd August, 1967. He was told by a letter dated the 12th September, 1967 (Ext. M. 95) that he would be required to serve a period of probation for one year and that his work would be watched by the authorities before he would be allowed to continue as special Assistant i.e. Supervisor.

31. From what has been stated above it is clear that in filling up permanently the vacancy created by the death of R. K. Tiwari the Bank merely followed the procedure laid down in the settlement dated 24th April, 1962 and in the circular No. 561, dated 3rd March, 1964, and there is no dispute that both are applicable to the concerned workmen, Kalika Prasad. It has been shown above that Kalika Prasad had no illusion in his mind about his real status during the period in which he officiated as Supervisor. The management too was alive to the fact that the time for filling up the vacancy on a permanent basis was long over due and that Kalika Prasad was working as Supervisor only on the basis of a temporary arrangement. In this connection reference may be made to Ext. M. 71, being a letter dated the 22nd August, 1966 written by the Asstt. General Manager, Eastern Circle, Calcutta to the Manager of the Branch Office at Monghyr. The relevant portion of the letter runs thus: "Permanent vacancies of Supervisors at branches are to be filled up by approved clerical staff as per Head Office directions. We cannot leave the vacancy of Supervisor left unfilled for an indefinite period. You will appreciate that P.O. Jaynagar is without a permanent Supervisor since long. To fill up the vacancy, Shri Khurana....has been selected by us..... If he ultimately does not accept his promotion at Jaynagar some other person approved by Head Office shall have to be selected by us".

32. It has been stated in para 2(1) of the statement of claim by the workmen that the management filled up the undermentioned minimum permanent vacancies of Supervisors by eligible clerks of different offices in Behar: (a) 1964....at least 22 vacancies; (b) 1965.... at least 20 vacancies; (c) 1966.... at least 15 vacancies. In reply the Bank has categorically denied that the management filled up any permanent vacancy of Supervisors in 1964 or 1965. The workmen have not produced any evidence, either documentary or oral in support of their statement regarding permanent posting of Supervisors in 1964 and 1965. When it is remembered that the case of the 383 Officers. Grade II was finalised in December, 1965, it is highly improbable that any vacancy of a Supervisor was filled up permanently in 1964 and 1965 in disregard of clause 21 of the settlement dated 24th April, 1962.

33. It now remains to examine the validity of the contentions of the workmen as embodied in clauses (m) and (n) of para 2 of their statement of claim. Clause (m) is to the following effect: "That right from 30th July, 1962 to 22nd August, 1967 number of clerks were promoted as Supervisor in different offices of Bihar Pradesh but the management did not fill up the vacancy of Supervisor of B/O Jaynagar against which Shri Kalika Prasad was working continuously from 30th July, 1962, was simply because he had attained the status of permanent supervisor in view of his having officiated as such beyond one year and also because of the fact that Jaynagar being deficit area office management allowed the subject to

officiate as supervisor beyond one year and in view of Shri Prasad's working continuously for more than five years as Supervisor against a permanent sanctioned vacancy, he has attained the status of a permanent supervisor more so when while allowing him to work as Supervisor no specific period for which he had to officiate was conveyed to him." There is nothing on record to show that the management did not fill up the vacancy of Supervisor of B/O Jaynagar simply because Kalika Prasad had attained the status of permanent supervisor. He was never promoted to the rank of a supervisor, hence there cannot be any question of his becoming permanent automatically officiating under a temporary arrangement in that post for more than five years. After the death of R. K. Tiwari, there was no doubt a permanent vacancy, but it cannot be said that Kalika Prasad became permanent by officiating not as a promotee but under a temporary arrangement for more than five years against a permanent vacancy. There is no hard and fast rule as to how long a temporary arrangement may continue. A temporary arrangement does not cease to be temporary simply because it continues for more than five years. In the instant case no permanent arrangement could be made upto December, 1965 by reason of clause 21 of the settlement dated 24th April, 1962. Kalika Prasad was allowed to continue till the 21st August, 1967, because Khurana and Narain Prasad, who were selected one after another on the basis of the priority list, refused to accept the promotion, offered to them. Hence there was cogent reason why the vacancy at the Jaynagar Branch could not be filled up permanently before the 22nd August, 1967. In the circumstances of the case it cannot be said that Kalika Prasad became permanent in the usual course by being allowed to officiate for more than five years.

34. Clause (n) of para 2 of the statement of claim filed by the workmen reads as follows: "That in view of Kalika Prasad's having worked continuously as Supervisor for more than one year, in terms of Banks own Cir. No. 20 dated 20th October, 1952, Cir. No. 198 dated 28th July, 1956, A.G.M. Office Calcutta Circle No. 194 dated 5th May, 1967 read with Staff Dept. Circle No. 561 of 3rd March, 1964 Shri Kalika Prasad stood confirmed as supervisor as a result of which he was paid special Allowance which had become part of his basic pay, F/Fund of the Special Allowance which had become part of his service conditions and after more than five years enjoyed all these benefits which the management now cannot abruptly withdraw without any cogent reason in utter violation of the provisions of the I.D. Act." None of the circulars mentioned in this clause have been filed by the workmen, circular No. 20, dated 20th October, 1952 has, however, been filed by the management and has been marked as Ext. M. 8. There is nothing in Ext. M. 8 from which it can be said that Kalika Prasad stood confirmed as supervisor by reason of his having worked continuously for more than one year. Circular No. 198 dated 28th July, 1956 has not been filed by the management, nor was it called for from the management by the workmen. I am, therefore, not in a position to say to what extent, if at all, it supports the case of the workmen as made out in this clause. Circular No. 561 of 3rd March, 1964 is definitely against the case made out by the workmen. As to the Circular of 1967, it is not at all material for the purpose of deciding the issue involved in this case. The complaint of the workmen that the Bank has violated the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 by sending the concerned workman back to his substantive post as clerk is without foundation. Mr. Bhardwaj appearing on behalf of the workmen tried to convince me that the Bank was guilty of violating sec. 9A of the Act. But I confess that I remain unconvinced. Kalika Prasad used to get certain extra benefits while officiating as supervisor; if he goes back to his substantive post as clerk, he will naturally lose those benefits. That does not amount to a change in his service conditions. Besides, the question whether the order passed by the Bank for the reversion of the concerned workman to his substantive post as clerk is hit by sec. 9A of the Industrial Disputes Act is not within the scope of the reference and hence does not call for any answer. Moreover in this case the concerned workman has not been told anything as to the extra allowances and other benefits that he used to get during the officiating period. It is for this reason also it may be said that sec. 9A is not attracted.

35. From the above discussion the irresistible conclusion is that the management of the Bank was justified in sending him back to his substantive post as clerk with effect from the 22nd August, 1967. According to the Bank, as Kalika Prasad was never promoted either temporarily or on a permanent basis to the rank of a Supervisor, the question of reversion cannot arise at all. It therefore contends that the reference is liable to be dismissed in limine. I am not prepared to accept this preliminary objection for the simple reason that the word 'reverting' has been used in the reference not in the sense of demotion but in the sense of sending back to the previous post. Another preliminary objection on the ground that the dispute is merely individual was waived by the Bank on 7th August, 1969 in

course of argument before my predecessor-in-office. However, in view of my finding on merits, the preliminary objections have become redundant.

36. My award is as follows. The Punjab National Bank Limited was justified in reverting Shri Kalika Prasad to the post of clerk with effect from the 22nd August, 1967 after having allowed him to work as Supervisor with effect from the 30th July, 1962. He is, therefore, entitled to no relief from the Punjab National Bank Limited.

37. Let a copy of this award be sent to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) A. C. SEN,
Presiding Officer.

[No. 23/39/68-LR.III.]

ORDERS

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1836.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Ruby General Insurance Company Limited, Jaipur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Gopal Narain Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the termination of the employment of Shri Bhanwar Singh, Peon, Udaipur Branch of Ruby General Insurance Company, Limited as ordered by the Branch Manager, *vide* his letter dated the 9th December, was legal and justified? If not to what relief is the workman entitled.

[No. F. L.17012/3/71-L.R.I.]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1971

का० प्रा० 1836.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में रुबी जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जयपुर से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल नारायण शर्मा होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने तारीख 9 दिसम्बर, 1970 वाले पत्र में दिए गए आदेश के अनुसार रुबी जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड उदयपुर शाखा में चपरासी, श्री भंवर सिंह के नियोजन को समाप्त करना वैध और न्यायोचित था ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुसौध का हकदार है ?

[संख्या एल० 17012/3/71-एल० आर० 1]

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1837.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Air Force Academy Project Secunderabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed.

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (4) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Chandra-Sekhara Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the following demands of the workmen of the Air Force Academy Project, Dundigal, Secunderabad are justified and if so to what relief the workmen are entitled and from what date?

- (i) Payment of Project Allowance to the staff, who are not regular but engaged on work of permanent nature.
- (ii) Grant of continuity of service to workmen working in the project for long periods.
- (iii) Leave facilities such as privilege leave, sick leave and casual leave.
- (iv) Supply of Uniforms, shoes, soaps, goggles and caps for workers engaged in mixing cement and loading and unloading cement bags and those working on machines.

[No. F. 3/2/70-L.R.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

का० प्रा० 1837.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वायु सेना अकादमी प्रायोजना सिकन्दराबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है :

अनुसूची

"क्या वायु सेना अकादमी प्रायोजना, डुन्डीगल, सिकन्दराबाद के कर्मकारों की निम्नलिखित मांगें न्यायोचित हैं और यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?

- (1) उन कर्मचारी बृन्द को प्रायोजना भत्ते का संदाय करना जो नियमित नहीं हैं किन्तु स्थायी प्रकृति के कार्य में लगे हुए हैं :
- (2) लम्बी अवधि तक प्रायोजना में कार्य करने वाले कर्मकारों को सेवा की निरन्तरता प्रदान करना ।

- (3) छुट्टी सुविधाएँ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमारी की छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी ।
- (4) सिमेंट मिलाने और सिमेंट के बोरो को लाने और उतारने के काम में लगे कर्मचारों को और मशीनों पर कार्य करने वालों को वर्दी, जूते, साबुन, घूप के चश्मे और टोपी का प्रदाय ।

[सं० 3/2/70-एल० आर० 1]

एस० एस० सहस्रनामन, अधर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 19th April, 1971

S.O. 1838.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 372 dated the 22nd January, 1970 the Central Government having regard to the location of the Central Dairy, Nagpur Milk Scheme, Nagpur, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said dairy from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 1st January, 1972.

[No. 601(77)/70-HI.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1971

का० आ० 1838—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 372 तारीख 22 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार नागपुर दुग्ध स्कीम नागपुर की केन्द्रीय डेरी की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रथम जनवरी, 1972 तक जिसमें प्रथम जनवरी का दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है ।

[सं० फा० 601(74)/70 एच० आई०]

S.O. 1839.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 363 dated the 22nd January, 1970 the Central Government having regard to the location of the State Transport Maintenance Centre, Dhubri, belonging to the State Government of Assam in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 31st December, 1971.

[No. F. 601(76)/70-HI.]

का० आ० 1839—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 363 तारीख 22 जनवरी, 1970

के क्रम में केन्द्रीय सरकार असम राज्य सरकार के राज्य परिवहन अनुरक्षण केन्द्र, दुबरी की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति का ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ब्रह्णीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से 31 दिसम्बर, 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[संख्या फा० 601(76)/70-एच० आई०]

S.O. 1840.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 814 dated the 23rd February, 1970, the Central Government having regard to the location of the Hanger No. 6, Juhu Airport, maintenance section of the Department of Aviation, Bombay in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 30th January, 1971 upto and inclusive of the 29th January, 1972.

[No. F. 601/81/70-HI.]

फा० आ० 1840—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 814 तारीख 23 फरवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार हैंगर सं० 6, जूहू एयर पोर्ट विमानन विभाग, मुम्बई के अनुरक्षण अनुभू ग अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ब्रह्णीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 30 जनवरी, 1971 से 29 जनवरी, 1972 तक जिसमें 29 जनवरी, का दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[संख्या फा० 601(81)/70-एच० आई०]

S. O. 1841.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Electrical and Mechanical Workshop, Madras Airport, Madras, under the control of the Ministry of Tourism and Civil Aviation, Government of India are otherwise in receipt of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948, (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 809 dated the 20th February, 1970 the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from all the provisions of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st February, 1971 upto and inclusive of the 31st January, 1972.

[No. F. 601(83)/70-HI.]

फा० आ० 1841—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन विद्युत और यांत्रिक कर्मशाला, मद्रास हवाई अड्डा, मद्रास के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित फायदों के सारतः समान प्रसुविधाय अन्यथा प्राप्त हैं ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० फा० आ० 809 तारीख 20 फरवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम

से परामर्श करने के पश्चात् ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से प्रथम फरवरी, 1971 से 31 जनवरी, 1972 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 601(83)/70 एच० आई०]

S.O. 1842.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Hindusthan Cables Limited, Rupnarayanpore, District Burdwan, West Bengal, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factory from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification.

[No. 601 (77)/70-HI.]

का० आ० 1842—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से इस अधिसूचना के प्रकाशन की ता० से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 602(23)/70 एच० आई०]

S.O. 1843.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 290 dated the 16th January, 1970 the Central Government having regard to the location of the factories, namely, Machine Shop-cum-Tool Room, Calcutta-2 and the Chorme Tanning Extension Centre Calcutta-46 in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factories from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 31st December, 1971.

[No. 601(77)/70-HI.]

का० आ० 1843—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 299 तारीख 16 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार मशीन कर्मशाला एवं औजार कक्ष, कलकत्ता-2 और फ्राम ट्रेनिंग एक्सटेंशन सेन्टर कलकत्ता-46 नामक कारखानों की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से 31 दिसम्बर, 1971 तक और उस दिन को भी सम्मिलित करते हुए, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 601(77)/70 एच० आई०]

S.O. 1844.—Whereas the Central Government was satisfied that (1) M/s. A. G. Mujawar and Co. (Stone crushing), (2) Mechanical sub-Division Maharashtra State Government were situated in Shirol and Koynanagar areas which were sparse areas (that is, areas whose insurable population was less than 500) in the districts of Kolhapur and North Satara in the State of Maharashtra;

And, whereas by virtue of their location in the sparse areas, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in those areas

by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 3447, dated the 16th September, 1964:

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Shirol and Koynanagar areas in the districts of Kolhapur and North Satara in the State of Maharashtra has now exceeded 500, and these are no longer sparse areas:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification:—

- (1) against Sl. No. 2 the entry "Shirol" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted;
- (2) against Sl. No. 4 the entry "Koynanagar" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted;

[No. F. 603(7)/70-HL.]

का० आ० 1844.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मेसर्स ए० जी० मजावर एण्ड कम्पनी (स्टोन क्रशिंग), (2) मेकेनिकल सब डिजीवन महाराष्ट्र राज्य सरकार, शिरोल और कोयनानगर क्षेत्रों में स्थित थे जो महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और उत्तर सतारा जिलों में बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र (अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिनकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) थे ;

और यतः, उनकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्रों में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त कारखानों को, भारत सरकार के भूतपूर्व समाज सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 3447 तारीख 16 सितम्बर 1964 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और उत्तर सतारा जिलों में शिरोल और कोयनानगर क्षेत्रों की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र नहीं हैं ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

- (1) क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ 3 में "शिरोल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ।
- (2) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ 3 में "कोयनानगर" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ;

[संख्या फा० 603(7)/70 एच० आई०]

S.O. 1845.—Whereas the Central Government was satisfied that (1) M/s. Eagle Stone Crusher Works, (2) M/s. Patel Engineering Co. Limited were situated in Shirol and Koynanagar areas which were sparse areas (that is, areas whose insurable population was less than 500) in the districts of Kolhapur and North Satara in the State of Maharashtra;

And, whereas by virtue of their location in the sparse areas, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in those areas by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 895, dated the 4th March, 1964;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Shirol and Koynanagar areas in the districts of Kolhapur and North Satara in the State of Maharashtra has now exceeded 500, and these are no longer sparse areas;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification:—

- (1) against Sl. No. 4 the entry "Shirol" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted;
- (2) against Sl. No. 6 the entry "Koynanagar" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted;

[No. F. 603(7)/70-HI.]

क्र० अ० 1845.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसर्स ईगल स्टोन क्रशर वर्क्स (2) मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, शिरोल और कोयनानगर क्षेत्रों में स्थित थे जो महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और उत्तर सतारा जिलों में बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र (अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिनकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) थे ;

और यतः, उनकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्रों में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त कारखानों को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० अ० 895 तारीख 4 मार्च, 1964 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर और उत्तर सतारा जिलों में शिरोल और कोयनानगर क्षेत्रों की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वे अब बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र नहीं हैं ;

अतः, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

- (i) क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ 3 में "शिरोल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ii) क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ 3 में "कोयनानगर" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 के तत्स्थानी प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ।

[संख्या फा० 603(7)/70-एच० आई०]

S.O. 1846.—Whereas the Central Government was satisfied that M/s. Deepak Tiles and Industries Private Limited, (i) M/s. Shantinath Cement Concrete Works; (ii) M/s. The Kolhapur Steel Limited were situated in Panvel and Shirol areas which were sparse areas (that is, areas whose insurable population was less than 500) in the districts of Kolaba and Kolhapur in the State of Maharashtra;

And, whereas by virtue of their location in the sparse areas, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in those areas by the Central Government in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2407, dated the 27th June, 1968:

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Panvel and Shirol areas in the districts of Kolaba and Kolhapur in the State of Maharashtra has now exceeded 500, and these are no longer sparse areas:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification:—

- (1) against Sl. No. 4 the entry "Panvel" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted;
- (2) against Sl. No. 5 the entry "Shirol" in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(7)/70-HL.]

का० आ० 1846.—यत् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि मैसर्स दीपक इंडस्ट्रिज एंड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, (i) मैसर्स शान्तिनाथ सिमेंट कंक्रीट वर्क्स, (ii) मैसर्स दि कोल्हापुर स्टील लिमिटेड पांवेल् और शिरोल् क्षेत्रों में स्थित थे जो महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा और कोल्हापुर जिलों में बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र (अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिनकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) थे ;

और यतः उनकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्रों में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखानों को, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2407 तारीख 27 जून, 1968 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा और कोल्हापुर जिलों में पांवेल् और शिरोल् क्षेत्रों की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वे अब बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र नहीं हैं ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे संशोधन निम्नलिखित करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

- (i) क्रम संख्या 4 के सामने स्तम्भ 3 में "पांवेल्" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ii) क्रम संख्या 5 के सामने स्तम्भ 3 में "शिरोल्" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

[संख्या फा० 603(7)/70 एच० आई०]

S.O. 1847.—Whereas the Central Government was satisfied that—

- (1) M/s. Dhoot Papeswar Press,
- (2) M/s. Dhoot Papeswar Panvel Limited,
- (3) M/s. S. T. Panvel Depot,

M/s. Rayalgaon Sugar Farm Limited, were situated in Panvel and Rayalgaon areas which were sparse areas (that is, areas whose insurable population was less than 500) in the districts of Kolaba and Nasik in the State of Maharashtra;

And, whereas by virtue of their location in the sparse areas, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of

1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in those areas by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2665, dated the 2nd November, 1961;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Panvel and Ravalgaon areas in the districts of Kolaba and Nasik in the State of Maharashtra has now exceeded 500, and these are no longer sparse areas;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification:—

- (1) against Sl. No. 10 the entry "Panvel" in column 4 and the corresponding entries in column 5 shall be omitted.
- (2) against Sl. No. 13 the entry "Ravalgaon" in column 4 and the corresponding entry in column 5 shall be omitted.

[No. F. 603(7)/70-HI.]

का० प्रा० 1847.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसर्स धृत पापेश्वर प्रेस (2) मैसर्स धृत पापेश्वर पांवल लिमिटेड (3) मैसर्स एस० टी० पांवल डीपो, मैसर्स रावलगांव शूगर फार्म लिमिटेड, पांवल और रावलगांव क्षेत्रों में स्थित थे जो महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा और नासिक जिलों में बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र (अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिनकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) थे ;

और, यतः उनकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्रों में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखानों को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2665 तारीख 2 नवम्बर, 1961 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अधिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का : ह समाधान हो गया है कि महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा और नासिक जिलों में पांवल और रावलगांव क्षेत्रों की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वे अब बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र नहीं हैं ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 4 में, —

- (1) क्रम संख्या 10 के सामने स्तम्भ 4 में "पांवल" प्रविष्टि और स्तम्भ 5 में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।
- (2) क्रम संख्या 13 के सामने स्तम्भ 4 में "रावलगांव" प्रविष्टि और स्तम्भ 5 में तत्स्थानी प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा ।

[संख्या का० 603(7)/70 एच० आई०]

S.O. 1848.—Whereas the Central Government was satisfied that M/s. Jenson and Nicholson (India) Limited was situated in Panvel area which was a spare area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Kolaba in the State of Maharashtra;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the said Act in that area by the

Central Government in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2975, dated the 30th September, 1966;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Panval area in the district of Kolaba in the State of Maharashtra has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against Sl. No. 1 the entry "Panvel" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(7)/70-HL.]

का० आ० 1848.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि मैसर्स जेनसोन एण्ड निकलसन (इंडिया) लिमिटेड, पावेल क्षेत्र में स्थित था जो महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा जिले में बिलखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और यतः उसकी बिलखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2975 तारीख 30 सितम्बर, 1966 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ।

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा जिले में पावेल क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिलखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है,

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 3 में "पावेल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि का खोप कर दिया जाएगा ।

[संख्या फा० 603(7)/70 एच० आई०]

S.O. 1849.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 156 dated the 16th December, 1970, published at pages 232-233 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 9th January, 1971 at page 233 at Serial No. 9 in column 3 insert "Jamalpur Kalan Srinagar" below Behalgarh against Messrs Laxmi Glue Manufacturing Company in column 4.

[No. 602/7/70-HI.]

का० आ० 1849—भारत के राजपत्र, तारीख 9 जनवरी, 1971 भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 233-234 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 156 तारीख 16 दिसम्बर, 1970 में पृष्ठ 234 पर क्रम संख्या 9 पर स्तम्भ 3 में बल्लभगढ़ के नीचे मैसर्स लक्ष्मी ग्लू फैब्रिकेशन कम्पनी, जो स्तम्भ 4 में है, के सामने "जमालपुर कलान श्रीनगर" अन्तःस्थापित करें ।

[संख्या फा० 602(7)/70 : एच० आई०]

New Delhi, the 20th April, 1971

S.O. 1850.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Campbell Electronics, Prabhadevi Industrial Estate, 2nd Floor, Cadell Road, Bombay-25 DD have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1970.

[No. 8/181/70-PF. II(i).]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1971

का० ग्रा० 1850—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स केम्पबेल इलेक्ट्रोनिक्स, प्रभादेवी इण्डस्ट्रीयल स्टेट, दूसरी मंजिल केडल रोड, मुम्बई-25 डी डी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधि सूचना 1970 के मार्च के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8/181/70-पी० एफ० 2 (i)]

S.O. 1851.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st March, 1970, the establishment known as Messrs Campbell Electronics, Prabhadevi Industrial Estate, 2nd Floor, Cadell Road, Bombay-25 DD for the purposes of said proviso.

[No. 8/181/68-PF. II (ii).]

का० ग्रा० 1851.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मेसर्स केम्पबेल इलेक्ट्रोनिक्स, प्रभादेवी इण्डस्ट्रीयल, एस्टेट, दूसरी मंजिल केडल रोड, मुम्बई-25 डी डी नामक स्थापन को 31 मार्च, 1970 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[संख्या 8/181/68-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 1852.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 22 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby appoints the Regional Provident Fund Commissioner, Assam, as the Secretary of the Regional Committee for the State of Assam set up under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3617 dated the 27th October, 1970 published in Part II, Section 3 (ii) of the Gazette of India dated the 7th November, 1970.

[No. 10(3)/59-PF. II.]

का० ग्रा० 1852.—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 22 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, असम को भारत के राजपत्र तारीख 7 नवम्बर, 1970 भाग 2, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित भारत

सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3617 तारीख 27 अक्टूबर 1970 के अन्तर्गत स्थापित असम राज्य के लिए प्रादेशिक समिति का सचिव नियुक्त करती है।

[सं० 10 (3)/59-पी० एफ०-2]

S.O. 1853.—Whereas it appear to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs True-graph Charts, 7/C Pitamber Lane, behind Paradise Cinema, Mahim, Bombay-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government, hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1970.

[No. 8/187/70-PF. II (I).]

का० प्रा० 1853.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स ट्रुग्राफ चार्टस, 7/ सी, पिताम्बर लेन, पैराडाइज सिनेमा के पीछे माहिम, मुम्बई-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की जनवरी के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8 /187/70-पी० एफ०-2(i)]

S.O. 1854.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st January, 1970 the establishment known as Messrs Truegraph Charts, 7/C Pitamber Lane, Behind Paradise Cinema, Mahim, Bombay-16 for the purposes of the said proviso.

[No. 8/187/70-PF. II (ii).]

का० प्रा० 1854.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मेसर्स ट्रुग्राफ चार्टस 7/सी पिताम्बर लेन, पैराडाइज सिनेमा के पीछे माहिम, मुम्बई-16 नामक स्थापन को 31 जनवरी, 1970 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनीर्दिष्ट करती है।

[सं० 8/187/68-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 1855.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaysu Fabrics, Hiralal Colony, Ashwini Kumar Road, Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1969.

[No. 8(243)/70-PF. II.]

क्रा० प्रा० 1855.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स बीयेम्स (रजिस्टर्ड) इंजीनियर्स एंड कन्ट्रक्टर्स, पोस्ट बाक्स संख्या 818, पल्लुरथी, कोचीन-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के सितम्बर, के तीसरे दिन को प्रदत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/243/70-पी० एफ० -2]

S.O. 1856.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of employees in relation to the establishment known as Messrs Beeyems (Registered) Engineers and Contractors, Post Box No. 818, Palluruthy, Cochin-5 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment, with effect from the twenty-eight day of February, 1971.

[No. 8/156/70-PF. II (1).]

क्रा० प्रा० 1856.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स बीयेम्स (रजिस्टर्ड) इंजीनियर्स एंड कन्ट्रक्टर्स, पोस्ट बाक्स संख्या 818 पल्लुरथी, कोचीन-5 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्वारा अध्यादेश फरवरी, 1971 से लागू करती है।

[सं० 8/156/70-पी० एफ० 2(1)]

S.O. 1857.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 28th February, 1971 the establishment, known as Messrs Beeyems (Registered) Engineers and Contractors, Post Box No. 818, Palluruthy, Cochin-5 for the purposes of the said proviso.

[No. 8/156/70-PF. II (II).]

क्रा० प्रा० 1857.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मेसर्स बीयेम्स (रजिस्टर्ड) इंजीनियर्स एंड कन्ट्रक्टर्स पोस्ट बाक्स संख्या 818 पल्लुरथी, कोचीन नामक स्थापन को अध्यादेश फरवरी, 1971 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 8/156/70-पी० एफ० 2(II)]

S.O. 1858.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and all the employees in relation to the establishment known as Messrs Mazumdar and Associates, 76, Hazra Road, Calcutta-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment, with effect from the twentyeighth day of February, 1971.

[No. 8/120/70-PF. II.]

का० आ० 1858.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मजूमदार एंड एसोसिएट्स, 76 हजरा रोड, कलकत्ता-29 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और सभी कर्मचारी इस बात पर सहमत हो गये हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा 1971 की फरवरी के अठ्ठाईसवें दिन से लागू करती है।

[सं० 8/120/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1859.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Periyar Chemicals Limited, Edayar, (via) Udyogamandal, Alwaye Taluk, Kerala have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirtieth day of April, 1971.

[No. 8(293)/70-PF. II (1).]

का० आ० 1859 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स पेरियर केमिकल्स लिमिटेड एडयार (द्वारा) उद्योग मंडल अलवाय तालुक, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त होगी।

[सं० 8/(293)/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1860.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 1 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th April 1971 the establishment known as Messrs. Periyar Chemicals Limited, Edayar, (Via) Udyogamandal, Alwaye Taluk, Kerala for the purposes of the said proviso.

[No. 8(293)/70-PF.II-(ii).]

का० आ० 1860.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आशयक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्द्वारा मेसर्स पेरियर केमिकल्स लिमिटेड एडयार (द्वारा) उद्योग मंडल अलवाय तालुक, केरल नामक स्थापन को 30 अप्रैल, 1971 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० 8/293/70-पी० एफ० 2(11)]

S.O. 1861.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nagabushanam Industries, HMT, Industrial Estate, Bangalore-31 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1970.

[No. 8(206)/70-PF. II.]

का० प्रा० 1861.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नगबुशानम इण्डस्ट्रीज, एच० एम० टी० इण्डस्ट्रीज एस्टेट, बंगलूर-31 नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/206/70-पी० एफ० -2]

S.O. 1862.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Diamond Trading Company, 200/F, Tiruchedur Road, P.B. No. 6, Palayam Kotal, Tirunelveli-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1970.

[No. 8/162/70-PF. II.]

का० प्रा० 1862.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दी डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी, 200/एफ० तिरुदूर रोड, पोस्ट बाक्स नं० 6 पलायामकोट्टे, तिरुनलवेली-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के अप्रैल, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/164/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1863.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the Majority of the employees in relation to the establishment known as the Ramavarma Theatre, Swaraj Round East, Trichur-1 (Kerala State) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 28th February, 1971.

[No. 8/174/70-PF. II.]

का० प्रा० 1863.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामा र्भा थियेटर, स्वराज रोड ईस्ट, त्रिचूर-1 (केरल राज्य) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म-चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा 28 फरवरी, 1971 से लागू करती है।

[संख्या 8/174/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1864.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Koneti Sree Ramulu and Son, Kalahasti (Andhra Pradesh) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the first day of July, 1970.

[No. 8/177/70-PF. II.]

का० प्रा० 1864.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोनेती श्री रामूलु एण्ड सन्स, कलाहस्ती (आंध्र प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

[संख्या 8/177/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1865.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and all the employees in relation to the establishment known as Messrs Fine Chem Marketing Private Limited, 527 Arun Chambers, Tardeo Road, Bombay-34 and its branch at Indore have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1970.

[No. 8/198/70-PF. II.]

का० प्रा० 1865.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फाइन केम मार्केटिंग प्राइवेट लि०, 527, अरुण चेम्बर्स तारदेव रोड, मुम्बई, 34 नामक स्थापन तथा इन्दौर में इसकी शाखा से सम्बद्ध नियोजक और सभी कर्मचारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के मार्च के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/198/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1866.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Doshi Metal Industries, 3, Jawahar Road, Udyognagar, Udhna, District Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment, with effect from the 26th February, 1971.

[No. 2/151/70-PF. II.]

का० आ० 1866.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स डॉशी मेटल इंडस्ट्रीज 3 जवाहर रोड, उद्योग नगर, उधना, जिला सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्य इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किय जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा अट्ठाईस फरवरी, 1971 से लागू करती है।

[सं० 8 (151)/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1867.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby appoints Sarvashri D. N. Kaila, N. K. Verma, H. S. Shukla and S. C. Hajela as Inspectors for the purposes of the Coal Mines Provident Fund Scheme, Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, Coal Mines Bonus Scheme, Andhra Pradesh Coal Mines Bonus Scheme, Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme and Assam Coal Mines Scheme and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2057, dated the 28th May, 1970, namely:—

In the said notification—

(i) for items 10 and 11, the following items shall respectively be substituted, namely:—

- "10. Shri D. N. Kaila—Senior Finance Officer, Coal Mines Provident Fund.
- 11. Shri N. K. Verma—Administrative Officer, Coal Mines Provident Fund."

(ii) after item 27, the following items shall be added, namely:—

- "28. Shri H. S. Shukla—Assistant Finance Officer, Coal Mines Provident Fund.
- 29. Shri S. C. Hajela—Coal Mines Provident Fund Inspector."

[No. 2(350)/63-PF. I.]

का० आ० 1867.—कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम 1948 (1948 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सर्वश्री डी० एन० कालिया, एन० के० वर्मा, एच० एस० शुक्ल और एस० सी० हजेल को कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, नेवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, कोयला खान बोनस स्कीम, आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम, राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम और असम कोयला खान बोनस स्कीम, के प्रयोजनों के लिये निरीक्षक नियुक्त करती है और भारत सरकार के श्रम

रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिवृचना संख्या का० आ० 2057 तारीख 28 मई 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिवृचना में—

(i) मद 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमशः प्रतिस्थापित की जायेंगी अर्थात्—

10. 'श्री डी० एन० कालिया—ज्येष्ठ वित्त अधिकारी कोयला खान भविष्य निधि ।

11. श्री एन० के० वर्मा—प्रशासन अधिकारी कोयला खान भविष्य निधि

(ii) मद 27 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जायेंगी अर्थात् :—

'28. श्री एन० एन० शुक्ल—सहायक वित्त अधिकारी कोयला खान भविष्य निधि ।

29. श्री एस० सी० हजेला—कोयला खान भविष्य निधि निरीक्षक ।'

[सं० 2 (350)/63-पी०एफ०-1]

S.O. 1868.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Precision Rubber Company (India), Manok Road, Falghar, District Thana, including its office at Borivli West (Post Box No. 7718), Bombay-92 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1948), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1969.

[No. 8/13/70-PF. II.]

का० आ० 1868.—इतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स प्रिस्सीजन रबर कम्पनी (इंडिया) मेनोर रोड पालघर, जिला थाना नामक स्थापन, जिसमें सका बोरिवली वेस्ट (पोस्ट बाक्स सं० 7718) मुम्बई-92 का कार्यालय सम्मिलित है। से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) परा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिवृचना 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/13/70-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1869.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and all the employees in relation to the establishment known as Messrs Coronation Plastic Industrials, Banerji Road, Ernakulam, Cochin-18 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment, with effect from the twenty-eight day of February, 1971.

[No. 8/138/70-PF. II.]

नदिर्ला, 21 अप्रैल, 1971

का० आ० 1869.—इतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स कारोनेशन लास्टिक इंडस्ट्रियल्स, बनर्जी रोड एर्नाकुलम, कोचीन, 18 नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और सभी

कर्मचारी इस बात पर सहमत हो गये हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा 1971 की फरवरी के अठारहवें दिन से लागू करती है।

[सं० 8/116/68-पी० एफ०-2]

S.O. 1870.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Babsan and Company, Hirji Govindji Estate, Thokersey Jivraj Road, Sewri, Bombay-15 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1970.

[No. 8(247)/70-PF. II.]

क्र० प्र० 1870.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स बाबसन एण्ड कम्पनी, हीरजी गोविन्दजी एस्टेट थोकरसे जीवराजरोड; सेवरी मुम्बई-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के फरवरी के अठारहवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/247/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1871.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajnikant Textile, Hiralal Colony, Ashwini Kumar Road, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1969.

[No. 8(244)/70-PF. II.]

क्र० प्र० 1871.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स रजनीकान्त टेक्स्टाइल्स, हीरालाल कालानी, अश्वनी कुमार रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है, कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 के सितम्बर, के 30 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8/244/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1872.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the Employees in relation to the establishment known as Messrs Padinjarekara Agencies (Private) Limited, Kottayam Latex Factory, Post Box, No. 22 Kottayam-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall come into force on the thirtieth day of April, 1971.

[No. S. 35019(5)/71-PF. II(I).]

का० आ० 1872.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स पडिन्जेकरा एजन्सोज (प्राइवेट) लिमिटेड, कोट्टायम लेटेक्स फैक्टरी, पोस्ट बॉक्स सं० 22, कोट्टायम-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1971 के अप्रैल, के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019 (5)/71-पी० एफ०-2]

S.O. 1873.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th April, 1971 the establishment known as Messrs The Padinjarekara Agencies Private Limited, Kottayam Latex Factory, Post Box No. 22, Kottayam-1 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(5)/71-PF. II(ii).]

का० आ० 1873.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एतद्द्वारा मेसर्स दि पडिन्जेकरा एजन्सोज, (प्राइवेट) लिमिटेड, कोट्टायम लेटेक्स फैक्टरी, पोस्ट बॉक्स सं० 22, कोट्टायम-1, नामक स्थापन को 30 अप्रैल, 1971 से उक्त परन्तु के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस० 35019 (5)/71-पी० एफ० 2 (II)]

S.O. 1874.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. B. Engineering Works, 8 Green Street, Near Green House, Fort, Bombay-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1970.

[No. 8(255)/70-PF.II.]

का० प्रा० १८७४.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स एस० बी० ई० जे० नियोर्गिस वर्क्स ; ८ ग्रीन स्ट्रीट, ग्रीन हाउस के समीप, फोर्ट, मुम्बई-१, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना १९७० के मई मास के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० ८/२५५/७०-पो० एफ०-२]

S.O. 1875.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Novelty, Post Office Tezpur, District Darrong (Assam) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1970.

[No. 8(273)/70-PF.II.]

का० प्रा० १८७५.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स दि नावल्टी, डाकघर तेजपुर, जिला दर्रोंग (असम) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना १९७० के अगस्त, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या ८ (२७३)/७०—पो० एफ० २]

S.O. 1876.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Automatic Steel Products, 168, C.S.T. Road, Swastick Industrial Estate, Kalina, Maharashtra State have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1970

[No. 8(259)/70-PF.II.]

का० प्रा० 1876.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स आटोमेटिक स्टील प्रोडक्ट्स, 168, सी० एस० टी० रोड, स्वस्तिक एण्डस्ट्रीयल एस्टेट, कालिनी, महाराष्ट्र राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1970 के अप्रैल, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० 8 (259)/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1877.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nimesh Textiles, Hiralal Colony, Ashwinl Kumar Road, Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1969.

[No. 8(245)/70-PF.II.]

का० प्रा० 1877.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स निमेश टेक्सटाइल्स, हीरालाल कॉलोनी, अश्वनी कुमार रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1969 के सितम्बर के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० 8(245)/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1878.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Uganda Service Station, 44 Rafi Ahmed Kidwai Road, Wadala, Bombay-31 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1970.

[No. 8(248)/70-PF.II.]

का० 1878.—प्रा० यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स यूगाण्डा सर्विस स्टेशन, 44 रफी अहमद क़िदवाई रोड, वडाला, मुम्बई-31, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की मई के 31वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/248/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1879.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Bandra People's Co-operative Bank Limited, Samant's New Building, National Library Road, Bandra, Bombay-50 including its branch at MIG Colony, Bandra East, Bombay-51 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment, with effect from the twenty-eighth day of February, 1971.

[No. 8/144/70-PF.II.]

का० आ० 1879.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दि बान्द्रा पिपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सामन्तस न्यू बिल्डिंग, नेशनल लाइब्रेरी रोड, बान्द्रा, मुम्बई-50 नामक स्थापन, जिसमें इसको एम आई जी कालोनी, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई-51 की शाखा सम्मिलित है, से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा 1971 की फरवरी के अठ्ठाईसवें दिन से लागू करती है।

[संख्या 8/144/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1880.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and all the employees in relation to the establishment known as Messrs Mukesh Textiles, Court House, 4th Floor, Tilak Marg, Dhobi Talao, Bombay-2 (BR) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1970.

[No. 8/1888/70-PF.II(i).]

का० आ० 1880.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुकेश टक्साइल्स कोर्ट हाउस, चौथी मंजिल तिलक मार्ग, धोबी तलाब मुम्बई-2 (बी० आर०) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और सभी कर्मचारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/188/70-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 1881.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st January, 1970 the establishment known as Messrs Mukesh Textiles, Court House, 4th Floor, Tilak Marg, Dhobi Talao, Bombay-2(BR) for the purposes of the said proviso.

[No. 8/188/70-PF. II(ii).]

का० आ० 1881.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर लेने के पश्चात् एतद्वारा मैसर्स मुकेश टेक्स्टाइल्स, कोर्ट हाउस, चौथी मंजिल तिलक मार्ग, धोबी तलाब, मुम्बई-2 (बी० आर०) नामक स्थापन को 1 जनवरी, 1970 से उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[संख्या 8/188/70-पी० एफ० 2(II)]

S.O. 1882.—Whereas it appears to the Central Government that employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nigo's Corporation, Patel Compound, 48-B, Lamington Road, (North), near Nair Hospital, Bombay-8 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1969.

[No. 8(249)/70-PF.II.]

का० आ० 1882.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निगोज कारपोरेशन, पटल कम्पाउण्ड 48-बी, लैमिंगटन रोड (नार्थ), नायर अस्पताल के समीप, मुम्बई-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 की अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/249/70-पी० एफ०-2]

S.O. 1883.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Pradeep Textiles, Hiralal Colony, Ashwini Kumar Road, Surat have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September 1969.

[No. 8(258)/70-PF.II.]

का० आ० 1883.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रदीप टेक्स्टाइल्स, हीरालाल कोलोनी अश्विनी कुमार रोड, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के सितम्बर, के 30 वें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/258/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1884.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sagar Soap Mills, 6-Rameshwar Nagar (Azad Pur) Delhi-33 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1969.

[No. 8(280)/70-PF.II.]

क्र० प्र० 1884.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सागर सोप मिल्स, 6-रामेश्वर नगर (आजादपुर), दिल्ली-33 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1969 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/260/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1885.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madura Aluminium Company 70 East Marret Street, Madurai have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1970.

[No. 8/149/70/PF.II.]

क्र० प्र० 1885.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मयुरा एल्युमिनियम कम्पनी, 70, ईस्ट मैरिट स्ट्रीट, मयुराई नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1970 के फरवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या 8/149/70-पी० एफ० 2]

S.O. 1886.—Whereas it appears to the Central Government that the Employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Paragor Agencies, Shri Ram Industrial Estate, II Floor Block No. A/30, G.D.

Ambedkar Road, Wadala, Bombay-31. DD. have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1968.

[No. 8/90/69/PF. II.]

क्र० आ० 1886—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पैरागोन एजेंसीज, श्री राम इंडस्ट्रीज एन्डेट, दूसरी मंजिल, खण्ड सं० ए/30, जी० डी० ग्रम्बेडकर रोड वडाला, मम्बई-31 डी० डी० नामक स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952:19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1968 के दिसम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[संख्या 8/90/69-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1887.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4182 dated the 13th November, 1968, the Central Government hereby exempts the National Instruments Limited, Calcutta, from all the provisions of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 13th day of November, 1969.

[No. F. 601(34)/70-HI.]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

क्र० आ० 1887.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या क्र० आ० 4182 तारीख 13 नवम्बर 1968 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नेशनल इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता को उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति की तारीख से और आगे एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से छूट देती है :

[सं० एफ० 60/(34)/70—एच० आई०.]

New Delhi, the 28th April 1971

S.O. 1888.—Whereas the Central Government was satisfied that

(1) Messrs American Industries

(2) Messrs Jai Industries

were situated in Karnal area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Karnal in the State of Haryana;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of

1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2974, dated the 29th September, 1966;

And, whereas the Central Government is satisfied, that the insurable population of the Karnal area in the district of Karnal in the State of Haryana has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 4, the entry "Karnal" in column 3 and the entries corresponding thereto in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(5)/70-HI.]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1971

का० आ० 1888.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसस अमरीकन इंडस्ट्रीज, (2) मैसर्स जय इन्डस्ट्रीज, करनाल क्षेत्र में स्थित या जो हरियाणा राज्य के करनाल जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थित के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2974 तारीख 29 सितम्बर, 1966 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च के अधीन नियोजक के विशेष अधि-दाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हरियाणा राज्य के करनाल जिले में करनाल क्षेत्र को बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 4 के सामने, स्तम्भ 3 में "करनाल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायगा ।

[सं० फ० 603(5)/70—एच० आई०]

S.O. 1889.—Whereas the Central Government was satisfied that Karnal Co-operative Transport Society was situated in Karnal area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Karnal in the State of Haryana;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1367, dated the 6th May, 1963;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Karnal area in the district of Karnal in the State of Haryana has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 8, the entry "Karnal" in column 3 and the entry corresponding thereto in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(5)/70-HI.]

का० आ० 1889.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि करनाल कोआप-रेटिव टान्सपोर्ट सोसाइटी, करनाल क्षेत्र में स्थित थी जो हरियाणा राज्य के करनाल जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1367 तारीख 6 मई, 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हरियाणा राज्य के करनाल जिले में करनाल क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम, की अनुसूची में क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 3 में "करनाल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायगा।

[संख्या फा० 603(5)/70—एच० आई०]

S.O. 1890.—Whereas the Central Government was satisfied that

(1) Messrs Punjab Roadways

(2) Messrs National Tractors and Implements

were situated in Karnal area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Karnal in the State of Haryana;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 788, dated the 8th March, 1966;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Karnal area in the district of Karnal in the State of Haryana has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 5, the entry "Karnal" in column 3 and the entries corresponding thereto in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(5)/70-HI.]

का० प्रा० 1890—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसर्स पंजाब रोडवेज, (2) मैसर्स नेशनल ट्रकटर्स एण्ड एम्प्लीमेंट्स, करनाल क्षेत्र में स्थित था जो हरियाणा राज्य के करनाल जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थित वे आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वसन मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 798 तारीख 8 मार्च, 1966 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73घ के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम, के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हरियाणा राज्य के करनाल जिले में करनाल क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 के सामने, स्तम्भ 3 में "करनाल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायगा ।

[सं० फ० 603(5)/70-एच० आई०।]

S.O. 1891.—Whereas the Central Government was satisfied that

- (1) Messrs Karnal Distillery,
- (2) Messrs Aggarwal Iron Foundry,
- (3) Messrs Adarsh Industrial Cooperation

were situated in Karnal area which was sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Karnal in the State of Haryana;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 135, dated the 5th January, 1962;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Karnal area in the district of Karnal in the State of Haryana has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely—

In the Schedule to the said notification against Serial No. 10, the entry "Karnal" in column 3 and the entries corresponding thereto in column 4 shall be omitted.

[No. F. 603(5)/70-HI.]

का० प्रा० 1891—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसर्स करनाल डिस्टिलरी, (2) मैसर्स अग्रवाल आयरन फाउण्ड्री, (3) मैसर्स आदर्श इन्डस्ट्रियल कोऑपरेशन, करनाल क्षेत्र में स्थित था जो हरियाणा राज्य के करनाल जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने की, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 135 तारीख 5 जनवरी, 1962 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते।

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हरियाणा राज्य के करनाल जिले में करनाल क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची क्रम सं० 10 के सामने, स्तम्भ 3 में "करनाल" प्रविष्टि और स्तम्भ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

[संख्या का० 603(5)/70—एच० आई०]

S.O. 1892.—Whereas the Central Government was satisfied that Jai Bharat Auto Industries was situated in Chaura Bazar, Karnal area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Karnal in the State of Haryana;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the Employers' special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 3444, dated the 18th September, 1964;

And whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Chaura Bazar, Karnal area in the district of Karnal in the State of Haryana has now exercised 500, and it is not longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 5 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. F. 603(5)/70-HL.]

का०आ० 1892.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि जय भारत आटो इंडस्ट्रीज, चौड़ा बाजार, करनाल क्षेत्र में स्थित था जो हरियाणा राज्य के करनाल जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में, अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के समाज सुरक्षा विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 3444 तारीख 18 सितम्बर, 1964 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि हरियाणा राज्य के करनाल जिले में चौड़ा बाजार, करनाल क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः, अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

[संख्या फा० 603(5)/70-एच० आई०]

S.O. 1893.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 367, dated the 22nd January, 1970 the Central Government having regard to the location of the Government Automobile Workshops at Madurai and Salem, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshops from the payment of the employers special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 5th January, 1972.

[No. F. 601(75)70-HL.]

फा० ग्रा० 1893.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या फा० ग्रा० 367, तारीख 22 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार मदुरा और सलेम स्थित सरकारी आटोमोबाइल कर्मशालाओं की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मशालाओं को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से 5 जनवरी, 1972 तक जिसमें बहू दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 601(75)/70-एच० आई०]

S.O. 1894.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 365, dated the 22nd January, 1970 the Central Government having regard to the location of the Public Works Department Workshop, Bhopal in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 9th January, 1972.

[No. F. 601(79)/70-HL.]

फा० ग्रा० 1894.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० फा० ग्रा० 365 तारीख 22 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार लोक निर्माण विभाग कर्मशाला, भोपाल की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से 9 जनवरी, 1972 तक जिसमें बहू दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 601(79)/70-एच० आई०]

S.O. 1895.—Whereas the Central Government is satisfied that the employees of the Small Industries Service Institutes, Industrial Estate, Okhla, New Delhi, belonging to the Central Government in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs, are otherwise in respect of benefits substantially similar to the benefits provided under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 298, dated the 16th January, 1970 the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts the above mentioned factory from all the provisions of the said Act for a further period of one year with effect from the 14th January, 1971 upto and inclusive of the 13th January, 1972.

[No. F. 601(84)/70-HI.]

का० आ० 1895.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय के लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन उपबन्धित प्रसुविधाओं के समरूप प्रसुविधाएं अन्यथा प्राप्त हैं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 298 तारीख 16 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, ऊपर वर्णित कारखाने को उक्त अधिनियम के सभी उपबन्धों से 14 जनवरी, 1971 से 13 जनवरी, 1972 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 601(84)/70 एच० आई०]

S.O. 1896.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 370, dated the 22nd January, 1970 the Central Government having regard to the location of the Sanitary Store Workshop of the New Delhi Municipal Committee, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshop from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 6th January, 1972.

[No. F. 601(80)/70-HI.]

का० आ० 1896.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 370 तारीख 22 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली नगर पालिका की स्वच्छता भण्डार की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 जनवरी, 1972 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है ।

[संख्या फा० 601(80)/70-एच० आई०]

S.O. 1897.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 362, dated the 22nd January, 1970, the Central Government, having regard to the seasonal nature of the

Industry carried on in the factories which are exclusively engaged in wool-pressing either with or without cotton pressing and ginning, hereby exempts the said factories from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification upto and inclusive of the 31st December, 1971.

[No. F. 601(73)/70-HI.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

का० आ० 1897.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 73क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 362 तारीख 22 जनवरी 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार उन कारखानों में जो रुई दबाई और ओटाई के साथ-साथ या उसके बिना उन दबाई में अनन्य रूप से लगे हुई हों चलाए जा रहे उद्योग की मौसमी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अधिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से 31 दिसम्बर 1971 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[संख्या का० 601(73)/70-एच० आ०]

दयजीत सिंह,

प्रार सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 1898.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 5, and section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3581, dated the 26th September, 1968, namely:—

In the said notification, under the heading "II. Representatives of Employers", for entries at serial No. 2 and 3, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

- "(2) Shri S. N. Banerji, Deputy Secretary, (Establishment Works) Department of Works, Housing and Urban Development, New Delhi.
- (3) Shri N. Gopalan, Deputy Director, Civil Engineering (General), Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi."

[No. WE. 7(8)/70-MW.]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1971

का० आ० 1898.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा नियोजन विभाग)

की अधिसूचना सं० का० आ० 3581 तारीख 26 मिनम्बर, 1968 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

अक्त अधिसूचना में “2 नियाजनों के प्रतिनिधि” शीर्ष के नीचे क्रम संख्या 2 और 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रति स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“(2) श्री एस० न० बनर्जी,
उपसचिव (स्थापन कार्य) सचिव, आवास और नगर विकास विभाग,
नई दिल्ली ।

(3) श्री एन० गोपाल, उपातिदेशक, सिविल इंजीनियरी (साधारण)
रेल मंत्रालय रेल बोर्ड नई दिल्ली ।

[सं० डब्लू० ई० 7(8)/70-एम० डब्लू०]

हंमराज छाबड़ा, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1899.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952, (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri A. K. Jha as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. 8/85/69-MI.]

J. D. TEWARI, Under Secy.

(अस और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

का० आ० 1899.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए० के० झा को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 8/85/69-एम-1]

जे० डी० तिवारी, अवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 19th April 1971

S.O. 1900.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kotma Colliery of Associated Cement Company Limited, Post Office Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central

Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether keeping in view the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry, the scale of pay prescribed by the management of Kotma Colliery of Associated Cement Company Limited, Post Office Kotma, District Shahdol (Madhya Pradesh) for their monthly paid clerical staff need any revision? If so, to what relief are the workmen entitled and from what date?"

[No. 1/67/70-LR.II.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

(अम, और रोगाट विभाग)

आदेश

नं० दिल्ली 22 मार्च, 1971

क्र० जा०.1900—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोतमा, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) की कोतमा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या कोयला खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, डाकघर कोतमा, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) की कोतमा कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने मासिक वेतन पाने वाले लिपिकीय कर्मचारी वृन्द के लिए विहित वेतनमान का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ? यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?"

[संख्या 1/67/70-एल० आर० 2.]

कानैल सिंह, अवर सचिव ।

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 16th April 1971

S.O. 1901.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under it under Section 28 of the said Act, shall be exercisable also by the Deputy Secretary to the Government of Punjab, Rehabilitation Department-cum-Deputy Chief Settlement Commissioner, in respect of proceedings pertaining in acquired evacuee properties and lands, situate within the State of Punjab, subject to the condition that he shall not exercise any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him in any other capacity.

[No. 3(1)/LR/71.]

(पुनर्वास विभाग)

(कार्यालय मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 1971

एस० ओ० 1901.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा आदेश देती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत इसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित अर्जित निष्कांत सम्पत्तियों तथा भूमियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए पंजाब सरकार के पुनर्वास विभाग में नियुक्त उप सचिव तथा उप-मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा भी प्रयुक्त की जायेंगी। परन्तु यह है कि ऐसे मामले के सम्बन्ध में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनपर उन्होंने किसी रूप में कोई आदेश द दिया हो।

[संख्या 3(1)/एल० तथा आर०/71]

S.O. 1902.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Sub-Divisional Officer (Civil), Kangra of the Himachal Pradesh Government, as Settlement Officer for the purpose of performing in addition to his own duties as Sub-Divisional Officer (Civil), the functions assigned to a Settlement Officer by or under the said Act in respect of urban acquired evacuee properties and urban agricultural lands and (ii) rural acquired evacuee properties including agricultural lands and shop houses, cattlesheds and vacant sites in any rural area, forming part of the compensation pool.

[No. 3(2)/LR/67.]

एस० ओ० 1902.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा जिला के उपखण्ड अधिकारी (सिविल) को वे अपने उपखण्ड अधिकारी (सिविल) के पद के कार्यों के अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम द्वारा या उस के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी को सौंपे गए मुआवजा पूल के अन्तर्गत (1) शहरी अर्जित निष्कांत सम्पत्तियों तथा शहरी कृषि भूमियों और (ii) किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ग्रामीण अर्जित निष्कांत सम्पत्तियों के, जिनमें कृषि भूमि, दुकानें, मकान, पशुखाएँ तथा खाली स्थान शामिल हैं, कार्य को देखने के लिए बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या 3 (2)/एल० तथा आर०/67]

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1903.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (Revenue) of Government Himachal Pradesh, as Settlement Commissioner, for the purpose of performing in addition to his own duties as Deputy Secretary (Revenue), Government of Himachal Pradesh the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of acquired evacuee urban and rural properties and urban and rural agricultural lands forming part of the compensation pool, transferred to the State Government in 'package deal' or under administrative and financial arrangements.

[No. 3(16)/LR/69.]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 1971

एस० ओ० 1903.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके

द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के अवसर सचिव (राजस्व) को हिमाचल प्रदेश में अपने अवसर सचिव (राजस्व) के कार्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत 'पैकेज डील' या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अधीन राज्य सरकार को हस्तान्तरित मुआवजा पूल की अर्जित निष्क्रान्त शहरी तथा ग्रामीण सम्पत्तियों और शहरी तथा ग्रामीण कृषि भूमियों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 3(16)/एल० आर०/69]

S.O. 1904.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by Section 34(2) of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) he hereby delegates to the Deputy Secretary (Revenue) Himachal Pradesh Government exercising the powers of the Settlement Commissioner, his powers under Sections 23, 24 and 28 of the said Act for the purpose of passing necessary orders under these sections in respect of acquired urban and rural properties and urban and rural agricultural lands forming part of the compensation pool, transferred to the State Government in 'package deal' or under administrative and financial arrangements.

[No. 3(16)/LR/69.]

एस० प्रो० 1904.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34(2) द्वारा मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे इसके द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त को शक्तियों का प्रयोग करने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य के उपसचिव (राजस्व) को उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 तथा 28 के अन्तर्गत 'पैकेज डील' या प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को हस्तान्तरित मुआवजा पूल की अर्जित निष्क्रान्त शहरी तथा ग्रामीण सम्पत्तियों और शहरी तथा ग्रामीण कृषि भूमियों के सम्बन्ध में उक्त धाराओं के अधीन आवश्यक आदेश देने के लिए अपनी शक्ति का प्रदान करते हैं।

[संख्या 3(16) एल० आर० 69]

S.O. 1905.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (Revenue) of Government of Himachal Pradesh, as Settlement Commissioner, for purpose of performing, in addition to his own duties as Deputy Secretary (Revenue), Government of Himachal Pradesh, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of acquired evacuee urban and rural properties and urban and rural agricultural lands forming part of the compensation pool, transferred to the State Government in 'package deal' or under administrative and financial arrangements.

[No. 3(16)/LR/69.]

एस० प्रो० 1905.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के उपसचिव (राजस्व) को हिमाचल प्रदेश में अपने उपसचिव (राजस्व) के पद के कार्य भार के अतिरिक्त उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत 'पैकेज डील' या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अधीन राज्य सरकार को हस्तान्तरित मुआवजा पूल की अर्जित निष्क्रान्त शहरी तथा ग्रामीण सम्पत्तियों और शहरी तथा ग्रामीण कृषि भूमियों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों को करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 3(16) एल० आर० 69]

ORDER

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 1906.—In pursuance of rule 88 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955, I, W. G. Pathak, Chief Settlement Commissioner, Government of India hereby determine that members of the Scheduled Castes specified

in part X of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, shall alone be entitled to bid or to submit tender in respect of un-allotted rural evacuee Agricultural land situated within the Union Territory of Delhi with the exception of the following categories of the lands:—

- (i) lands retrieved by Delhi Administration for scrutiny/preparation of accounts of each land allottee.
- (ii) lands already sold but sale of which has been set aside by Competent authority.
- (iii) lands which have sub-urban potential, residential or commercial sites, or, in the garden colonies.
- (iv) small fragments of land not exceeding one acre surrounded by holdings of owners who are not members of Scheduled Castes

[No. 9(1)(2)/LR/71.]

W. G. PATHAK,

Chief Settlement Commissioner-cum-Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1971

एल० ओ० 1906—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम 1955 के नियम 88 का अनुसरण करते हुए मैं वा० ग० पाठक, भारत सरकार का मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा यह निश्चय करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के खण्ड — में उल्लिखित अनुसूचित जातियों के सदस्य ही केवल निम्नलिखित भूमियों के अलावा संघ क्षेत्र दिल्ली में स्थित पहली निष्क्रान्त ऋषि भूमि, जिसका बंटन पहले ही हुआ नहीं, बोली देने तथा टेंडर देने के अधिकारी होंगे।

- (1) वह भूमि जो दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि के प्रत्येक एलाटी की छानबीन/लेखे तैयार करने के लिए ले ली गई हो।
- (2) जो भूमि पहले ही बेची जा चुकी है परन्तु जिसकी बिक्री का समक्ष अधिकारी द्वारा अमान्य कर दिया गया है।
- (3) उद्यान बस्तियों में जिस भूमि पर अर्द्ध शहरी क्षमता आवासीय या निवास या वाणिज्यिक स्थल हो या 7 उपनिवेशों में हो।
- (4) भूमि के वे छोटे-छोटे टुकड़े जिनका क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न हो तथा जो ऐसे लोगों की सम्पत्तियों के मालिकों द्वारा घिरी हुई हो जो अनुसूचित जातियों के सदस्य नहीं हैं।

[संख्या 9(1)(2)/एल० एंड आर०/71]

वा० ग० पाठक,

मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, तथा
भारत सरकार के संयुक्त सचिव।

